



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 405] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 26, 2018/पौष 5, 1940
No. 405] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 26, 2018/PAUSHA 5, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2018

अंतिम जांच परिणाम

विषय: चीन जन. गण., यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'कोटिड पेपर' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी निर्णायक समीक्षा जांच

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 6/42/2017-डीजीएडी.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां इस के बाद अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आंकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे यहां इस के बाद नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए :-

- जबकि, इंडियन पेपर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ने मै० बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी मै० बीआईएलटी ग्राफिक पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (जिसे यहां इसके बाद "याचिकाकर्ता" अथवा "आवेदक" भी कहा गया है) की ओर से समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां इस के बाद अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आंकलन और संग्रहण और क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे यहां इसके बाद नियमावली भी कहा गया है) के अनुसरण में चीन जन. गण., यूरोपीय संघ और यूएसए (जिन्हें यहां इसके बाद संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'कोटिड पेपर' के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां इसके बाद प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की है।

2. और जबकि, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की विद्यमानता, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए, जो यदि लागू किया जाता तो घरेलू उद्योग को कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होता, याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर ए डी नियमावली के नियम 5 के अनुसरण में संबद्ध जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/42/2017- डीजीएडी, दिनांक 23 जनवरी, 2018 के अनुसार एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया।

ख. प्रक्रिया

3. प्राधिकारी द्वारा यहां नीचे वर्णित की गई प्रक्रिया का संबद्ध जांच के संबंध में अनुसरण किया गया है:-
- क) प्राधिकारी ने ऊपर नियम 5 के उपनियम (5) के अनुसरण में जांच शुरुआत करने की कार्यवाही से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।
- ख) प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 23 जनवरी, 2018 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया।
- ग) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग साथ ही आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराये गये पतों के अनुसार अन्य घरेलू उत्पादकों को जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में उनके विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।
- घ) प्राधिकारी ने ऊपर नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसरण में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति उपलब्ध कराई।
- ड.) भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए उनके देशों से निर्यातकों/उत्पादकों को परामर्श देने का भी अनुरोध किया गया। संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पतों सहित उन्हें उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गये पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी भेजी गई।
- च) प्राधिकारी ने एडी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसरण में संगत सूचना प्राप्त करने के लिए संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी:-

चीन जन गण

- (i) गोलड ईस्ट पेपर (जियांगसू) कंपनी लिमिटेड
- (ii) हायनान जिन्हाई पल्प एंड पेपर
- (iii) चेनमिंग ग्रुप

यूरोपीय संघ

- (iv) स्टोरा एनसो ओईज
- (v) यूपीएम सेल्स ओई
- (vi) साप्पी लिमिटेड
- (vii) कैम पेपर ग्रुप स्विटजरलैंड इंक

यू.एस.ए.

- (viii) न्यू पेज, मियामिसबर्ग, ओहियो, यूएसए
- छ) प्रत्युत्तर में, संबद्ध देशों से निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने निर्धारित प्रपत्र में निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किये:-
- (i) मै० गोलड हुआशेंग पेपर (सोजहाऊ) इंडस्ट्रियल पार्क कंपनी लिमिटेड (जीएचएस)
- (ii) मै० हायनान जिन्हाई पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (जेएचपीपी) और
- (iii) मै० गोलड ईस्ट ट्रेडिंग (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड (जीईएचके)
- (iv) मै० गोलड ईस्ट पेपर (जियांगसू) कंपनी लिमिटेड (जीई)

- (v) मै० यूपीएम जीएमबीएम, जर्मनी
- (vi) मै० यूपीएम पेपर ईना ओई, फिनलैंड
- (vii) मै० यूपीएम स्पेशिएल्टी पेपर्स ओई, फिनलैंड
- (viii) मै० यूपीएम सेल्स ओई, फिनलैंड
- (ix) मै० शानडांग केनमिंग पेपर होल्लिंडग्स लिमिटेड
- (x) मै० शानडांग केनमिंग पेपर सेल्स लिमिटेड
- (xi) मै० शाउंगुआंग माइलुन पेपर कंपनी लिमिटेड, चीन जन गण
- (xii) मै० केनमिंग (एचके) लिमिटेड, हांगकांग
- (xiii) मै० पीजी पेपर कंपनी लिमिटेड
- (xiv) मै० सप्पी अलफील्ड जीएमबीएच
- (xv) मै० सप्पी ऐनहिंगेन जीएमबीएच
- (xvi) मै० सप्पी ग्रेटकार्न जीएमबीएच
- (xvii) मै० सप्पी फिनलैंड ऑरिशन्स ओई (किरकनीमी)
- (xviii) मै० सप्पी लानाकेन एनवी
- (xix) मै० सप्पी मासट्रिच बीबी
- (xx) मै० सप्पी स्टॉकस्टड जीएमबीएच
- (xxi) मै० सप्पी यूरोप एसए

ज) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसरण में अनिवार्य सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातकों की प्रश्नावलियां भेजी:-

- (i) एलाइड स्पेशिएल्टी पेपर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
- (ii) भगवती एंटर प्राइजेज
- (iii) एक्सेल एंटर प्राइजेज
- (iv) केसी एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
- (v) नरसिंह दास एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
- (vi) पारस पेपर्स
- (vii) न्यूटेक प्रिंट सर्विसेज
- (viii) प्लस मार्केटिंग
- (ix) शाह देव जी शिव जी एंड कंपनी
- (x) सेठ ब्रदर्स
- (xi) श्री बालाजी उद्योग
- (xii) श्री चामुंडा एंटर प्राइजेज

(xiii) सिनकेम

(xiv) स्टैन्डर्ड पेपर एंड बोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(xv) यूनीक सेल्स कॉरपोरेशन

(xvi) टेनी जोज एंड एसोसिएट्स लिमिटेड

(xvii) व्हाइट एरो ग्रुप ऑफ कंपनीज

झ) उत्तर में निम्नलिखित आयातों/प्रयोक्ताओं ने जवाब दिया है और आयातकों की प्रश्नावली का उत्तर दायर किया:-

(i) मै० अवरी डेनिंसन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

(ii) मै० लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड

(iii) मै० मालायाला मनोरमा कंपनी लिमिटेड

(iv) मै० आउटलुक पब्लिशिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

ट) ऊपर उल्लिखित उत्तर देने वाले निर्यातकों और आयातकों के अतिरिक्त, जांच की अवधि के दौरान निम्नलिखित पक्षकारों की ओर से कुछ कानूनी अनुरोध प्राप्त हुए हैं:-

(i) यूरोपियन कमीशन

(ii) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स

(iii) कन्फेडरेशन ऑफ यूरोपियन पेपर इंडस्ट्रीज

ठ) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों/अनुरोधों के अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराये।

ड) पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के सौदावार विवरण उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) को अनुरोध किया गया, जिसे प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा की संगणना और सौदों की उचित जांच के पश्चात अपेक्षित विश्लेषण के लिए डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों का सहारा लिया है।

ढ) सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर उत्पादन की लागत और भारत में संबद्ध वस्तुओं को बनाने तथा उनकी बिक्री की लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) तैयार की गई है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से निम्न पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

ण) आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की स्थल पर जांच के जरिये प्राधिकारी द्वारा, अनिवार्य मानी गई सीमा तक, प्रत्यक्ष निरीक्षण किया गया। अंतिम जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ, जहां भी प्रयोज्य था, अनिवार्य संशोधन के साथ, केवल ऐसी सत्यापित सूचना का सहारा लिया गया है।

त) प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य समझे जाने वाली सीमा तक, उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का सत्यापन किया गया और अंतिम जांच परिणामों के निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ इसका आश्रय लिया गया है।

थ) वर्तमान पाटनरोधी जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि अप्रैल, 2016 से जून, 2017 (15 महीने) है। तथापि, क्षति जांच अवधि को 2013-14, 2014-15, 2015-16 की अवधि और पीओआई के रूप में विचारित किया गया है।

द) ए.डी. नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसरण में, प्राधिकारी ने 5 जून, 2018 को आयोजित सुनवाई में सभी हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया। सभी हितबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने मौखिक सुनवाई में भाग लिया उन्हें मौखिक रूप से अभिव्यक्त किये गये विचारों के लिखित निवेदनों को दायर करने की सलाह दी गई। पक्षकारों को विरोधी पक्षकारों द्वारा अभिव्यक्त विचारों की प्रतियों का संग्रहण करने की सलाह दी गई और उनके खंडन प्रस्तुत करने का परामर्श दिया गया।

- ध) इन जांच परिणामों में, जहां भी संगत पाया गया, इस जांच की अवधि के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का प्राधिकारी द्वारा उल्लेख किया गया है।
- न) गोपनीयता आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी जरूरत थी, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना पर गोपनीय के रूप में विचारित किया गया और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया। जहां भी संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना के पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
- प) जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने पहुंच से इंकार किया है अथवा अन्यथा रूप से वर्तमान जांच की अवधि के दौरान अनिवार्य सूचना उपलब्ध नहीं कराई है अथवा उल्लेखनीय रूप से जांच में बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी घोषित किया है और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अंतिम जांच परिणाम दर्ज किये हैं।
- फ) निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों से युक्त 28 नवंबर, 2018 को हितबद्ध पक्षकारों को एक प्रकटन विवरण जारी किया गया था जिसमें प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां, यदि कोई हैं, देने के लिए 10 दिसंबर, 2018 तक का समय दिया गया था। प्राधिकारी ने इस अंतिम जांच परिणाम में हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन पश्चात टिप्पणियों पर उपयुक्त रूप से विचार किया है।
- ब) इस अंतिम जांच परिणाम में *** गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सूचना दर्शाता है।
- (भ) संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 67.45 रुपये हैं।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच शुरुआत स्तर पर, विचाराधीन उत्पाद को नियमानुसार परिभाषित किया गया है:-

“काइलिन (चीनी क्ले) अथवा कैल्शियम कॉबॉनेट या पॉलीमर या अन्य अकार्बनिक पदार्थ के साथ लेपित, जिल्द के साथ अथवा उसके बिना सतह और किसी एक या दोनों ओर किसी अन्य लेप के साथ, रंगीन सतह, सजावट वाली अथवा मुद्रित सतह के साथ अथवा उसके बिना, किसी भी आकार की रोल अथवा आयताकार, (चौकोर सहित) शीटों में, चाहे वे मलिन, चमक, मेटी अथवा उच्च चमक (काॅस्ट लेपित) परिष्कृति वाले हों अथवा नहीं, से शुद्ध रसायन लुगदी से सामान्य रूप से निर्मित किंतु उनसे हमेशा अथवा विशेष रूप से निर्मित नहीं किये गये, अध्याय 4810 के तहत उचित रूप से वर्गीकरण योग्य पेपर अथवा पेपर बोर्ड”।

5. विचाराधीन उत्पाद को प्राथमिक रूप से पत्रिकाओं, कैटेलॉग्स, पुस्तकों और नियमावलियों, कैलेंडर्स, विवरणिका, लेबल्स, आदि के मुद्रण, लचीली पैकिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कोटिड कागज के लिए जीएसएम की सीमा 40 जीएसएम से 350 जीएसएम तक होती है। इस याचिका के सीमा क्षेत्र में विशेष रूप से शामिल न किया गया कागज पैकेजिंग प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाने वाला बहुपरतीय बोर्ड है, जो विचाराधीन उत्पाद का भाग नहीं है।

ग.1. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किये गये और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गये अनुरोध नियमानुसार हैं:-
- क) वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “ काइलिन (चीनी क्ले) अथवा कैल्शियम कॉबॉनेट या पॉलीमर या अन्य अकार्बनिक पदार्थ के साथ लेपित, जिल्द के साथ अथवा उसके बिना, और किसी एक या दोनों ओर किसी अन्य लेप के साथ अथवा उसके बिना, रंगीन सतह के साथ अथवा उसके बिना, सजावट वाली अथवा मुद्रित सतह के साथ अथवा उसके बिना, किसी भी आकार की रोल अथवा आयताकार, (चौकोर सहित) शीटों में, चाहे वे मलिन, चमक मेटी अथवा उच्च चमक (काॅस्ट लेपित) परिष्कृति वाले हों अथवा नहीं, से शुद्ध रसायन लुगदी से सामान्य रूप से निर्मित किंतु उनसे हमेशा अथवा विशेष रूप से निर्मित नहीं किये गये पेपर अथवा पेपर बोर्ड”।
- ख) लेपित पेपर और पेपर बोर्ड को मुख्य रूप से शुद्ध रसायन लुगदी से बनाया जाता है और यह आठ अंकीय स्तर पर एचएसएन के अध्याय 4810 अर्थात् 48101430, 48101320, 48101310, 48101490, 48101910, 48101920, 48101930, 48101990, 48102200, 48102900, 48103100, 48103200, 48103990, 48109200 और 48109900 के

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत आता है। घरेलू उद्योग के उत्पाद आयातित उत्पादों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं, जो जहां तक उनकी तकनीकी विशेषताओं, रासायनिक गठन और अन्य आधारभूत रूपरेखाओं का संबंध है, उनके समान ही है। इन शीर्षों के सभी उत्पाद मुद्रण उद्योग में समान प्रयोगों के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं।

- ग) पीयूसी को मुख्य रूप से पत्रिकाओं, कैटेलॉग्स, पुस्तकों और नियमावलियों, कैलेंडर्स, विवरणिकाओं, लेबल्स मुद्रण के लिए लचीली पैकिंग आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। कोटिड कागज के लिए ग्रेमेज 40 जीएसएम से 350 जीएसएम के भीतर है और पैकेजिंग के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने वाले बहुपरतीय बोर्ड को विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है, जो विचाराधीन उत्पाद का भाग नहीं है।
- घ) अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि चार अंकीय स्तर पर संपूर्ण अध्याय 4810 को आयात आंकड़ों में शामिल किया गया है, जिसने चार अंकीय स्तर पर पीयूसी को अनिश्चित बनाया है। इस संबंध में यह अनुरोध किया जाता है कि याचिका में स्पष्ट रूप से कोडों को सूचीबद्ध किया गया है, जो विचाराधीन उत्पाद से संबंधित है।
- ड.) वर्तमान मामले के विभिन्न तर्कों और पहलुओं पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग में उत्पाद के क्षेत्र को संशोधित किया है और उसके विवरण लिखित निवेदन में उपलब्ध कराये गये हैं। संशोधित विचाराधीन उत्पाद के आधार पर, आयात कार्यप्रणाली को भी पहले दायर किये गये लिखित अनुरोधों के साथ संलग्न किया गया है और अब इसी का सहारा लिया जाना चाहिए।
- च) विचाराधीन उत्पाद विस्तृत नहीं है और इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा समावेशों और बहिष्करणों के विवरण स्पष्ट रूप से दर्शाये गये हैं।

ग.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

7. विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तुओं के संबंध में निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गये निवेदन निम्नानुसार हैं:-
 - क) घरेलू उद्योग ने कुछ बहिष्करणों के साथ एचएस कोड 48.10 की शर्तों में पीयूसी को परिभाषित किया है। तथापि, इस बात की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद संपूर्ण एचएस कोड 48.10 के लिये आयात आंकड़े उपलब्ध कराये गये हैं कि आयात आंकड़ों में, परिभाषा द्वारा, अधिक उत्पाद शामिल किये गये हैं। उनकी तुलना में जिन्हें पीयूसी के विवरण में शामिल किया गया है।
 - ख) याचिकाकर्ता के स्वयं की स्वीकृति के अनुसार, चार अंकीय स्तर पर संबंधित उत्पाद में विभिन्न बहिष्करण किये गये हैं। वास्तव में, स्वयं 6 और 8 अंकीय स्तर पर भी ऐसे उत्पाद हैं जो विचाराधीन उत्पाद का भाग नहीं है।
 - ग) घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच शुरुआत करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी को सौदावार आयात आंकड़े भी उपलब्ध नहीं कराये। विशेष रूप से जबकि परिभाषित पीयूसी चार अंकीय स्तर पर एचएसएन कोड का केवल एक सबसेट है। माननीय प्राधिकारी कृपया यह नोट करें कि अन्य सभी जांचों के प्रतिकूल, डीजीसीआई एंड एस से सौदावार आंकड़ों की कोई अधिप्राप्ति नहीं की गई है, जो निश्चित रूप से एक स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आयात विवरण में बहिष्कृत उत्पादों को शामिल किया गया है और इसलिए, इन पर जांच शुरुआत करने के प्रयोजन हेतु भी भरोसा नहीं किया जा सकता।
 - घ) उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता ने उष्मारोधी इंसुलेटिंग पेपर, लचीलों पैकिंग पेपर आदि जैसे पेपरों की उन विविधताओं को शामिल किया है, जो जांच की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता उद्योग द्वारा उत्पादित और आपूर्ति नहीं किये गये हैं। स्थापित विधिशास्त्र तथा डीजीटीआर की समनुरूप कार्य प्रणाली के अनुसार भी, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित, न की गई वस्तुओं को इस साधारण कारण से भी शुल्कों के सीमा क्षेत्र से बहिष्कृत किये जाने की जरूरत है कि यह आयातकों के लिए अविवेकपूर्ण कठिनाइयां उत्पन्न करेगा।
 - ड.) समान पीयूसी के आयातों पर दिनांक 15 दिसंबर, 2004 को पिछले अंतिम जांच परिणामों में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उसमें पैरा 5 पर नोट किया था कि " संबंधित वस्तुओं में 80 जीएसएम से निम्न के कोटिड पेपर शामिल नहीं किये जाते"।
 - च) बीजीपीपीएल पिछली पाटनरोधी जांचों में भी घरेलू उद्योग था। तथापि, इसने कोटिड पेपर और 80 जीएसएम से कम के पेपर बोर्ड पर पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण के लिए अनुरोध नहीं किया था। यदि, बीजीपीपीएल 80 जीएसएम से कम कोटिड पेपर का विनिर्माण नहीं कर रहा है, तो इसे वर्तमान जांच में पीयूसी के कार्यक्षेत्र के भीतर शामिल नहीं किया जा सकता।

- छ) संबद्ध जांच में मौखिक सुनवाई के समय, घरेलू उद्योग सहमत था कि 80 जीएसएम से कम भार वाले कोटिड पेपर को विचाराधीन उत्पाद के सीमा क्षेत्र से निकाल देना चाहिए। इस संबंध में, हम निर्दिष्ट प्राधिकारी से घरेलू उद्योग के अनुरोध को रिकार्ड पर लेने और विचाराधीन उत्पाद के सीमा क्षेत्र से 80 जीएसएम से कम भार वाले कोटिड पेपर को बहिष्कृत करने का अनुरोध करते हैं।
- ज) ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग ने एचएस कोड 48102200 के तहत आने वाले उत्पादों को उत्पाद कार्य क्षेत्र के भीतर शामिल किया है। एचएस कोड 48102200 में "कम भार वाला कोटिड पेपर" शामिल है। तथापि, आयात वर्गीकरण में, घरेलू उद्योग ने विशेष रूप से नोट किया है कि हल्के भार का कोटिड पेपर गैर पीयूसी है और उत्पाद क्षेत्र से बाहर है।
- झ) इसी प्रकार, घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराये गये अद्यतन आयात आंकड़ों में, बड़ी संख्या में " बहुपरतीय वाले बोर्ड" के आयात सौदे दर्शाये गये हैं, जिन्हें पीयूसी के रूप में विचारित किया गया है। जैसा कि जांच शुरुआत के नोटिस में उपलब्ध कराया गया है, बहुपरतीय बोर्ड को विशेष रूप से जांचाधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। अतः प्रत्यर्थी ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराये गये अद्यतन आयात आंकड़ों को निकाल देने का प्राधिकारी से अनुरोध किया है।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

8. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद कार्य और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तु के कार्य क्षेत्र के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये निवेदनों को नोट किया है।
- (क) विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रकटन पश्चात टिप्पणियों सहित अनुरोधों और घरेलू उद्योग के रिकार्ड की जांच के आधार पर प्राधिकारी 75 जीएसएम से कम के दोनों ओर के कोटेड पेपर, हल्के कोटेड पेपर, इलैक्ट्रिकल क्राफ्ट इंशुलेशन पेपर, क्राफ्ट इंशुलेशन पेपर और इंशुलेटिंग पेपर को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग करते हैं।
- (ख) तदनुसार, "क्योलिन (चीनी मिट्टी) अथवा कैल्शियम कार्बोनेट अथवा पॉलीमर अथवा अन्य इनऑर्गेनिक तत्व से कोटेड पेपर अथवा पेपर बोर्ड", जो बाइंडर युक्त और बिना बाइंडर के हैं और जिस पर अन्य कोई कोटिंग नहीं है, एक ओर या दो ओर, सतह पर रंगयुक्त है अथवा नहीं, जिसकी सतह अलंकृत अथवा प्रिंटेड है, जो रोल में अथवा आयाताकार (वर्ग सहित) शीटों में है, किसी भी आकार का है, डल, ग्लास, मेट अथवा हाई ग्लॉस वाला है (कास्ट कोटेड) परिष्कृत है; सामान्यतः बनाया जाता है, परंतु अनिवार्य रूप से और विशिष्ट रूप से वर्जिन केमिकल पल्प से नहीं बनाया जाता है, वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद है। विचाराधीन उत्पाद में 40 जीएसएम से 350 जीएसएम के बीच आने वाले जीएसएम वाले कोटेड पेपर शामिल हैं। विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किए गए निम्नलिखित हैं :
- पैकिंग प्रयोजन के लिए मल्टीलेयर्ड बोर्ड
 - 75 जीएसएम से कम के दोनों ओर कोटेड पेपर
 - हल्के कोटेड पेपर
 - इलैक्ट्रिकल क्राफ्ट इंशुलेशन पेपर
 - क्राफ्ट पेपर
 - क्राफ्ट इंशुलेशन पेपर
 - इंशुलेटिंग पेपर
- ग) विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क उप-शीर्ष 4810 के अंतर्गत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 48 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और स्थिति

घ.1. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये निवेदन

9. घरेलू उद्योग के कार्य क्षेत्र के संबंध में जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध और उसकी स्थिति निम्नानुसार है:-
- क) घरेलू उद्योग, मै० बीआईएलटी ग्राफिक पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जो भारत में संबद्ध वस्तुओं का एक निर्माता है, की ओर से भारतीय कागज विनिर्माता संघ द्वारा दायर आवेदन दायर किया गया है। विचाराधीन उत्पाद के एक और ज्ञात घरेलू उत्पादक है अर्थात् जेके पेपर लिमिटेड।
- ख) आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और भारत में किसी आयातक अथवा संबद्ध देशों के निर्यातकों से संबंधित नहीं है और उसने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

- ग) अन्य हितबद्ध पक्षकारों के संबंध में कि देश में संबद्ध वस्तुओं के अन्य कथित उत्पादकों को शामिल न किये जाने के द्वारा घरेलू उद्योग को गलत रूप से परिभाषित किया है, जो अंततः क्षति संबंधी मापदंडों का विषम विश्लेषण करता है, घरेलू उद्योग दोहराता है कि यह दावा किसी विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित नहीं है। वास्तव में, हितबद्ध पक्षकार स्वयं बहस द्वारा आपस में परस्पर प्रतिकूल विवाद कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में उत्पादक विद्यमान हैं, किंतु वास्तव में केवल दो मुख्य उत्पादक हैं। किसी भी मामले में, हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रमाणित करने के लिए कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि याचिकाकर्ता का उत्पादन भारतीय उत्पादन में एक प्रमुख समनुपात स्थापित नहीं करता।
- घ) जेके पेपर्स द्वारा की गई आयात मात्रा में पूर्णतः महत्वपूर्ण है, जो निश्चित ही अपने स्वयं की उत्पादन मात्राओं से काफी तुलनीय है। नियमावली के अंतर्गत जेके पेपर्स को पात्र घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। यह होते हुए भी, जेके पेपर्स ने वर्तमान याचिका का विरोध नहीं किया है और अपने आयातों के बावजूद एडीडी के अधिरोपण के लिए अनुरोध किया है।

घ.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

10. घरेलू उद्योग के कार्य क्षेत्र और स्थिति के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध निम्नानुसार हैं:-
- क) वर्तमान मामले में आवेदकों ने कहा है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं के केवल दो उत्पादक हैं अर्थात् मै० बीआईएलटी ग्राफिक पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड और मै० जेके पेपर्स लिमिटेड, जो विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में संलग्न हैं। हालांकि, भारत में संबद्ध वस्तुओं के अन्य उत्पादक भी हैं। यह सूचना आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई है। इसलिए तथ्यात्मक रूप से गलत प्रतीत होती है।
- ख) यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि इस तथ्य के बावजूद कि जेके पेपर आईपीएमए (याचिकाकर्ता) का भाग है, इसे वर्तमान आवेदन में आवेदक नहीं बनाया गया है। यह विचारणीय है कि याचिका इस मुद्दे पर मौन है कि जेके पेपर घरेलू उद्योग का भाग क्यों नहीं है। पक्षपात के बिना, विनम्रतापूर्वक यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी को कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए जेके पेपर्स के निष्पादन और उत्पादन संबंधी मापदंडों पर विचार करना चाहिए कि जेके पेपर्स का बहिष्करण जानबूझकर घरेलू उद्योग के उत्पादन संबंधित आंकड़ों को विरूपित करने के लिए नहीं किया गया है।
- ग) एनसीवी याचिका के अनुसार, यह नोट किया जाना चाहिए कि भारत में कुल भाग का परिकलन करते समय, याचिकाकर्ता ने जेके पेपर द्वारा की गई बिक्री पर विचार नहीं किया है और सिर्फ आयातों और घरेलू उद्योग द्वारा की गई कैप्टिव खपत और बिक्री का योग करने के द्वारा संगणना कर दी गई है। यह निवेदन किया गया कि जेके पेपर के अतिरिक्त, भारत में अन्य उत्पादक भी हैं। अर्थात् वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड श्रीकृष्णा पेपर्स मिल्स लिमिटेड, सेंचुरी पेपर्स और अन्य प्राधिकारी से, एतद्वारा घरेलू उद्योग को संशोधित और पूर्ण सूचना उपलब्ध कराने के लिए कहने का अनुरोध किया जाता है।
- घ) आईपीएमए को स्पष्ट करना चाहिए कि (i) क्या बीजीपीपीएल और जेके पेपर के अतिरिक्त इसका कोई सदस्य कोटिड पेपर का उत्पादन कर रहा है और (ii) क्या याचिका में उत्पादन से संबंधित सूचना भारत में कोटिड पेपर के कुल उत्पादन की है अथवा यह आईपीएमए को उपलब्ध सूचना पर आधारित है।
- ड.) यदि कुल उत्पादन की संगणना करते समय भारत में सभी उत्पादकों को शामिल नहीं किया गया है तब निर्णायक रूप से यह निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या याचिकाकर्ता स्थिति के प्रयोजनार्थ कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख समानुपात स्थापित करता है, जैसा कि एडी नियमावली के नियम 2 (ख) के अंतर्गत यथा अपेक्षित है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को जांच में आगे और कोई कार्यवाही किये जाने से पहले भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों और उनके संबंधित उत्पादन के संबंध में घरेलू उद्योग से विशिष्ट सूचना प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध करना चाहिए।
- च) कोटिडरहित पेपर पर पाटनरोधी जांच में जेके पेपर घरेलू उद्योग के संघटकों में से एक है। हालांकि, यह वर्तमान पाटनरोधी जांच में घरेलू उद्योग का भाग नहीं है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि जेके पेपर ने उत्पाद का आयात किया है और इसलिए इसे घरेलू उद्योग के सीमा क्षेत्र से बहिष्कृत किया गया है।
- छ) प्रतिवादी ने निवेदन किया है कि ऐसे घरेलू उत्पादक का कोई स्वतः बहिष्करण नहीं हुआ है, जो संबद्ध उत्पाद का एक आयातक भी है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के बहिष्करण के संबंध में विवेकाधिकार प्राप्त है। हमने प्राधिकारी से घरेलू उद्योग के क्षेत्र से जेके पेपर के बहिष्करण के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे की जांच करने का अनुरोध किया है। प्रतिवादी ने निवेदन किया है कि जेके पेपर की उत्पादन से संबंधित सूचना का उचित रूप से आंकलन करने के लिए और महत्वपूर्ण क्षति के अधिक प्रतिनिधि निर्धारण पर पहुंचने के लिए घरेलू उद्योग के संघटकों के रूप में जेके पेपर को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- ज) घरेलू उद्योग ने केवल यह कहते हुए अन्य कोटिड पेपर उत्पादकों की विद्यमानता के बारे में हितबद्ध पक्षकारों के दावे की उपेक्षा की है कि दावे को प्रमाणित करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

11. समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ‘घरेलू उद्योग’पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

12. याचिका को घरेलू उद्योग मै० बीआईएलटी ग्राफिक पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की ओर से भारतीय पेपर विनिर्माता संघ द्वारा दायर किया गया था, जो भारत में संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है। याचिका में यह कहा गया था कि विचाराधीन उत्पाद के एक और ज्ञात घरेलू उत्पादक है अर्थात् जेके पेपर लिमिटेड।
13. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने मुद्दा उठाया है कि मै० बीआईएलटी ग्राफिक पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड और मै० जेके पेपर लिमिटेड के अलावा भारत में विचाराधीन उत्पाद के अन्य घरेलू उत्पादक भी हैं।
14. प्राधिकारी ने भारत में कुल उत्पादन और घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन किया और अन्य ज्ञात घरेलू उत्पादकों से अनुरोध किया, जैसा कि विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माण के संबंध में अपने निवेदनों में इंगित किया गया है। मै० सेंचुरी पल्प एंड पेपर, मै० स्टार पेपर, मिल्स लिमिटेड, मै० पदमजी पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, मै० वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड और मै० श्रीकृष्णा पेपर मिल्स और इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहा है कि वे संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माता नहीं हैं। तथापि, एक घरेलू उत्पादक अर्थात् मै० शेषासायी पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड ने स्वीकार किया है कि वे पीओआई के दौरान *** मिलियन टन की क्षमता के साथ संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादक हैं। इसलिए, प्राधिकारी ने नोट किया है कि प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के कुल उत्पादनमें ***% हिस्सा धारित करता है।
15. प्राधिकारी ने नोट किया है कि याचिकाकर्ता कंपनी ने, न तो संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है न ही यह संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित है। इसलिए, प्राधिकारी मानते हैं कि याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के प्रमुख समानुपात पर नियंत्रण रखता है। अतः इस जांच के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता ने स्थायी अनिवार्यता को संतुष्ट किया है और एडी नियमावली के नियम 2 (ख) और नियम 5 (3) की शर्तों में घरेलू उद्योग स्थापित होता है।

ड. गोपनीयता से संबंधित मुद्दे**ड. 1. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

16. गोपनीयता मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:-

- क) प्रतिवादी निर्यातकों/उत्पादकों ने अपने प्रश्नावली उत्तरों के सार्वजनिक पाठ में अर्थपूर्ण जानकारी उपलब्ध न कराकर अत्याधिक गोपनीयता का दावा किया है, जैसे शेयर धारकों का नाम, संबंधित पक्षकार का ब्यौरा, सवितरण की भारतीय सारणी आदि। प्रतिवादी ने अपने गोपनीयता दावे को स्थापित और उसका औचित्य सिद्ध नहीं किया है। यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी की राय है कि गोपनीयता के अनुरोध की जरूरत नहीं है अथवा सूचना का आपूर्तिकर्ता था तो सूचना को सामान्य रूप से सार्वजनिक करने में अथवा सामान्यकृत प्रपत्र में अपने प्रकटीकरण को प्राधिकृत करने में इच्छुक नहीं हैं तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की अवहेलना कर सकता है।
- ख) प्रतिवादी निर्यातक और उत्पादकों ने अपने उत्तरों में अपनी “संबंधित पक्षकार” सूचना में गोपनीयता का दावा किया है। सार्वजनिक खोज प्रकट करती है कि शाउगांग मेलन पेपर कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त वस्तु के एक और उत्पादक है, जो शानडांग केनमिंग पेपर होल्डिंग लिमिटेड से संबंधित है। अर्थात् जियांगझी केनमिंग पेपर कंपनी लिमिटेड इसके अतिरिक्त, शानडांग केनमिंग पेपर सेल्स कंपनी लिमिटेड और केनमिंग (एचके) लिमिटेड के अलावा, एक अन्य संबंधित कंपनी है, जो संबद्ध वस्तु के व्यापार में संलग्न है। अर्थात् किंगडाउ केनमिंग इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स कंपनी लिमिटेड। यह स्वीकार किया गया है कि इन दोनों कंपनियों ने वर्तमान जांच में उत्तर दायर नहीं किया है। सहायक कंपनियों की विशिष्ट संख्या और उनके नाम पर कोई स्पष्टता नहीं है। संबंधित पक्षकारों के संबंध में दावों की सत्यता का सत्यापन किये जाने की जरूरत है। ईक्यूआर की पांच सहायक कंपनियों में से तीन सहायक प्रतिवादी कंपनियां हैं। अर्थात् शाउगांग मेलन पेपर कंपनी लिमिटेड, केनमिंग एचके लिमिटेड और शानडांग केनमिंग पेपर सेल्स कंपनी लिमिटेड जो कोटिड पेपर के उत्पादन अथवा बिक्री के व्यापार में संलग्न हैं।

- ग) घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि घरेलू उद्योग के संबंध में वास्तविक सूचना का प्रकटन उत्पाद में आगामी व्यापार को जोखिम में डाल सकता है। जहां तक एक मात्र याचिकाकर्ता होने के कारण मात्रा संबंधी सूचना का संबंध है, याचिकाकर्ता को सूचना को न्याय संगत रूप से गोपनीय माना गया है। उक्त सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है और इसलिए वे इसे प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं हैं।
- घ) तथापि, यह नोट करना आश्चर्यजनक है कि निर्यातकों ने निर्यातों, बिक्रियों, उत्पादन आदि के बारे में सूचना सहित इसके आंकड़े पर पूर्ण गोपनीयता दावा किया है, किंतु घरेलू उद्योग से समान सूचना की मांग कर रहे हैं। गोपनीयता का दावा करने का मानदंड घरेलू उत्पादकों और निर्यातकों के अलग-अलग नहीं होना चाहिए। यहां तक कि आयातक प्रश्नावली उत्तर में भी पूर्ण रूप से कोई सूचना प्रकट नहीं की गई है।

ड. 2. अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये निवेदन

17. गोपनीयता मुद्दे के संबंध में अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित निवेदन किये गये हैं:-
- क) घरेलू उद्योग ने याचिका का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया है, जिसमें पांच देशों से संबंधित आंकड़े और सूचना शामिल की गई है जबकि वर्तमान जांच उन पांच देशों में से केवल तीन तक प्रतिबंधित है। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई याचिका में अंतर्निहित आंकड़े पांच देशों के संबंध में हैं और संचयी विश्लेषण भी पांच देशों की तुलना में किया गया है। स्पष्ट रूप से, घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई याचिका का अगोपनीय पाठ जांच शुरूआत अधिसूचना में अंतर्निहित सूचना/आंकड़ों से संबंधित नहीं है और जो संभवतः वर्तमान जांच को आरंभ करने के लिए माननीय प्राधिकारी के आधार का निर्माण करता है।
- ख) एक उचित अगोपनीय पाठ की अनुपस्थिति में, प्रतिवादी हितवद्ध पक्षकारों के अधिकार अत्यधिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है।
- ग) इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत अगोपनीय पाठ भी जांच से संबंधित मूलभूत सूचना पर गोपनीयता के विवेकाधीन दावे के कारण भी अनुचित है। आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा नियम 6 (3) की शर्तों में आवेदन का उचित अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराना अनिवार्य था और नियम 7 की शर्तों में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता के दावों को स्वीकृति अथवा अस्वीकृति प्रदान की जानी थी।
- घ) घरेलू उद्योग ने याचिका में गोपनीयता के रूप में विभिन्न प्रमुख आर्थिक मापदंड प्रस्तुत किये हैं। ऐसी सूचना के बिना, प्रत्यर्थी आवेदक उद्योग के क्षति मानदंडों की अर्थपूर्ण जांच को पूरी तरह से अपनाने में सक्षम नहीं है। अत्यधिक गोपनीयता के इस दावे ने प्रत्यर्थी की उन के हितों को सुरक्षित करने की क्षमता को उल्लेखनीय रूप से क्षीण किया है। यह स्वीकार किया जाता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचना की गोपनीयता के दावों का अवश्य मूल्यांकन करना चाहिए और न कि उचित जांच के बिना सूचना को गोपनीय के रूप में निर्दिष्ट नहीं करना चाहिए।
- ड.) गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार की यह राय हो सकती है कि ऐसी सूचना सारांशीकरण के लिए संवेदनशील नहीं है और ऐसी सूचना का अगोपनीय पाठ उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। तथापि, ऐसी स्थिति में एडी नियमावली के नियम 7 (2) के अंतर्गत सूचना के प्रदाता पक्षकार द्वारा एक विवरण में यह कारण बताना अनिवार्य है कि इस का सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। सिर्फ एक मात्र कथन कि "सूचना का सारांशीकरण संभव नहीं है"। कारणों के विवरण को तैयार करने की कानूनी अनिवार्यता को पूरा नहीं कर सकता कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
- च) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता के दावे का मूल्यांकन किया जाना और यह निर्धारित करना की अनिवार्य है कि क्या प्रश्नाधीन सूचना को गोपनीय रखा जा सकता है अथवा नहीं। वर्तमान मामले में गोपनीयता का दावा उस सूचना के संपूर्ण मूल्यांकन के बिना स्वतः ही प्रदान किया गया है जिस से गोपनीयता का दावा संबंध रखता है।
- छ) याचिकाकर्ता ने (i) क्षमता (ii) बिक्री (iii) क्षमता उपयोग (iv) निर्यात बिक्री (v) बाजार हिस्सा (vi) कर्मचारी और (vii) मांग के वास्तविक आंकड़ों में गोपनीयता का दावा किया है। इन मापदंडों के लिए वास्तविक आंकड़ों को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी सभी अंतिम जांच परिणामों में प्रकट किया गया है। निवल बिक्री वसूलियों के संबंध में घरेलू उद्योग ने सूचीबद्ध संख्याओं का प्रकटन भी नहीं किया है। इन आंकड़ों को सभी पाटनरोधी जांचों में प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अंतिम जांच परिणामों में प्रकट किया गया है। उदाहरण के लिए, रूस, कजाकिस्तान, टर्की और दक्षिण अफ्रीका से सोडियम डिट्रमेट पर हाल ही में समाप्त पाटनरोधी जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम जांच परिणामों में क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री, मांग और बाजार हिस्से के वास्तविक आंकड़ों को प्रकट किया है। वास्तव में, वास्तविक आंकड़े प्रकट किए गए थे, हालांकि इस पाटनरोधी जांच में भी घरेलू उद्योग में एकल उत्पादक शामिल है।
- ज) वास्तव में, कोटिड पेपर से संबंधित पाटनरोधी जांच में कुल मांग, क्षमता, क्षमता उपयोग, कर्मचारियों की कुल संख्या से संबंधित वास्तविक आंकड़े और घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत (निवल बिक्री वसूली) की सूचीबद्ध रूप में उपलब्ध कराई गई थी:-

विवरण	यूनिट	2000	2001	2002
मांग	मी०टन	83,194	90,597	110,721
बीआईएलटी का बाजार हिस्सा (घरेलू उद्योग)	%	76.57	75.97	62.95

स्रोत:- अंतिम जांच परिणाम सं. 14/7/2003 दिनांक 15 दिसम्बर, 2004 पैरा 28 और 40

- i) अतः वर्तमान पाटनरोधी जांच में इन आंकड़ों पर गोपनीयता का दावा करने का कोई आधार नहीं है।

ड.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

18. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

" गोपनीय सूचना" (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

19. प्राधिकारी निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय पाठ को अन्तर्निहित करने वाली सार्वजनिक फाइल के जरिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराएंगे।
20. संगत समझी गई सीमा तक गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदनों की प्राधिकारी द्वारा जांच की जाएगी और तदनुसार उनका उल्लेख किया जाएगा। गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है, जहां भी जरूरत थी और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया। जहां भी संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना के पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यापार संबंधित संवेदनशील सूचना का गोपनीय के रूप में दावा किया है।

च. विविध अनुरोध

च. 1. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध:-

21. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किये गये हैं:-

- क) प्रश्नावली में कुछ प्रश्न उन आर्थिक सहायताओं के संबंध में सूचना मांगते हैं, जो निर्यातक देश की सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है।
- ख) यह देखा गया कि प्रत्यर्थी निर्यातकों ने उनकी सरकार की ओर से किसी आर्थिक सहायता की अनुपस्थिति का दावा किया है। याचिकाकर्ता की जानकारी के अनुसार, चीन सरकार द्वारा ऐसे बहुत से कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जिनमें निर्यातकों को लाभ प्रदान किये जा रहे हैं। भारतीय प्राधिकारी ने यह भी धारित किया कि सभी योजनाएं प्रचालन में हैं और विस्तृत जांच के पश्चात उन आर्थिक सहायताओं का सामना किया गया। परिस्थितियों के अन्तर्गत, निर्यातकों का कथन कि चीन सरकार की कोई आर्थिक सहायता योजना प्रचालन में नहीं है, अत्यधिक भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत है। निर्यातकों से प्रचालनरत आर्थिक सहायता योजनाओं के बारे में रिपोर्ट करने की आशा की जाती है कि क्या उन्होंने उससे कोई लाभ प्राप्त किया है अथवा नहीं। हमने

प्राधिकारी से भ्रामक, अपूर्ण अथवा अन्यथा रूप से विसंगत प्रश्नावली उत्तर की गंभीरता पर विचार करते हुए प्रश्नावली उत्तर को खारिज करने का अनुरोध किया है।

- ग) आयात मात्राओं के दावों के अविश्वसनीय होने के संबंध में, क्योंकि उनमें दो गैर-संबद्ध देशों कोरिया और इंडोनेशिया से आयात शामिल है, घरेलू उद्योग का कहना है कि आवेदन का गोपनीय पाठ यह विचार करते हुए दायर किया गया कि क्षति पांच देशों के कारण है और इसलिए याचिका में पांच प्रस्तावित संबद्ध देशों की आयात मात्रा शामिल है। जांच अधिकारी ने संबद्ध देशों के वर्तमान सेट के विरुद्ध जांच आरंभ करने और उसे आगे बढ़ाना उचित समझा। जरूरत इस बात की है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा याचिका की एक प्रति प्राप्त की जानी चाहिए, जिस पर निर्दिष्ट प्राधिकारी भरोसा करते हैं। अर्थात् जांच आरंभ के लिए प्राधिकारी द्वारा विचार की गई सूचना जिसे घरेलू उद्योग द्वारा जांच आरंभ किये जाने पर उपलब्ध कराया गया था। इसके अतिरिक्त, जांच आरंभ किये जाने के पश्चात दायर अनुबंध और याचिका में भी प्रत्येक संबद्ध देश के लिए पृथक मात्रा दी गई है और हितबद्ध पक्षकार संबद्ध आयातों की मात्रा के हिस्से का विश्लेषण कर सकता है। तथापि, जैसा कि सुनवाई के समय कहा गया था, घरेलू उद्योग ने पहले ही सुनवाई पश्चात लिखित निवेदनों सहित संशोधित सूचना दायर कर दी है

च.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

22. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:-

- क) घरेलू उद्योग ने कहा है कि आईपीएमए पेपर उत्पादकों को उत्पादन संबंधी आंकड़े अनुरक्षित करता है, किंतु घरेलू उद्योग ने अन्य उत्पादकों के बिक्री संबंधी आंकड़ों के स्रोत को प्रकट नहीं किया है।
- ख) याचिका में नकदी प्रवाह, उत्पादकता, मजदूरी, ब्याज और कर पूर्व लाभ (पीबीआईटी) मूल्य ह्रास लागत और ब्याज लागत के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है। उत्पादकता, नकदी प्रवाह, मजदूरी पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा(iv) में विनिर्दिष्ट अनिवार्य क्षति संबंधी मापदंड हैं।

च. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

23. विविध मुद्दों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए मुद्दों का निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:-

जहां तक चीनी सरकार द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायताओं का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच एक पाटनरोधी जांच है और इसलिए प्राधिकारी चीनी सरकार द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायताओं की जांच नहीं कर रहे हैं।

छ. बाजार आर्थिक उपचार (एमईटी, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

24. धारा 9 क (1) (ग) के अंतर्गत, किसी अनुच्छेद के संबंध में सामान्य मूल्य से तात्पर्य है:-

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत।

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

छ. 1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

25. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

- क) यह निवेदन किया जाता है कि चीन जन.गण से प्रतिवादियों को बाजार अर्थव्यवस्था उपचार प्रदान नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि प्रतिवादी निर्यातक नीचे दी गई शर्तों में से प्रत्येक को संतुष्ट न करें:-
- i) बाजार अर्थव्यवस्था की पदवी ऐसी स्थिति में नहीं दी जा सकती यहां प्रमुख शेयर धारकों में एक राज्य स्वामित्व प्राप्त/नियंत्रित सत्ता है- यह सुनिश्चित किया जाने की जरूरत है कि क्या कोई शेयर धारक है जो एक राज्य स्वामित्व वाली इकाई है। निर्दिष्ट प्राधिकारी और ईसी ने लगातार धारित किया है कि ऐसे मामलों में राज्य के हस्तक्षेप की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। यह धारित किया जा रहा है कि यह केवल अकेले पिछले हस्तक्षेपों का प्रश्न नहीं है, किंतु पाटनरोधी शुल्कों के अधिरोपण के पश्चात भविष्य में संभावित राज्य हस्तक्षेप की संभावनाओं का भी है, जो बाजार अर्थव्यवस्था उपचार के लिए संगत है।
 - ii) बाजार अर्थव्यवस्था की पदवी नहीं दी जा सकती जब तक कि प्रत्यर्थी चीनी निर्यातक यह स्थापित न करें कि प्रमुख इनपुट की कीमतें महत्वपूर्ण रूप से बाजार मूल्यों को प्रतिबिंबित करती हैं – “महत्वपूर्ण रूप से बाजार मूल्य को प्रतिबिंबित करना” विस्तृत रूप से इस अर्थ को प्रतिपादित करता है कि इन इनपुट की कीमत को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अभिभावी कीमतों से तुलनीय होना चाहिए।
 - iii) बाजार अर्थव्यवस्था की पदवी नहीं दी जा सकती जब तक कि प्रत्यर्थी निर्यातक यह स्थापित न करें कि उन के बही खाते अंतराष्ट्रीय लेखाकरण मानकों के अनुसरण में हैं – बाजार अर्थव्यवस्था उपचार को ऐसी स्थितियों में अस्वीकृत किया जाना चाहिए जहां चीनी निर्यातक यह स्थापित करने में अक्षम रहें कि उनके बहीखाते अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण, मानकों लेखाकरण मानकों (आईएस) के अनुरूप हैं। अंतराष्ट्रीय के अनुसरण पर आग्रह करने की जरूरत वार्षिक रिपोर्ट में अभिव्यक्त राजस्व और व्ययों, परिसंपत्तियों और देनदारियों की सटीकता और पर्याप्तता को सुनिश्चित करने के लिए है।
 - iv) बाजार अर्थव्यवस्था की पदवी प्रदान नहीं की जा सकती जब तक कि उक्त मापदंडों में से एक को भी संतुष्ट नहीं किया जाता – बाजार अर्थव्यवस्था की पदवी प्रदान नहीं की जा सकती जब तक कि प्रत्यर्थी चीनी निर्यातक नियमावली के अंतर्गत निर्धारित किए गए प्रत्येक मापदंड के संबंध में परीक्षण को उत्तीर्ण नहीं कर लेते। यह स्थिति महत्वपूर्ण क्षति के लिए जरूरी परीक्षण के एकदम विपरीत है। यह एक भली-भांति स्वीकृत स्थिति है कि क्षति का एक सकारात्मक जांच परिणाम दर्ज नहीं किया जा सकता यदि केवल एक एकल मापदंड भी क्षति को स्थापित करता हो। इसलिये, जहां एकल मापदंड भी क्षति की विद्यमानता को स्थापित करने के लिए पर्याप्त है, वहीं एक एकल मापदंड को उत्तीर्ण करने में असफलता बाजार अर्थव्यवस्था की पदवी के दावे को अस्वीकृत करने के लिए पर्याप्त है।
 - v) भार/बाध्यता – प्राधिकारी के लिए यह स्थापित करना जरूरी नहीं है कि प्रत्यर्थी कंपनियां निश्चित रूप से बाजार अर्थव्यवस्था वातावरण के अंतर्गत प्रचालन कर रही हैं और बाजार अर्थव्यवस्था उपचार के लिए हकदार हैं। इस के विपरीत, प्रतिवादी निर्यातकों को यह स्थापित करना है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियों में प्रचालन कर रहे हैं।
 - vi) समग्र रूप में समूह से प्रत्युत्तर – बाजार अर्थव्यवस्था की पदवी प्रदान नहीं की जा सकती जब तक कि प्रतिवादी कंपनी और इस का समूह समग्र रूप से दावा न करे। यदि समूह का भाग बनने वाली एक या अधिक कंपनियों ने उत्तर दायर नहीं किया है तो बाजार अर्थव्यवस्था की पदवी को अस्वीकृत किया जाना चाहिए।
 - vii) रूपांतरण – ऐसी स्थिति में जहां वर्तमान शेयर धारकों ने स्वयं अपनी उत्पादन सुविधाओं को स्थापित नहीं किया है, किंतु इसे किसी अन्य पक्षकार से अधिग्रहित किया है, बाजार अर्थव्यवस्था की पदवी प्रदान नहीं की जा सकती जब तक कि रूपांतरण की प्रक्रिया के दस्तावेजी साक्ष्य के जरिए पूरी तरह से स्थापित न किया गया हो।
- ख) प्राधिकारी को चीन में प्रारंभिक संयंत्र की स्थापना के बाद से स्वामित्व में सभी परिवर्तनों, यदि कोई हो, जिसका प्रभाव हो सकता है, की जांच पड़ताल करनी चाहिए और उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए। विकास का इतिहास बाजार अर्थव्यवस्था उपचार प्रदान करने/इंकार करने के आधार का निर्माण करता है। निर्यातक द्वारा यह स्थापित करना अपेक्षित है कि इनपुट की कीमतें महत्वपूर्ण रूप से बाजार मूल्यों को प्रतिबिंबित करती हैं। इसके अतिरिक्त, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पहले धारित किया है कि “ बाजार मूल्यों को महत्वपूर्ण रूप से प्रतिबिंबित करना ” चीनी बाजार कीमत के संदर्भ में नहीं है। यह अंतराष्ट्रीय कीमतों के संदर्भ में है। निर्यातक ने यह स्थापित करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि इनपुट की कीमतों ने महत्वपूर्ण रूप से बाजार मूल्य को प्रतिबिंबित किया है। किसी अन्य संबंधित/असंबंधित कंपनी के आपूर्ति की जा रही और उस संबंधित/असंबंधित सत्ता द्वारा भारत को सामग्री के निर्यात की संभावना को वर्तमान उत्तर से निकाला नहीं जा सकता। निर्दिष्ट प्राधिकारी के ऐसे

विगत निर्धारण है जहाँ निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पृथक पाटन मार्जिन और शुल्कों के लिए इंकार किया था, जहाँ भी निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाया कि मूल्य श्रृंखला अपूर्ण थी।

- ग) यूरोपीय संघ और यूएसए की मामले में सामान्य मूल्य को संबंधित देशों में आयात कीमतों के आधार पर निर्धारित किया गया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि यूरोपीय संघ में विश्वव्यापी आयातों की कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य को निर्धारित करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। इसके विपरीत, जब निर्यातक देश के घरेलू बाजार में खपत कीमत के संबंध में सूचना उपलब्ध है, यह ऐसी सूचना है जिसे सह संबद्ध किए जाने की आवश्यकता है। ईयू और यूएसए में संबद्ध वस्तुओं के आयात महत्वपूर्ण हैं। इन देशों में आयात कीमत इन संबद्ध देशों के घरेलू बाजार में अभिभावी कीमत को दर्शाते हैं। अतः याचिकाकर्ता ने कानून के अनुसरण में जांच आरंभ करने के स्तर पर सामान्य मूल्य को निर्धारित किया है।
- घ) याचिकाकर्ता ने जांच के आरंभ होने के स्तर पर, भारत में संबद्ध आयातों की मात्रा और मूल्य को प्राप्त करने के लिए डीजीसीआई एंड एस का आश्रय लिया है। निर्यात कीमत को सीआईएफ स्तर पर परिचालित किया गया था। जबकि सामान्य मूल्य को कारखानागत स्तर पर परिचालित किया गया था। निर्यात कीमतों को समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा कमीशन, अंतर्देशीय माल भाड़ा, पत्तन व्ययों, बैंक प्रभारों और वैट समायोजन (चीन जन.गण के लिए) पर व्ययों के लिए समायोजित किया गया था। चूंकि याचिकाकर्ता ने सौदा-वार आयात आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, याचिकाकर्ता ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन की संशोधित संगणन उपलब्ध कराई है।

ख.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

26. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं:-

- क) सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण संबद्ध देशों से निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर आधारित होना चाहिए।
- ख) यह नोट किया जाना चाहिए कि वर्तमान मामले में, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस आधार पर इस जांच के कार्य क्षेत्र से कोरिया जन.गण और इंडोनेशिया को बाहर रखना उचित समझा कि आयात कीमतें पाटन की अनुपस्थिति की साक्षी हैं। यह स्वीकार किया जाता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह दृष्टिकोण चीन जन.गण, ईयू और यूएसए के विरुद्ध जांच आरंभ करने कारण भेदभावपूर्ण है, जबकि कोरिया जन.गण और इंडोनेशिया को इसमें शामिल नहीं किया गया है। यह स्वीकार किया जाता है कि यह बहिष्करण एडी नियमावली के नियम 14 (घ), नियम 5 (2) और नियम 5 (3) (ख) के संबंध में असंगत है।
- ग) यदि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क को लगाने के प्रयोजन से देशों के बीच पक्षपात किया है तो यह सर्वाधिक पसंसीदा राष्ट्र (एमएफएन) उपचार के उल्लंघन में होगा जैसा कि जीएटीटी 1947 के अनुच्छेद 1 के तहत प्रतिष्ठापित किया गया है।
- घ) आगे यह कहा जाता है कि कोरिया जन. गण और इंडोनेशिया से आयातों की मात्रा 3 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा से अधिक है। कोरिया जन.गण और इंडोनेशिया को जांच से बाहर रखना जबकि उनकी आयात मात्रा न्यूनतम सीमा से अधिक है, अन्यायपूर्ण है। यह बहिष्करण तब अधिक त्रुटिपूर्ण हो जाता है, जब इस बहिष्करण का औचित्य सिद्ध करने के लिए पाटन की संगणना हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध नहीं कराई गई है।
- ड.) भारतीय जांच प्राधिकारी ने बाजार अर्थव्यवस्था की पदवी के दावे के संबंध में चीन जन.गण से निर्यातकों से मात्रा संबंधी सूचना की मांग करते हुए चीन जन.गण से निर्यातकों को पृथक प्रश्नावली जारी की है। विगत में भारत द्वारा चीन जन.गण को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है। एतद्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि डब्ल्यूटीओ तक चीन की पहुंच पर प्रोटोकॉल के संगत प्रावधानों के अनुसरण में, दिनांक 11 दिसंबर, 2016 के बाद से पाटनरोधी कार्रवाईयों में “सरोगेट देश” वाले अभ्यास का बहुपक्षीय कानूनी आधारों में अभाव होना चाहिए। इस तरह के अभ्यास तब से समाप्त होने के लिए बाधित हैं। प्राधिकारी से इस मामले में सामान्य मूल्य की संगणना में “सरोगेट देश” कार्य प्रणाली का प्रयोग न करने का अनुरोध किया जाता है, इस बात की परवाह किए बिना कि क्या चीन को एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाता है अथवा नहीं।
- च) घरेलू उद्योग ने गलत रूप से सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ यूई और यूएसए में पीयूसी की आयात कीमत की प्रासंगिकता पर गलत रूप से बल दिया है। ईयू एक बाजार अर्थव्यवस्था क्षेत्र है। बाजार अर्थव्यवस्था देशों के मामले में सामान्य मूल्य सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क (ग) के अनुसरण में निर्धारित किया जाता है। धारा 9क (ग) में व्यवस्था की गई है कि सामान्य मूल्य निम्न पर आधारित होगा (i) ऐसे देश में समान वस्तु की घरेलू बिक्री अथवा जब ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है अथवा विश्वसनीय नहीं है (ii) ऐसी वस्तु की तुलनीय कीमत जब इसे ऐसे निर्यातक देश से किसी उचित तीसरे देश से निर्यात

किया जाता है अथवा (iii) प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत के लिए और लाभों के लिए उचित परिवर्द्धन के साथ मूल के देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत।

- छ) संबंधित बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश में पीयूसी की आयात कीमत के साथ इस तरीके से निर्धारित सामान्य मूल्य के साथ और अधिक सह संबंध स्थापित करने के लिए किसी कानूनी अनिवार्यता की जरूरत नहीं है।
- ज) प्रत्यर्थी ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है और सारी संगत सूचना उपलब्ध कराई है। घरेलू उद्योग ने गलत दावा किया है कि संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। घरेलू उद्योग नोट की गई प्रत्यर्थियों की संबंधित सत्तायें उत्पादन अथवा भारत को पीयूसी के निर्यातों में शामिल नहीं है। अतः संबंधित सत्ताओं द्वारा उत्तर दायर करने की कोई जरूरत नहीं है।
- झ) घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका में, ई.यू. से प्रति यूनिट सीआईएफ कीमत/निर्यात कीमत काफी अधिक थी। तथापि, घरेलू उद्योग के लिए सबसे अच्छे ज्ञात कारणों के लिए अद्यतन आंकड़ों में, ईयू से सीआईएफ कीमत/निर्यात कीमत को अत्यधिक रूप से घटाया गया है।

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	पीओआई (ए)	पीओआई
याचिका के अनुसार सीआईएफ कीमत	मी० टन	52,476	52,391	51,338	49,796	49,796
अद्यतन आंकड़ों के अनुसार सीआईएफ कीमत	रुपये/ मी० टन	44,714	42,571	42,205	41,286	41,286

- ट) किसी अन्य स्पष्टीकरण के बिना आयात कीमतों (सीआईएफ) में पर्याप्त विभिन्नता है। यह पहले से बताई गई मुख्य विशेषताओं, अशुद्धताओं, असंगतियों और घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आयात आंकड़ों की अविश्वसनीयता में परिवर्द्धित किया जाता है।
- ठ) किसी भी स्थिति में, सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण प्रश्नावली उत्तर में प्रतिवादियों द्वारा उपलब्ध कराई सूचना के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः बड़े हुये पाटन मार्जिन और निम्न निर्यात कीमत के संबंध में दावा महत्वहीन है।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

27. धारा 9क (1) (ग) के अंतर्गत, किसी अनुच्छेद के संबंध में सामान्य मूल्य से तात्पर्य है:-

- क) व्यापार की समान प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप-धारा (6) के तहत बनाये गये नियमों के अनुसार यथा निर्धारित निर्यातक देश अथवा भू-भाग में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- ख) जब निर्यातक देश या भू-भाग के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या भू-भाग की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-
- (i) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार निर्यातक देश या भू-भाग से या किसी उचित तीसरे देश से किया हो, अथवा
- (ii) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार यथा निर्धारित प्राशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत,
- ग) प्राधिकारी ने निर्धारित प्रपत्र और तरीकों में उन्हें सूचना उपलब्ध कराने की सलाह देते हुये, संबद्ध देशों से ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी। हालांकि, निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों के अतिरिक्त, संबद्ध देशों से अन्य उत्पादकों/निर्यातकों में से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्धारित प्रश्नावली उत्तर को दायर करने के द्वारा इस जांच में सहयोग नहीं किया:-

(i) मै० गोल्ड हुआशेंग पेपर (सोजहाऊ) इंडस्ट्रियल पार्क कंपनी लिमिटेड (जीएचएस)

(ii) मै० हायनान जिनहाइ पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (जेएचपीपी) और

(iii) मै० गोल्ड ईस्ट ट्रेडिंग (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड (जीईएचके)

- (iv) मै० गोल्लड ईस्ट पेपर (जियांगसु) कंपनी लिमिटेड (जीई)
- (v) मै० यूपीएम जीएमबीएम, जर्मनी
- (vi) मै० यूपीएम पेपर ईना ओई, फिनलैंड
- (vii) मै० यूपीएम स्पेशिएल्टी पेपर्स ओई, फिनलैंड
- (viii) मै० यूपीएम सेल्स ओई, फिनलैंड
- (ix) मै० शानडांग केनमिंग पेपर होल्लिंग्स लिमिटेड
- (x) मै० शानडांग केनमिंग पेपर सेल्स लिमिटेड
- (xi) मै० शाउंगुआंग माइलुन पेपर कंपनी लिमिटेड, चीन जन गण
- (xii) मै० केनमिंग (एचके) लिमिटेड, हांगकांग
- (xiii) मै० पीजी पेपर कंपनी लिमिटेड
- (xiv) मै० सप्पी अलफील्ड जीएमबीएच
- (xv) मै० सप्पी ऐनहिंगेन जीएमबीएच
- (xvi) मै० सप्पी ग्रेटकार्न जीएमबीएच
- (xvii) मै० सप्पी फिनलैंड ऑरिशनस ओई (किरकनीमी)
- (xviii) मै० सप्पी लानाकेन एनवी
- (xix) मै० सप्पी मासट्रिच बीवी
- (xx) मै० सप्पी स्टॉकस्टड जीएमबीएच
- (xxi) मै० सप्पी यूरोप एसए

28. चाइनीज एसेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और जीएटीटी, 1994 तथा पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां अभिभावी रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं।

ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सविस्डीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

29. जांच शुरुआत के स्तर पर, प्राधिकारी ने इस अनुभाग के साथ कार्यवाही आगे बढ़ाई कि चीन जन.गण में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग में महत्वपूर्ण विकृति अभिभावी है। जांच शुरुआत किए जाने पर, प्राधिकारी ने चीन जन.गण में उत्पादकों/निर्यातकों को जांच शुरुआत के नोटिस का उत्तर देने और घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माण, उत्पादन और विक्रियों के संबंध में भारत और अन्य देशों को निर्यातों में बाजार स्थितियों की व्यापकता का प्रदर्शन करने से संबंधित संगत सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दी। प्राधिकारी ने नियमों के अनुबंधन के पैरा 8(3) में निर्धारित किए गए मापदंड के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को संपूर्ण प्रश्नावली की प्रतियां भेजी। प्राधिकारी ने चीन जन. गण की सरकार से भी चीन जन. गण में उत्पादकों/निर्यातकों को संगत सूचना उपलब्ध कराने की सलाह देने के लिए भी कहा।
30. अनुच्छेद 15 का तात्पर्य है कि उप पैराग्राफ के प्रावधानों में से एक चीन की प्राप्ति की तारीख से 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। चूंकि घरेलू उद्योग को क्षति का कारण बनने वाले पाटन की बात जांच अवधि के आधार पर स्थापित की गई है, जांच की अवधि के दौरान अभिभावी स्थितियां वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ संगत, उचित और अनिवार्य हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि अप्रैल, 2016 से जून, 2017 है। चूंकि, अनुच्छेद 15 का उप पैराग्राफ जांच की अवधि के अधिकतर भाग के दौरान अस्तित्व में था। प्राधिकारी को ऐसी कार्य प्रणाली का प्रयोग करना होगा जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है। यदि जांचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि विनिर्माण, उत्पादन और उस उत्पाद की बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियां अभिभावी हैं।
31. प्राधिकारी ने नोट किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत और अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा पाटनरोधी जांच में चीन जन. गण को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में माना गया है। चीन जन. गण को नियमों की शर्तों में निर्यातक देश अथवा वैक्तिक निर्यातकों द्वारा अनुमानों के खंडन के अध्यधीन एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है।

बाजार अर्थव्यवस्था के दावों की जांच

32. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंधन के पैराग्राफ 8 के अनुसार, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का खंडन किया जा सकता है। यदि चीन जन. गण से निर्यातक पैराग्राफ 8 के उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंड के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराता (कराते) हैं और इस के विपरीत तथ्य स्थापित करते हैं। चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तु के सहयोगी निर्यातक/उत्पादकों द्वारा अनिवार्य सूचना/पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराना अपेक्षित है जैसा कि बाजार अर्थव्यवस्था उपचार प्रश्नावली के उत्तर में पैराग्राफ 8 के उप पैराग्राफ (3) में उल्लेख किया गया है ताकि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मानदंड पर विचार करने में सक्षम हो सके कि क्या:-

- i) कच्ची सामग्री सहित कीमत, लागत और इनपुट, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, आउटपुट, बिक्री और निवेश के संबंध में चीन जन. गण के निर्णय आपूर्ति और मांग को प्रतिबिंबित करने वाले बाजार संकेतकों की प्रतिक्रिया में और इस संबंध में महत्वपूर्ण राज्य के हस्तक्षेप के बिना लिए गए हैं और क्या प्रमुख इनपुट की लागतें उल्लेखनीय रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती हैं;
- ii) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतें और वित्तीय स्थिति भूतपूर्व गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली, विशेषतः परिसंपत्तियों के मूल्य ह्रास, अन्य बट्टे खाते डाली गई राशियों, वस्तु विनिमय व्यापार और ऋणों के मुआवजे के माध्यम से भुगतान के संबंध में लागू की गई महत्वपूर्ण विकृतियों के अधीन है;
- iii) ऐसी फर्मों दिवालियेपन और संपत्ति कानूनों के अधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन के लिए कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं; और

iv) विनिमय दर रूपांतरण बाजार दर पर लागू किए जाते हैं।

छ.4. चीन जन. गण में सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

छ.4.1. चीन जन. गण में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

33. यह नोट किया जाता है कि एक चीनी समूह, जिसमें गोल्ड ईस्ट पेपर (जियांगसू) कंपनी लिमिटेड, गोल्ड हुआशेंग पेपर (सुझोउ इंडस्ट्रीयल पार्क) कंपनी लिमिटेड, हायनान जिन्हाई पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड और गोल्ड ईस्ट ट्रेडिंग (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड शामिल हैं, ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा किया है। हालांकि, जांच की अवधि के दौरान उन्होंने अपना दावा वापिस ले लिया। किसी अन्य चीनी उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा नहीं किया है। इसलिए, प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है और यह पाटन मार्जिन संबंधी सारणी में पैरा 52 में दर्शाया गया है।

छ.4.2. चीन जन. गण के लिए निर्यात कीमत

क. मै० शाउडांग मेलन पेपर कंपनी लिमिटेड और मै० शानडांग केनमिंग पेपर होल्डिंग्स लिमिटेड (उत्पादक) सहित इसके व्यापारी ट्रेडर मै० केनमिंग (एचके) लिमिटेड (निर्यातक) हांगकांग के लिए निर्यात कीमत

34. उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर उत्तर से, प्राधिकारी ने नोट किया है कि मै० शाउगुआंग मेलन पेपर कंपनी लिमिटेड और मै० शानडांग केनमिंग पेपर होल्डिंग्स लिमिटेड चीन जन.गण से संबंधित है और संबंधित ट्रेडर अर्थात् मै० केनमिंग (एचके) लिमिटेड (निर्यातक), हांगकांग के माध्यम से पीओआई के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। उत्पादकों अंतर्देशीय माल भाड़ा, हैंडलिंग प्रभार, विदेशी माल भाड़ा, ऋण लागत, बैंक प्रभार आदि के कारण समायोजनों का दावा किया है और कारखानागत निर्यात कीमत के परिकलन के लिए प्राधिकारी द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई है। प्राधिकारी द्वारा यह भी नोट किया गया है कि ट्रेडर ने हानि पर संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है और इसलिए ट्रेडर द्वारा उपगत की गई हानि के लिए उचित समायोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने अप्रतिदेय वैट के कारण उचित समायोजन किया है। तदनुसार, प्रतिभागी उत्पादकों के लिए कारखानागत निर्यात कीमत *** अमेरिकी डॉलर प्रति मी० टन निर्धारित की गई है।

ख. गोल्ड ईस्ट ट्रेडिंग (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड ("जीईएचके") के लिए निर्यात कीमत

35. गोल्ड ईस्ट ट्रेडिंग हांगकांग कंपनी लिमिटेड ("जीईएचके") द्वारा दायर उत्तर से, प्राधिकारी ने नोट किया है कि जीईएचके के तीन संबंधित उत्पादकों द्वारा विनिर्मित वस्तुएं प्राप्त करते हैं। गोल्ड ईस्ट पेपर (जियांगसू) कंपनी लिमिटेड, गोल्ड हुआशेंग पेपर (सुझोउ इंडस्ट्रीयल पार्क) कंपनी लिमिटेड (जीएचएस) और हायनान जिन्हाई पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (जेएचपीपी) जीईएचके कच्ची सामग्री की आपूर्ति करते हैं (पल्प और कुछ रसायन) जो उपर्युक्त तीन उत्पादकों द्वारा टोल विनिर्माण के लिए, संसाधन व्यापार प्रक्रिया के अंतर्गत चीन को आयात की जाती है। इन उत्पादकों द्वारा विनिर्मित वस्तुएं जीईएचके द्वारा भारत और अन्य देशों को निर्यात की जाती हैं। जीईएचके इन कच्ची सामग्री उत्पादकों द्वारा विनिर्मित तैयार उत्पादों का स्वामित्व धारित करता है। तदनुसार, जीईएचके भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यातक हैं।

36. यह नोट किया जाता है कि जीईएचके ने समुद्र पारीय माल भाड़ा, निकासी और हैंडलिंग प्रभार, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय माल भाड़ा, कमीशन, बैंक प्रभार और ऋण लागत के कारण समायोजन का दावा किया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने अप्रतिदेय वैट के कारण उचित समायोजन किया है। तदनुसार, जीईएचके के लिए कारखानागत निर्यात कीमत *** अमेरिकी डॉलर प्रति मिलियन टन निर्धारित की है।

ग. चीन गणराज्य से असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य:-

37. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन गणराज्य से किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को कोई उत्तर नहीं दिया है। चीन गणराज्य में सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात मूल्य का निर्धारण किया है और इसे पाटन मार्जिन सारणी में पैरा 52 में दर्शाया है।

जी.5. यूरोपियन संघ में सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य कीमत और निर्यात मूल्य का निर्धारण:-

जी.5.1 यूरोपियन संघ में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य कीमत का निर्धारण:-

क. मै० यूपीएम कम्यूनिकेशन पेपर्स ओवाई (पूर्ववर्ती यूपीएम पेपर ईएनए ओवाई), (ख) यूपीएम स्पेसिटी पेपर्स ओवाई, (ग) मै० यूपीएम जीएमबीएच एंड एक्सपोर्टर्स/ट्रेडर्स मै० यूपीएम सेल्स ओवाई (यूपीएम ग्रुप) के लिए सामान्य मूल्य।

38. यूपीएम ग्रुप अर्थात् मै० यूपीएम कम्यूनिकेशन पेपर्स ओवाई, मै० यूपीएम स्पेशियलिटी पेपर्स ओवाई और मै० यूपीएम जीएमबीएच में उत्पादकों के द्वारा दायर किये गये प्रत्युत्तर से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सभी कंपनियों ने अपनी संबंधित कंपनी यूपीएम सेल्स ओवाई के माध्यम से पीओआई के दौरान घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्रियां की हैं। यह नोट किया है कि यूपीएम ग्रुप में सभी उत्पादक कंपनियां संपूर्ण उत्पादन को मै० यूपीएम सेल्स ओवाई को बेचती हैं और मै० यूपीएम सेल्स ओवाई भारत और दूसरे देशों को घरेलू बिक्रियां और निर्यात करती है। यह भी नोट किया गया कि घरेलू बिक्रियां ईयू में संबद्ध और असंबद्ध उपभोक्ताओं को भी की गई थी। तथापि, संबद्ध उपभोक्ताओं के लिए कीमतें असंबद्ध उपभोक्ताओं की अपेक्षा अधिक थीं।
39. सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत और एसजीए व्यय के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेन-देनों का निर्धारण करने के लिए सामान्य अवधि का व्यापार जांच परीक्षण किया। यदि लाभ कमाने वाले लेन-देन 80 प्रतिशत से अधिक होते हैं, तब प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए घरेलू बाजार में सभी लेन-देनों पर विचार किया है और यदि लाभ योग्य लेन-देन 80 प्रतिशत से कम होते हैं, तो सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए केवल लाभ योग्य घरेलू बिक्रियों को ही ध्यान में रखा जाता है।
40. इस मामले में, सामान्य अवधि के व्यापार जांच परीक्षण के आधार पर सभी घरेलू बिक्रियों को सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए ध्यान में रखा गया है, क्योंकि लाभ योग्य बिक्रियां 80 प्रतिशत से अधिक थीं। मै० यूपीएम सेल्स ओवाई स्वदेशी दुलाई, समुद्री माल-भाड़े, बीमा, रख-रखाव और अन्य व्यय, क्रेडिट व्यय, कमीशन और छूट/कटौती को समायोजित करने के लिए दावा किया है और प्राधिकारी के द्वारा इनकी अनुमति दे दी गई है। कारखानागत सामान्य मूल्य प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी ने मै० यूपीएम सेल्स ओवाई के द्वारा किये एसजीए व्यय की कटौती भी की है। तदनुसार, भागीदार उत्पादकों के लिए कारखानागत सामान्य मूल्य का निर्धारण यूपीएम ग्रुप के लिए प्रति टन *** अमेरिकी डॉलर के रूप में किया गया है।

ख. मै० सप्पी अल्फील्ड जीएमबीएच, मै० सप्पी एन्हिगन जीएमबीएच, मै० सप्पी ग्रेटकार्न जीएमबीएच, मै० सप्पी फिनलैंड ऑरिंशंस ओवाई (किरकनेमी), मै० सप्पी लानाकेन एनवी, मै० सप्पी मास्ट्रिच बीवी, मै० सप्पी स्टॉकस्टेड जीएमबीएच और मै० सप्पी यूरोप एसए ("सप्पी ग्रुप") के लिए सामान्य मूल्य:-

41. सप्पी ग्रुप में उपर्युक्त उत्पादकों के द्वारा प्रस्तुत किये प्रत्युत्तर से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सभी कंपनियों ने पीओआई के दौरान घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। प्राधिकारी ने एसएपीपीआई समूह के द्वारा की गई घरेलू बिक्रियों की जांच की है और यह नोट किया है कि जब भारत में विचाराधीन उत्पाद के निर्यातों की तुलना की गई, तब घरेलू बाजार में बिक्रियों को दर्शाया गया है।
42. अतः प्राधिकारी ने एसएपीपीआई ग्रुप की घरेलू बिक्रियों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने का निर्णय लिया है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने प्रत्येक कंपनी के लिए विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेन-देनों का निर्धारण करने के लिए सामान्य अवधि का व्यापार जांच परीक्षण किया। यदि लाभ कमाने वाले लेन-देन 80 प्रतिशत से अधिक होते हैं, तब प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए घरेलू बाजार में सभी लेन-देनों पर विचार किया है और यदि लाभ योग्य लेन-देन 80 प्रतिशत से कम होते हैं, तो सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए केवल लाभ योग्य घरेलू बिक्रियों को ही ध्यान में रखा जाता है।
43. एसएपीपीआई ग्रुप की कंपनियों ने कमीशन, दावे, स्वदेशी भाड़े, डिलीवरी प्रभारों और बीमा का समायोजन करने के लिए दावा किया है और प्राधिकारी ने इनको स्वीकार कर लिया है। तदनुसार, भागीदार उत्पादकों के लिए कारखानागत सामान्य मूल्य का निर्धारण प्रति टन *** अमेरिकी डॉलर के रूप में किया गया है।

ग. यूरोपीय संघ से असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य:-

44. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ईयू से किसी भी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। ईयू में सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिये प्राधिकारी ने उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर कारखानागत सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है और इसे दी गई पाटन मार्जिन सारणी में पैरा 52 में दर्शाया है।

जी.5.2. यूरोपीय संघ के लिए निर्यात मूल्य

- क. मै० यूपीएम कम्यूनिकेशन पेपर्स ओवाई (पूर्ववर्ती यूपीएम पेपर ईएनए ओवाई), (ख) यूपीएम स्पेसिटी पेपर्स ओवाई, (ग) मै० यूपीएम जीएमबीएच एंड एक्सपोर्ट्स/ट्रेडर्स मै० यूपीएम सेल्स ओवाई (यूपीएम ग्रुप) के लिए निर्यात मूल्य।

45. यूपीएम ग्रुप अर्थात् मै० यूपीएम कम्यूनिक्शन पेपर्स ओवाई, मै० यूपीएम स्पेक्षिटी पेपर्स ओवाई और मै० यूपीएम जीएमबीएच में उत्पादकों के द्वारा दायर किये गये प्रत्युत्तर से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सभी कंपनियों ने अपनी संबंधित कंपनी यूपीएम सेल्स ओवाई के माध्यम से पीओआई के दौरान विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। भारत के लिए सभी निर्यात असंबद्ध ग्राहकों के लिए किये गये हैं।
46. तदनुसार, प्राधिकारी ने असंबद्ध भारतीय ग्राहकों के लिए निर्यात मूल्य को ध्यान में रखते हुए तथा स्वदेशी ढुलाई, समुद्री माल भाड़े, बीमा, रख-रखाव एवं अन्य व्यय, क्रेडिट व्यय, बिक्री कमीशन और छूट/कटौती का समायोजन करके कारखानागत निर्यात मूल्य निकाला है। कारखानागत निर्यात मूल्य प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी ने मै० यूपीएम सेल्स ओवाई के द्वारा किये एसजीए व्यय की कटौती भी की है। तदनुसार, भागीदार उत्पादकों के लिए कारखानागत निर्यात मूल्य का निर्धारण यूपीएम ग्रुप के लिए प्रति टन *** अमेरिकी डॉलर के रूप में किया गया है।

ख. मै० सप्पी अल्फील्ड जीएमबीएच, मै० सप्पी एन्हिगन जीएमबीएच, मै० सप्पी ग्रेटकार्न जीएमबीएच, मै० सप्पी फिनलैंड ऑरिंशंस ओवाई (किरकनेमी), मै० सप्पी लानाकेन एनवी, मै० सप्पी मास्ट्रिच बीवी, मै० सप्पी स्टॉकस्टेड जीएमबीएच और मै० सप्पी यूरोप एसए ("सप्पी ग्रुप") और मै० पीजी पेपर कंपनी के लिए ("पीजीसीपीएल") के लिए निर्यात मूल्य:

47. भारत के लिए बिक्री करने में शामिल उत्पादकों और निर्यातकों के द्वारा प्रस्तुत किये गये उत्तर से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान एसएपीपीआई ग्रुप के उत्पादकों के द्वारा एक संबद्ध व्यापारी अर्थात् सप्पी यूरोप एसए और असंबद्ध व्यापारी पीजीसीपीएल के माध्यम से भारत के लिए बिक्रियां की गई थीं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दोनों व्यापारियों ने अपने-अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर दिए हैं तथा उनके संबंधित प्रत्युत्तरों की विधिवत जांच कर ली गई है। भारत के लिए समस्त निर्यात संबद्ध ग्राहकों के लिए किये गये हैं।
48. तदनुसार, प्राधिकारी ने असंबद्ध भारतीय ग्राहकों के लिए मूल्य को ध्यान में रखते हुए और शामिल व्यापारियों के एसजी एंड ए खर्चों के साथ-साथ कमीशन, दावे, लदान खर्च, बीमा और बैंक प्रभारों को समायोजित करके कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि पीजीसीपीएल ने हानि पर संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है, इसलिए पीजीसीपीएल की हानि के लिए उपयुक्त समायोजन किया गया है और कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण एसएपीपीआई ग्रुप के लिए प्रति टन *** अमेरिकी डॉलर के रूप में किया गया है।

ग. यूरोपीय संघ से असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य:-

49. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ईयू से किसी भी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। ईयू में सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिये प्राधिकारी ने उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण किया है और इसे दी गई पाटन मार्जिन सारणी में पैरा 52 में दर्शाया गया है।

जी.6 अमरीका में सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारण:-

जी.6.1. अमरीका में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण :-

50. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अमेरिका से किसी उत्पादक/निर्यातक ने प्रत्युत्तर नहीं दिया है और वर्तमान जांच में प्राधिकारी को सहयोग नहीं किया है। अमेरिका में सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिये प्राधिकारी ने उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर कारखानागत निर्यात मूल्य का निर्धारण किया है और इसे दी गई पाटन मार्जिन सारणी में पैरा 52 में दर्शाया है।

जी.6.2. अमेरिका में अन्य उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य का निर्धारण:-

51. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अमेरिका से किसी भी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। अमेरिका में सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिये प्राधिकारी ने उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर संबद्ध वस्तुओं के लिए निर्यात मूल्य का निर्धारण किया है और इसे दी गई पाटन मार्जिन सारणी में पैरा 52 में दर्शाया है।

जी.7. पाटन मार्जिन सारणी

52. संबंधित संबद्ध देशों से सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिये पीओआई के दौरान पाटन मार्जिन नीचे दी गई सारणी के अनुसार निर्धारित किया गया है:-

क्र. सं.	देश	उत्पादक	निर्यातक	निर्मित सामान्य मूल्य सामान्य/मूल्य	निवल निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
				(अम.डॉ./मी.ट)	(अम.डॉ./मी.ट)	(अम.डॉ./मी.ट)	(%)	(रेंज)
1	चीन जन. गण.	क. मै० शाउगुआंग मेलन पेपर कंपनी लिमिटेड ख. मै० शानडांग केनमिंग पेपर होल्डिंग्स लिमिटेड,	मै. केनमिंग (एच.के.) लिमिटेड	***	***	***	***	60-70
2	चीन जन. गण.	गोल्ड ईस्ट ट्रेडिंग हांगकांग)) कंपनी लिमिटेड	गोल्ड ईस्ट ट्रेडिंग पनी हांगकांग) क) लिमिटेड	***	***	***	***	60.70
3	चीन जन. गण.	अन्य सभी	अन्य सभी	***	***	***	***	90-100
4	यूरोपियन संघ	क. सप्पी एलफील्ड जीएमबीएच ख. सप्पी एनहिनजेन जीएमबीएच ग. सप्पी ग्राटकोर्न जीएमबीएच घ. सप्पी फिनलैंड ऑपरेशनली (किरकनेमी) ड. सप्पी लेनकेन (एनबी) च. सप्पी मास्ट्रेच्ट बी.वी.	क सप्पी यूरोप एसए ख पीजी पर कंपनी लि.	***	***	***	***	25-35

क्र. सं.	देश	उत्पादक	निर्यातक	निर्मित सामान्य मूल्य सामान्य/मूल्य	निवल निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
5	यूरोपीय संघ	क. मै. यूपीएम कंप्यूनिक्शन पेपर्स ओवाई ख मै. यूपीएम स्पेशियलिटी पेपर्स ओवाई, ग. यूपीएम जीएमबीएच	मै. यूपीएम सेल्स ओवाई	***	***	***	***	(5)-0
6	यूरोपियन संघ	अन्य सभी	अन्य सभी	***	***	***	***	70-80
7	यूएसए	सभी	सभी	***	***	***	***	140- 150

ज. क्षति निर्धारण एवं कारणात्मक संबंध

ज.1. घरेलू उद्योग के द्वारा किया गया निवेदन:

53. घरेलू उद्योग के द्वारा किये गये निवेदन नीचे दिये अनुसार है:

- क) कुछ हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा यह दावा किया है कि जांच शुरूआत की समाप्ति होने पर जांच की अवधि समाप्त नहीं हो जाती है। यह निवेदन किया है कि अप्रैल, 2016 - जून, 2017 हाल ही की अवधि थी, क्योंकि जांच शुरूआत करने का नोटिस जनवरी, 2018 में जारी किया गया था। विगत में बहुत से मामले हुए हैं जिनमें पीओआई 6 महीने से मामूली से ज्यादा पुरानी थी। किसी मामले में यदि प्राधिकारी ने प्रासंगिक समझा तो उसमें पीओआई के बाद के घरेलू उद्योग के निष्पादन का भी मूल्यांकन किया जा सकता है। घरेलू उद्योग का निष्पादन पाटन आयातों की वजह से प्रतिकूल बना रहेगा।
- ख) यह तर्क दिया गया है कि ईयू से आयातों की कीमतें चीन और अमेरिका के मुकाबले अधिक हैं। घरेलू उद्योग का कहना है कि ईयू से किये गये आयात, चीन और अमेरिका से निर्यात की गई वस्तुओं तथा घरेलू उद्योग के द्वारा उत्पादित और बेची गई वस्तुओं से मुकाबला कर रहे हैं और इस प्रकार संचयी आंकलन उचित है।
- ग) मांग का आंकलन घरेलू उद्योग की बिक्रियों, अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियों और समस्त स्रोतों से किये आयातों को जोड़ के रूप में देखा जा सकता है। विचाराधीन उत्पाद की मांग, जो याचिका से देखी जा सकती है, क्षति अवधि के दौरान बढ़ी है और यह सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाती है।
- घ) यह तर्क दिया गया है कि देश में मांग बढ़ी है और पीओआई में एक बड़ी अवधि के घरेलू उद्योग के कार्यों के बंद हो जाने को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन उत्पाद की उपलब्धता में कमी होने से आयातों की मात्रा में बढ़ोतरी हुई। घरेलू उद्योग इस बात से सहमत हैं कि घरेलू उद्योग पीओआई की एक बड़ी अवधि के दौरान बंद रहा। तथापि, घरेलू उद्योग यह बताता है कि वर्ष 2015-16 में घरेलू उद्योग के द्वारा प्राप्त किये गये अधिकतम क्षमता उपयोग को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग के बंद रहने की अवधि के लिए समायोजन करने के बावजूद आयातों में पूर्णतः तथा सापेक्ष अवधियों में अभी बढ़ोतरी होने को दर्शाएगा।
- ड.) संबद्ध देशों से आयात मूल्यों में कच्चे माल की लागतों में बिना किसी संगत गिरावट के पीओआई के दौरान काफी कमी हुई। यह घरेलू उद्योग को हुई क्षति का मुख्य कारण रहा है।
- च) संबद्ध देशों से आयातों के पट्टा मूल्य पूर्णतः और प्रत्येक संबद्ध देश से अलग-अलग पट्टा मूल्य क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की निवल बिक्रियों की वसूली से कम रहे हैं। अतः बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी हो रही है। कीमतों में कमी होने की सीमा में पीओआई के दौरान बढ़ोतरी हुई है।

- छ) यदि इष्टतम स्तर पर समायोजित किये गये आंकड़ों पर विचार किया हो, तो यह देखा जाएगा कि बिक्रियों की अधिकतम लागत में जबकि बढ़ोतरी हुई है, क्षति अवधि में विक्रय मूल्य में बढ़ोतरी हुई। तथापि, विक्रय मूल्य में बढ़ोतरी लागतों में बढ़ोतरी से काफी कम है। संबद्ध आयातों की पहुंच मूल्य क्षति जांच अवधि के दौरान बिक्रियों की अधिकतम लागत से भी काफी कम रहें। अतः यह देखा जा सकता है कि आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों को नियंत्रित रखने एवं कम रखने दबाव बना रहा है।
- ज) याचिकाकर्ता ने घरेलू उद्योगों के अधिकतम क्षतिरहित मूल्य के साथ संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य से तुलना भी की है। दोनों की तुलना यह दर्शाती है कि संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य क्षतिरहित मूल्य से काफी कम है। इसके परिणामस्वरूप सभी संबद्ध देशों से सस्ता और/अथवा क्षति मार्जिन सकारात्मक रहा।
- झ) संपूर्ण अवधियों तथा सापेक्ष अवधियों में आयातों में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा, आयातों से घरेलू मूल्य कम हो रहे हैं और मूल्य में कमी होने से बाजार में घरेलू उद्योग के मूल्य नियंत्रित हो रहे हैं तथा ऐसे पाटन आयातों से काफी हद तक मूल्यों को और नियंत्रित रखने एवं कम होने की संभावना है।
- ट) घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्रियों में क्षति अवधि के दौरान गिरावट हुई। यद्यपि यह माना गया है कि उत्पादन और बिक्रियों में गिरावट होने से भी बंदी हुई है, जो घरेलू उद्योग को करनी पड़ी थी। परंतु याचिकाकर्ता यह निवेदन करता है कि संबद्ध देशों से काफी कम मूल्य पर आयातों की वजह से बाजार में मूल्यों में गिरावट हुई है, फिर भी घरेलू उद्योगों की बिक्री की मात्रा काफी कम रही है।
- ठ) बंदी के प्रभाव की वजह से उत्पादन को समायोजित करने के बाद भी तथा बिक्रियों के समुचित रूप से समायोजित करते हुए घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति अवधि में गिरावट हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग के पास बाजार हिस्सा इतना कम होने के बावजूद विदेशी उत्पादकों ने अपने मूल्यों को काफी हद तक कम किया।
- ड) याचिकाकर्ता कंपनी के लाभों में वर्ष 2014-15 में बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद में वे वर्ष 2015-16 में गिरावट को दर्शाते हैं तथा जांच अवधि के दौरान यह नकारात्मक हुआ। लाभों की जो स्थिति हुई और जांच अवधि के दौरान नकारात्मक रहने की तरह नगद लाभ भी उसी प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। याचिकाकर्ता कंपनी का आरओसीई क्षति जांच अवधि के दौरान निरंतर गिरावट होने को दर्शाता है। यद्यपि याचिकाकर्ता यह मानता है कि कम मूल्य के आयातों तथा उद्योग के सामने आयी परिणामी वित्तीय बाधाओं, दोनों, की वजह से उनके कार्य प्रभावित हुये थे, परंतु स्पष्ट तौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अवधि में घरेलू उद्योग को क्षति हुई होगी, चाहे उन्होंने विगत में अधिकतम उत्पादन किया होगा, याचिकाकर्ता ने विगत में प्राप्त किये गये उत्पादन को स्वीकार करते हुए घरेलू उद्योग की लाभप्रदता का निर्धारण किया है। इसके अलावा, प्रासंगिक अवधि के दौरान अलग-अलग किस्म के बहुत उत्पाद बेचे गये थे, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग की लाभप्रदता का निर्धारण करने के लिए वर्ष 2015-16 में यथा स्थिति उद्योग के मिश्रित उत्पाद के बारे में विचार किया गया था, जो पीओआई के दौरान प्रचलित रही होगी। गोपनीयता के आधार पर प्रासंगिक लाभप्रदता विवरण संलग्न हैं। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने, घरेलू उद्योग का अधिकतम उत्पादन स्तर जो रहा होगा उसे दर्शाते हुए क्षति विवरण को अद्यतन किया है। यह देखा जायेगा कि घरेलू उद्योगों को अभी वित्तीय हानियां हो रही होंगी। प्रत्यक्षतः घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पीयूसी के कम मूल्य के पाटन आयातों की वजह से हानि हुई है। आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य और बिक्री की लागत से कम है। कम कीमत के आयातों में पर्याप्त रूप से बढ़ोतरी होने से घरेलू उद्योग को हानि होने की संभावना है।
- ढ) घरेलू उद्योग की माल – सूचियों में वर्ष 2015-16 तक बढ़ोतरी हुई, परंतु जांच अवधि के दौरान कमी हुई। यह भी नोट किया जाये कि बंदी करने के बावजूद और कम मात्रा में उत्पादन और बिक्री करते हुए माल सूची स्तर पर्याप्त रहा। घरेलू उद्योग के रोजगार स्तर और भुगतान की गई मजदूरियां भी जांच अवधि के दौरान निरंतर गिरावट को दर्शाती हैं।
- ण) याचिकाकर्ता की मौजूदा क्षमता का अधिकांशतः उपयोग नहीं किया जाता है। अनुप्रयुक्त रही वर्तमान क्षमता से तथा घरेलू उद्योग को हुई हानियों से पूंजी जुटाने के लिए याचिकाकर्ता की सामर्थ्य कमजोर हुई है।
- त) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन का प्रभाव घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल रहा है। याचिकाकर्ता ने पाटन मार्जिन की गणना की है, जो सकारात्मक और पर्याप्त है।
- थ) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में क्षति जांच अवधि के दौरान बढ़ोतरी हुई है। संबद्ध आयातों की मात्राओं में निरंतर बढ़ोतरी हुई थी। घरेलू उद्योग को बंदी करनी पड़ी थी, इसके लिए समायोजन करने के बाद भी आयात बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, जो स्पष्टतः यह दर्शाती है कि आयातों में बढ़ोतरी याचिकाकर्ता के द्वारा उत्पादन को निलंबित करने की वजह से ही नहीं हुई थी। यह स्पष्ट रूप से पाटित आयातों से पहले से ही मौजूद अधिक मात्राओं के लिए आयातों में और बढ़ोतरी होने के खतरा को दर्शाता है। अनुचित मूल्यों के साथ जुड़ी आयात की मात्रा में ऐसी बढ़ोतरी से घरेलू उद्योग समाप्त हो जाएगा।

- द) चीन में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और मांग में गिरावट हुई है। तथापि, मांग में गिरावट, क्षमता और उत्पादन में हुई गिरावट से काफी अधिक है। यह देखा जा सकता है कि मांग वर्ष 2017 में चीन में कुल क्षमता से लगभग आधी है। यह अकेले ही चीन में अप्रयुक्त क्षमताओं और माल-सूची के स्तरों की सीमा को दर्शाती है।
- ध) चीन में कोटिड पेपर का विकास वर्ष 2009 से 2011 और वर्ष 2011 से 2015 तक दो चरणों में किया गया था। चीन के उत्पादकों का मुख्य उद्देश्य संबद्ध उत्पाद के तरीके का विस्तार करना तथा वृहद क्षमताओं की स्थापना करना था। इससे वर्ष 2009 में 5.79 मिलियन टन का क्षमता स्तर बढ़ कर वर्ष 2011 में 7.99 मिलियन टन हो गया। इससे आखिरकार संबद्ध उत्पाद के उत्पादन स्तर में बढ़ोतरी हुई। यह वर्ष 2009 में 5 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2011 में 6.71 मिलियन टन हो गया।
- न) चीन गणराज्य में कोटिड पेपर उद्योग का दूसरा चरण वर्ष 2011 से 2015 तक था। चीन के उत्पादकों ने इस चरण के दौरान अधिक क्षमताएं होने की समस्याओं का सामना किया जो प्रथम चरण में उठाये गये व्यापक विस्तार उपायों की वजह हुई थी। मांग में गिरावट होने तथा प्रथम चरण के विस्तार की वजह से बेकार हुई क्षमताओं के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपयोग में बढ़ोतरी होने तथा प्रिंट मीडिया विज्ञापन में कमी होने के कारण यह और ज्यादा प्रभावित हुई थी।
- प) संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास उपलब्ध माल – सूचियों के स्तर का घरेलू उद्योग के द्वारा पता नहीं लगाया जा सका था। तथापि, संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास उपलब्ध पर्याप्त क्षमता और संबद्ध देशों में पीयूसी की मांग में गिरावट होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि विदेशी उत्पादक अल्प अवधि में उत्पादन बढ़ा सकते हैं और अभी पर्याप्त माल सूची स्तर बनाए रखते हैं।
- फ) याचिकाकर्ता ने याचिका में एक विस्तृत गैर आरोप विश्लेषण प्रस्तुत किया है और यह सुनिश्चित किया है कि (क) सूचीबद्ध ज्ञात कारकों की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है, (ख) पाटित आयातों के अलावा कोई और कारक नहीं हैं, जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। साथ ही, यह कोई कानूनी जनादेश नहीं है कि विचाराधीन उत्पाद का पाटन घरेलू उद्योग की क्षति पहुंचाने का एकमात्र कारण है। जब तक घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने के कारणों में एक कारण पाटन है, तब तक यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि कारक लिंक संबंधी अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है।
- ब) अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा या तो नगण्य है अथवा उच्चतर मूल्यों पर है ; दावा की गई क्षति घरेलू प्रचालनों की वजह से है और न कि निर्यात बिक्रियों की वजह से है, जैसा कि घरेलू बिक्रियों के लिए अलग-अलग उपलब्ध करायी गई लागत एवं क्षति संबंधी सूचना से स्पष्ट है; संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रिया में भी किसी प्रकार कोई महत्वपूर्ण विकास/परिवर्तन नहीं हुआ है; याचिकाकर्ता के द्वारा उत्पादित और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों के निष्पादन से घरेलू उद्योग को क्षति का कोई संभव कारण नहीं है, क्योंकि उपलब्ध करायी गई सूचना केवल संबद्ध वस्तुओं के लिए ही है; व्यापार संबंधी कोई प्रतिबंधित कार्य नहीं है, जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।
- भ) याचिकाकर्ता कंपनी एक स्थापित जिम्मेदार बेल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (बीआईएलटी) का एक भाग है, जो लेखन और प्रिंटिंग (डब्ल्यू एंड पी) कागज का भारत का सबसे बड़ा निर्माता है और उसके अच्छे निवेशक संबंध हैं। समस्त सूचना कंपनियों की वेबसाइट पर नियमित रूप से प्रकाशित की जाती है। बंदी संबंधी तथ्य के बारे में वार्षिक रिपोर्ट में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है जो दायर की गई याचिका का एक भाग है। अतः घरेलू उद्योग के द्वारा प्राधिकारी को गुमराह करने अथवा तथ्यों को छिपाने का कोई इरादा नहीं था।
- म) याचिकाकर्ता के दो संयंत्र हैं, कभी एक संयंत्र बंद होता था और कभी दूसरा संयंत्र बंद होता था। अतः याचिकाकर्ता के उत्पादन स्तर में कमी आयी थी। तथापि, अधिकांश महीनों के दौरान उत्पादन होता था। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने पीओआई में शामिल सभी महीनों के दौरान संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की थी जैसा कि पहले दायर की गई याचिका के साथ याचिकाकर्ता के द्वारा दायर किए क्यू-15 से देखा जा सकता है। इसके अलावा, उन महीनों के लिए भी, जब घरेलू उद्योग ने पर्याप्त उत्पादन किया था। आयात के सकारात्मक पाटन एवं क्षति मार्जिन को दर्शाता है। मार्जिन का स्तर भी समान है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग के उत्पादन की मात्रा के तथ्य को ध्यान में न रखते हुए निर्यातकों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं है। अतः घरेलू उद्योग यद्यपि ,निरंतर उत्पादन कर रहा था, परंतु पाटन एवं क्षति संबंधी तथ्य सही रहा होगा।
- य) घरेलू उद्योग ने बंदी संबंधी सूचना भी दी है। यह सूचना घरेलू उद्योग की अधिकतम लागत पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति करने संबंधी आयातों में बढ़ोतरी को अभी दर्शाता है, जो वर्ष 2015-16 में प्राप्त किए गए क्षमता उपयोग स्तरों की तरह उन पर आधारित थी और यह इससे स्पष्ट होगा कि उन लागतों पर विचार करने के बावजूद घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से अनुचित मूल्य के आयातों से हुई क्षति का शिकार रहा है। आंकड़े स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि उन अधिकतम स्तरों पर भी घरेलू उद्योग को क्षति होगी और क्षति हो रही है तथा संबद्ध देशों से आयातों का पाटन हो रहा है।

- र) घरेलू उद्योग की बंदी की वजह से पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट हुई। लेकिन उस बंदी के बावजूद, यह देखा जा सकता है कि संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्यों में पीओआई के दौरान पर्याप्त गिरावट हुई। लिखित निवेदन के साथ संलग्न संशोधित सूचना यह दर्शाएगी कि वर्ष 2015-16 में घरेलू उद्योग के द्वारा प्राप्त किए गए क्षमता उपयोग स्तरों के आधार पर पीओआई के दौरान उत्पादन का समायोजन कर लिया गया था, फिर भी क्षति जांच अवधि के दौरान आयात की मात्राओं में बढ़ोतरी हुई थी और मूल्यों में गिरावट होने से पीओआई के दौरान आयातों में पर्याप्त रूप से बढ़ोतरी हुई। समायोजित किए गए उन स्तरों पर भी देश में आयातों का पाटन हो रहा है, जिससे घरेलू उद्योग को पहले से हो रही मौजूदा क्षति में बढ़ोतरी हो रही है। किसी मामले में मांग और आपूर्ति का अंतर पाटन को उचित नहीं ठहराता है।
- कक) विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों का दावा यह है कि क्षति विभिन्न अन्य कारकों की वजह से है और न कि आयातों की वजह से है। यह दावा सही नहीं है। जैसा कि पहले बताया गया है कि जब याचिकाकर्ता यह मानता है कि उनके प्रचालन कम कीमत के आयातों और उद्योग के सामन आयी परिणामी वित्तीय बाधाओं, दोनों तरह से प्रभावित हुए थे; प्रत्यक्षतः यह सुनिश्चित करने के लिए कि घरेलू उद्योग के द्वारा विगत में अधिकतम उत्पादन किया हो, फिर भी उनको इस अवधि में क्षति हुई होगी, याचिकाकर्ता ने विगत में प्राप्त किए उत्पादन पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग की लाभप्रदता का निर्धारण किया है। इसके अलावा, प्रासंगिक अवधि के दौरान विभिन्न किस्म के बहुत से उत्पादों की बिक्री की गई थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015-16 में उद्योग के लिए बनाए रखे मिश्रित उत्पाद के बारे में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता का निर्धारण करने के लिए उसी तरह से विचार किया गया था, जैसा कि पीओआई के दौरान रहा होगा। यह देखना होगा कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के कम मूल्य के पाटित आयातों की वजह से हानि होती है।
- खख) वर्तमान मामले में संचयी आकलन करने के लिए सभी शर्तों को पूरा किया जाता है। विशेष तौर पर, ईयू से हुए आयात का चीन और अमेरिका से निर्यात की गई वस्तुओं और घरेलू उद्योग के द्वारा उत्पादित और बेचे गए माल से मुकाबला हो रहा है और इस प्रकार संचयी आकलन उचित है। इसके अलावा, यदि कीमतें ईयू की कीमतों से अधिक होती हैं, तब इससे कम क्षति मार्जिन होगा और इससे शुल्क की मात्रा कम होगी।

एच.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा निवेदन:-

54. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निर्यातकों, आयातकर्ताओं प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किए गए निवेदनों को प्राधिकारी ने प्रासंगिक माना है, जो निम्नानुसार है:-
- क) लागत में असाधारण बढ़ोतरी होने की वजह से वीआईएलटी का निष्पादन बिक्रित हो गया, जिसकी मुख्य वजह उनकी वित्तीय लागत और बिक्री संबंधी खर्चों में अचानक बढ़ोतरी होना है। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि घरेलू उद्योग को कथित पाटन आयातों की वजह से कोई क्षति नहीं हुई है। अपितु, उनको क्षति आयातों के अलावा अन्य कारकों की वजह से हुई है।
- ख) याचिकाकर्ता कंपनी को निवेश संबंधी खराब निर्णयों एवं अन्य परिसमापन मुद्दों की वजह से क्षति हो रही है। संबद्ध देशों से आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादन के बीच में कोई संबंध नहीं होता है।
- ग) कच्चे माल (सोडियम क्लोरेट) पर पाटनरोधी शुल्कों का विचाराधीन उत्पाद से संबंधित व्यापार पर प्रभाव पड़ा है।
- घ) बाजार में जे.के. पेपर नामक अन्य कंपनी अत्यंत अच्छा कार्य कर रही है। उन्होंने अपने इतिहास में कागज का सबसे अधिक उत्पादन प्राप्त किया है, जो विगत वर्ष के 4.50 लाख एमटी के मुकाबले वर्ष 2016-17 में 4.70 लाख एमटी है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उनका उत्पादन वर्ष 2015-16 के 99 प्रतिशत की तुलना में 103 प्रतिशत के क्षमता उपयोग के अनुरूप हुआ। कंपनी ने लुगदी का 2.82 लाख एमटी का उत्पादन भी किया।
- ड.) कथित पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बारे में कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। इसलिए प्राधिकारी से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान जांच को समाप्त करने का अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग को हुई किसी प्रकार की क्षति आयातों के अलावा अन्य कारकों की वजह से हुई है और यह कथित पाटन आयातों से बिल्कुल में संबंध नहीं है। यह नोट किया जाता है कि यह पहली बार हुआ है कि याचिकाकर्ता ने अपने लिखित निवेदनों में तथा घरेलू उद्योग को हुई वस्तुगत क्षति के खतरे संबंधी प्रमाण में तीन संबद्ध देशों को ध्यान में रखते हुए संशोधित क्षति सूचना उपलब्ध करायी है। कृपया यह नोट किया जाता है कि न तो घरेलू उद्योग के द्वारा दायर की गई याचिका और न ही जांच शुरुआत की अधिसूचना परोक्ष रूप से यह निर्दिष्ट करती है कि जांच में "संबद्ध क्षति का खतरा" की जांच करने का प्रस्ताव है। स्पष्ट तौर पर नियम के अनुसार वस्तुगत निहित "वस्तुगत क्षति का खतरा" में ऐसे दावों को जांच के इस चरण में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में प्रतिवादी पक्षकारों यह प्रस्तुत करते हैं कि जांच के इस चरण में ऐसी नई सूचना पर विचार नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने उक्त अतिरिक्त सूचना के द्वारा संपूर्ण आवेदन पत्र में प्रभावी रूप से संशोधन किया है, जो कानून के निश्चित प्रावधानों के न केवल विरुद्ध हैं,

- अपितु स्वाभाविक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के घोर उल्लंघन भी है। घरेलू उद्योग से अतिरिक्त सूचना, को स्वीकार करना वस्तुतः नया आवेदन होगा। उसकी कानून में परिकल्पना नहीं की जाती है, और वह मौखिक सुनवाई के प्रयोजन को ही पूर्णतः नष्ट कर देता है।
- च) इसके अलावा, जनता की सुनवाई के बाद में दायर किये आंकड़ों और साक्ष्य को निरस्त करने के लिए प्राधिकारी की सुसंगत प्रथा रही है। प्राधिकारी जांच के विलंबित चरण में दायर किये गये आंकड़ों और सूचना को इस वजह से समनुरूप निरस्त कर रहे हैं कि अन्य पक्षकारों को ऐसे आंकड़ों के बारे में मत प्रस्तुत करने का अवसर न मिले। इसलिए, यह अनुरोध है कि प्राधिकारी वर्तमान मामले का मामला का निर्धारण करते समय ऐसी सूचना की सुनवाई और उपेक्षा करने के बाद याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत की गई नई सूचना को कृपया निरस्त कर सकते हैं।
- छ) घरेलू उद्योग को उसकी लंबी अवधि तक बंदी अकुशल प्रबंधन, वित्तीय कठिनाई और अव्यावहारिक निवेश निर्णयों की वजह से क्षति हुई है। यह रिकार्ड करने का मामला है कि घरेलू उद्योग विगत कुछ वर्षों से वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और उनकी लागतें आसमान को छू रही हैं।
- ज) ईयू उत्पादों के बीच में प्रतिस्पर्धा की शर्तें, अमेरिका और चीन से आयात तथा घरेलू उत्पाद संचयी आकलन में मदद नहीं करते हैं। ईयू से आयातों की वजह से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है और इसलिए ईयू से आयातों पर कोई उपाय लागू नहीं करने चाहिए।
- झ) कैजुअल्टी नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग हुई क्षति आयातों में बढ़ोतरी होने से संबंधित नहीं होती है, अपितु यह वस्तुतः आत्मकृत होती है।
- ट) रिकार्ड किये गये तथ्यों से यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने संबद्ध उत्पाद के बड़े हुये आयातों को बढ़ा-चढ़ा कर बताया है और घरेलू उद्योग वस्तुगत क्षति की जानबूझकर कल्पना की है। यदि जांच प्राधिकारी जांच को जारी रखते हैं तो यह निर्धारित करना होगा कि संबद्ध उत्पाद के आयातों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिससे याचिकाकर्ता को क्षति हुई हो।
- ठ) प्रारंभ में, वर्तमान पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने के लिए आवेदन पत्र पांच संबद्ध देशों नामतः चीन गणराज्य, ईयू, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के विरुद्ध दायर किया गया था। तथापि, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इसकी जांच शुरुआत अधिसूचना के द्वारा इंडोनेशिया और कोरिया गणराज्य को वर्तमान जांच के कार्य क्षेत्र के बाहर कर दिया था। इंडोनेशिया और कोरिया गणराज्य को अलग कर देने से याचिका में दर्शाये गये आयातों की मात्रा बदल गई है, तथापि, याचिकाकर्ता ने हितबद्ध पक्षकारों के लिए संशोधित सूचना उपलब्ध नहीं करायी है।
- ड) क्षति अवधि और पीओआई के दौरान क्षति अपरिवर्तित रहती है। पीओआई के दौरान उत्पादन और क्षमता उपयोग में पर्याप्त रूप से गिरावट आई है। ऐसी गिरावट के कारण मै० बीआईएलटी ग्राफिक पेपर प्रोडक्ट्स लि० की चल पूंजी और उसके सामने आई कच्चे माल संबंधी बाधाएँ हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 की बेल्लारपुर इंडस्ट्रीज लि० (बीआईएलटी की धारक कंपनी) की वार्षिक रिपोर्ट यह बताती है कि बीआईएलटी अत्यधिक ऋण की स्थिति में है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है और यह क्षति निश्चित तौर पर संबद्ध देशों के आयातों से नहीं हो रही है। याचिकाकर्ता ने यह भी निवेदन किया था कि उनके संयंत्र में उत्पादन कार्य 12 महीनों अर्थात् जुलाई, 2016 से जून, 2017 तक बंद कर दिया था। जांच अवधि के कुल 15 महीनों में से संयंत्र में उत्पादन 12 महीने तक बंद कर दिया था।
- ढ) याचिका के साथ संलग्न प्रोफार्मा-IV क में दर्शाए अनुसार माल सूचियों को आधार वर्ष 2013-14 की तुलना में पीओआई के दौरान कम कर दिया है। चल पूंजी संबंधी बाधाओं और कच्चे माल की कमी की वजह से घरेलू उद्योग भारतीय प्रयोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में, भारत में मांग और आपूर्ति के अंतर को समाप्त करने के लिए आयातों में बढ़ोतरी होती है और इससे निश्चित तौर पर घरेलू उद्योग कोई क्षति नहीं होती है। अतएव, आयातों से घरेलू उद्योग को कहीं भी क्षति नहीं हो रही है।
- ण) घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में पीओआई के दौरान पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है, जो आधार वर्ष 2013-14 में 100 से बढ़ कर पीओआई के दौरान 154 हो गई। तथापि, प्रचलित बाजार में कच्चे माल की लागत में ऐसी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। संपूर्ण क्षति अवधि और पीओआई के दौरान मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- त) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधार हुआ है, जो आधार वर्ष 2013-14 में 100 से बढ़ कर वर्ष 2015-16 में 102 हो गई। याचिकाकर्ता की निबल स्थाई परिसंपत्तियों और चल पूंजी में आधार वर्ष 2013-14 की तुलना में पीओआई के दौरान काफी बढ़ोतरी हुई है। निबल स्थायी परिसंपत्तियाँ आधार वर्ष 2013-14 की तुलना में पीओआई के दौरान 100 बढ़कर 130 हुई है।

चल पूंजी आधार वर्ष 2013-14 की तुलना में पीओआई के दौरान 100 से बढ़ कर 163 हुई है। व्यापार उपचार महानिदेशक से इसकी गहन जांच करने का अनुरोध है।

- थ) याचिका में यह दावा किया है कि याचिकाकर्ता को मात्रा और मूल्य संबंधी हुई क्षति की वजह संबद्ध देशों से आयातों में बढ़ोतरी होना है। तथापि, यह दावा याचिकाकर्ता को हुई क्षति प्रभाव को दर्शाने से संबंधित है। याचिका स्पष्टतः यह दर्शाती है कि याचिकाकर्ता को हुई किसी प्रकार की कथित क्षति आत्मकृत थी और याचिकाकर्ता ने जन सुनवाई के दौरान स्वयं इसको माना है। इसकी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि किसी अन्य भारतीय उत्पादक को कोई क्षति नहीं हो रही है। याचिकाकर्ता के द्वारा कम उत्पादन करने की वजह से आपूर्ति में कमी हुई और स्थानीय कमी की वजह अनिवार्य आयात प्रतिस्थापन किया गया था, क्योंकि विचाराधीन उत्पाद की मांग क्षति अविध के दौरान उसी स्तर पर रही।
- द) याचिकाकर्ता पीओआई और क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों के लिए 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत मूल्य सस्ते होने का दावा करता है। यदि मूल्य सस्ते होने के कारण क्षति हो रही थी, तो याचिकाकर्ता के द्वारा इस अवधि के दौरान हानियों को देखना चाहिए।
- ध) याचिका पीओआई के दौरान लागत में हुई आकस्मिक बढ़ोतरी को दर्शाती है, जो शेष उद्योग में नहीं हुई थी। प्राधिकारी से अन्य सहयोगी उत्पादकों की लागत का विश्लेषण करने का अनुरोध है, जो लागत में उपर्युक्त बढ़ोतरी को नहीं दर्शाएगी।
- न) याचिकाकर्ता को अनकोटेड पेपर के अपने उत्पादन के वजह से पर्याप्त क्षति भी हो रही है, जिसके लिए याचिकाकर्ता ने क्षति की मात्रा की अलग जांच करने का दावा किया है। इसकी वजह से याचिकाकर्ता के अनकोटेड पेपर के उत्पादन में भी काफी गिरावट आई है।
- प) याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि लाभप्रदता और नगद लाभों में भारी कमी हुई है और पीओआई के दौरान अत्यधिक हानियां हुई थीं। प्रतिवादी याचिकाकर्ता की वार्षिक रिपोर्टों का हवाला देता है, जो उन वित्तीय लागतों में तेजी से हुई बढ़ोतरी को दर्शाती है, जिनका उनकी लाभप्रदता पर सीधा प्रभाव होगा। वार्षिक रिपोर्टें अच्छे पीबीआईटी और नियोजित पूंजी पर लाभ को भी दर्शाती है।
- फ) याचिकाकर्ता ने जन सुनवाई के दौरान स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि उनके संयंत्र पीओआई के 15 महीने में से 12 महीने बंद रहे थे। इस तरह से स्वीकार करने से यह स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार की क्षति आत्मकृत होगी और पाटनरोधी शुल्क के लिए संपूर्ण मामला दिखावे का है। पाटित आयातों से मात्रा और मूल्य संबंधी पैरामीटरों को क्षति हो सकती है, परंतु उनसे निश्चित तौर पर संयंत्र बंद नहीं हो सकता है।
- ब) याचिका में दिये गये आंकड़े भारत में एक संस्था के निष्पादन संबंधी आंकड़ों को ही दर्शाते हैं और ये भारतीय घरेलू बाजार की स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। जेके पेपर और आईटीसी लि० जैसे अन्य उत्पादक समुचित स्तरों पर निष्पादन कर रहे हैं और केवल एक याचिकाकर्ता है जो आर्थिक रूप से प्रतिकूल स्थितियों से गुजर रहा है, जो आत्मकृत हैं।
- भ) घरेलू उद्योग ने यह निवेदन किया है कि जेके पेपर ने विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और उसने जन सुनवाई के दौरान जांच का विरोध नहीं किया है। यह निवेदन है कि जेके पेपर के आयातों को ध्यान में न रखते हुए उनके निष्पादन संबंधी आंकड़ों पर विचार करना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वे सबसे बड़े घरेलू उत्पादकों में से एक हैं।
- म) याचिकाकर्ता ने मलेशिया में आर्थिक सहायता प्राप्त की थी और वर्ष 2007 में लाभ की स्थिति में आने में असमर्थ हुआ था और इस तरह वर्ष 2015 में बेचने की कोशिश की थी। यह केवल वर्ष 2018 में समाप्त हुये निवेश के बारे में अपने आपको वंचित करने के लिए ही था। इससे याचिकाकर्ता के उद्धार एवं पुनः वित्तपोषित करने के प्रयासों में विलंब हुआ। याचिका के निकट स्रोतों से यह भी पुष्टि होती है कि याचिकाकर्ता समूह के भीतर अत्यधिक वित्तीय समस्याएँ थीं। याचिकाकर्ता के सामने आये गैर उत्तरदायी कारकों को ध्यान में रखते हुए यह निवेदन है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि आयातों और कथित क्षति के बीच में कोई कारणात्मक संबंध नहीं होता है और कथित क्षति आत्मकृत होती है। क्षति की गणना करना इस तथ्य की वजह से अनुचित होगा कि इसकी गणना पीओआई के 15 महीनों में 12 महीनों तक संयंत्र के बंद रहने के संदर्भ में की गई है और यदि क्षति अभी निर्धारित की है, तो माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा बंदी की अवधि विशेषकर पीओआई के दौरान किये असाधारण खर्चों को अलग-थलग करने के बाद में बनाने और बेचने के लिए लागत को पुनः निकालने तथा एनआईपी की गणनाओं के बारे में विचार करना होगा, क्योंकि यह एक आत्मकृत आभास है।
- य) यह निवेदन है कि मूल मामला होने से वर्तमान जांच के परिप्रेक्ष्य में और न कि एसएसआर जांच के संदर्भ में बाद के पीओआई आंकड़ों पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। बाद के पीओआई आंकड़ों पर विचार करना माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के विगत कार्य के अनुरूप नहीं होगा।

- र) एक संचित तरीके से क्षति मात्रा का विश्लेषण किया गया है, जो इस बात को ध्यान में रखते हुए न्यायसंगत नहीं होगा कि ईयू को छोड़ा नहीं गया है, यद्यपि कोरिया गणराज्य और इंडोनेशिया के वही आंकड़े हैं।
- कक) यह निवेदन है कि पहुंच मूल्यों में पहले बताए अनुसार गिरावट नहीं हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए कथित क्षति आत्मकृत प्रतिकूल व्यापार परिस्थितियों से हुई थी। कथित कम मूल्य के आयातों से संयंत्र कैसे बंद हो गए हैं, इस बारे में याचिकाकर्ता ने कोई कारण नहीं बताए हैं।
- खख) याचिका में पीओआई के द्वारा घरेलू उद्योग के उत्पादन के बंद होने के बारे में घरेलू उद्योग ने कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी थी। घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने के कथित पाटित आयातों के अलावा घरेलू उद्योग ने भी कोई ज्ञात कारक उपलब्ध नहीं कराए थे। जन सुनवाई अर्थात् जांच शुरूआत के बाद लगभग 6 महीनों के दौरान घरेलू उद्योग ने पहली बार विशेष रूप से यह निवेदन किया कि जुलाई, 2016 से जून, 2017 तक उत्पादन बंद हुआ था और यह स्वीकार किया कि चल पूंजी संबंधी बाधाओं की वजह से भी क्षति हुई है, जिसको समायोजित करना अपेक्षित है।
- गग) वर्तमान पाटनरोधी जांच में जांच की अवधि अप्रैल, 2016 से जून, 2017 तक है। 15 महीनों की इस अवधि में से घरेलू उद्योग का कार्य जून, 2016 से जुलाई, 2017 तक अर्थात् कुल 15 महीनों के लिए बंद था। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के द्वारा स्वीकार किए अनुसार और बाद में निवेदन में बताए अनुसार से यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग के सामने आयी चल पूंजी संबंधी बाधाओं की वजह से घरेलू उद्योग बंद हुआ था। प्रतिवादी यह निवेदन करता है कि तीन महीनों की प्रचालन अवधि के आधार पर पाटन, क्षति अथवा कारणात्मक संबंध का समुचित आकलन नहीं किया जा सकता है। ऐसी अल्प अवधि के आधार पर क्षति का निर्धारण निरूपित नहीं होगा और एक विकृत तस्वीर प्रस्तुत करेगा। क्षति का सही आकलन करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को उस पीओआई का चयन करना चाहिए जिसमें घरेलू उद्योग अधिकांश अवधि तक प्रचालन में था।
- घघ) प्रतिवादी यह समझता है कि अनकोटेड पेपर और कोटेड पेपर की विनिर्माण प्रक्रिया में बड़ा अंतर होता है। कागज की कुछ विशेषताओं जैसे वजन, सतह ग्लास, चिकनाई अथवा स्याही को कम सोखने के लिए अनकोटेड पेपर पर कम्पाउंड अथवा पोलीमर का कोट लगाया जाता है। तदनुसार, अनकोटेड पेपर और कोटेड पेपर की उत्पादन लागत अथवा बिक्री लागत के बीच समानता होनी चाहिए।
- ड.ड.) इंडोनेशिया, थाइलैंड और सिंगापुर से “अनकोटेड कॉपियर पेपर” का आयात करने पर जारी पाटनरोधी जांच में घरेलू उद्योग के द्वारा उपलब्ध कराए गए अनकोटेड पेपर की बिक्री लागत की तुलना में कोटेड पेपर की बिक्री लागत में पर्याप्त अंतर होने की प्रवृत्ति है।

बिक्री लागत	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	पीओआई (ए)
अनकोटेड पेपर*	रूपये/मी० टन – सूची	100	101	100	99
कोटेड पेपर**	सूची	100	99	98	154

* अनकोटेड पेपर पर पाटनरोधी जांच में घरेलू उद्योग की याचिका

* वर्तमान याचिका

- चच) पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II, पैरा(IV) और पाटनरोधी समझौते के अनुच्छेद 3.4 में ऐसे अनिवार्य आर्थिक मापदंडों की सूची के लिए प्रावधान हैं, जिनकी निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा जांच की जानी अपेक्षित होती है। पाटनरोधी नियमावली के पैरा(IV), अनुबंध II के तहत निर्धारित अनिवार्य मापदंड उत्पादकता, निवेश पर लाभ, नगद प्रवाह, मजदूरी, विकास है। क्षति संबंधी इन अनिवार्य मापदंडों के संबंध में यदि कोई सूचना बिल्कुल उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो वस्तुगत क्षति के होने के बारे में कोई दावा नहीं किया जा सकता है।
- छछ) कागज का विनिर्माण करने में जिस कच्चे माल का उपयोग किया जा सकता है, वे लकड़ी, लुगदी, कृषीय अपशिष्ट (खोई, गेहूं का भूसा, चावल का छिलका आदि) और बेकार कागज है। भारत में कागज उद्योग के द्वारा स्वीकार्य तथ्य यह है कि भारत में लकड़ी की लुगदी की उपलब्धता में कमी है, जिसकी वजह से कच्चे माल का मूल्य अधिक होता है। भारत में कागज उद्योग को कच्चे माल की अधिकांश आवश्यकताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आयात करना होता है। यह भी माना है कि कच्चे माल का मूल्य अधिक होने की वजह से याचिकाकर्ता की मौजूदा क्षमता कम उपयोग हुआ है। इसलिए, प्रतिवादी का यह निवेदन है कि पूर्वोक्त कच्चे माल की कमी होने की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।
- जज) घरेलू उद्योग ने आंकड़ों में ऐसे परिवर्तन करने के लिए कोई स्पष्टीकरण दिये बिना संपूर्ण क्षति अवधि के लिए संबद्ध देशों से आयात की मात्रा और मूल्य के बारे में संशोधित आंकड़े उपलब्ध कराये हैं। केवल यह बताया है कि विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

और गैर विचाराधीन उत्पाद को अलग-अलग करने के लिए विस्तृत आयात पद्धति के साथ-साथ अद्यतन आयात आंकड़े उपलब्ध कराये जाते हैं।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

55. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किये गये निवेदनों को नोट किया है और हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किये गये निवेदनों पर विधिवत विचार करने के बाद पाटनरोधी नियमावली के अनुसार विभिन्न मापदंडों की जांच की है।

संचयी आकलन

56. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II (iii) में यह प्रावधान है कि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के आयात की स्थिति पाटनरोधी जांचों के समकालीन अध्याधीन है, निर्दिष्ट प्राधिकारी संचयी रूप से ऐसे आयातों के प्रभाव का आकलन करेगा, यदि यह निर्धारित करता है कि :-

- क) प्रत्येक देश से आयात की तुलना में स्थापित पाटन का मार्जिन निर्यात मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त 2 प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात का 3 प्रतिशत है अथवा जहां अलग-अलग देशों का निर्यात 3 प्रतिशत से अधिक है, ये आयात संचयी रूप से समान वस्तु के आयात का 7 प्रतिशत से अधिक है और ;
- ख) आयात के प्रभाव का संचयी आकलन आयात की गई वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतियोगिता की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त है।

57. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि -

- क) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का भारत में पाटन किया जा रहा है, प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन नियमावली के अधीन निर्धारित न्यूनतम से अधिक सीमा से अधिक है।
- ख) प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा आयातों की कुल मात्रा के तीन प्रतिशत अलग-अलग है।
- ग) आयातों के प्रभावों का संचयी आकलन उचित है, क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात प्रत्यक्षतः न केवल परस्पर मुकाबला करते हैं, अपितु भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग के द्वारा प्रदान की गई समान वस्तुओं से भी मुकाबला करते हैं।

58. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों से संचयी तौर पर घरेलू उद्योग के लिए हुई क्षति का आकलन करना उचित है।

59. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए..." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसार विचार किया गया है।

60. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि बीजीपीपीएल स्वयं अपने मूल कारणों की वजह से पीओआई के एक बड़े भाग के लिए संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर रहा था। एक स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण हेतु संबद्ध वस्तुओं के एक बड़े उत्पादक मै० जेके पेपर लि० से सूचना हेतु अनुरोध किया था। तदनुसार, प्राधिकारी ने अंतिम हजांच परिणाम के बाद के भाग में क्षति और कारणात्मक संपर्क का आकलन करने के लिए बीजीपीपीएल के आंकड़ों के अलावा मै० जेके पेपर लि० के आंकड़ों के बारे में भी अलग-अलग विचार किया।

61. ऐसे क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किये निवेदनों की जांच की जाती है और उनका नीचे दिये अनुसार समाधान किया जाता है, जिनको प्राधिकारी के द्वारा प्रासंगिक माना गया है:-

एच.4. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव**(क) मांग/स्पष्ट खपत का आकलन**

62. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के जोड़ के रूप में भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को ध्यान में रखा है, क्षति जांच अवधि और पीओआई (ए) के दौरान इस प्रकार आकलन की गई मांग में समनुरूप बढ़ोतरी हुई है।

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	पीओआई(ए)
घरेलू उद्योग बिक्री	मी० टन	***	***	***	***
बिक्री – जेके पेपर लि०	मी० टन	***	***	***	***
बिक्री – सेहासायी पेपर	मी० टन	***	***	***	***
संबद्ध देशों से आयात	मी० टन	4,22,136	4,48,579	4,53,452	6,18,075
अन्य आयात	मी० टन	76,073	1,15,430	1,68,398	1,91,571
मांग/खपत	मी० टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	108	116	123

ख. संबद्ध देशों से आयात की मात्रा:-

63. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना होता है कि क्या संबद्ध देशों से पाटित आयातों में पूर्णतः अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के संदर्भ में काफी बढ़ोतरी हुई है।

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	पीओआई (ए)
ईयू से पाटित न हुए आयात	मी० टन	24,755	28,666	26,647	31,611
ईयू से पाटित आयात	मी० टन	88,692	1,05,312	1,24,424	1,41,405
चीन गणराज्य	मी० टन	1,95,124	2,15,054	1,83,540	2,93,269
यूएसए	मी० टन	1,13,566	99,547	1,18,841	1,51,790
संबद्ध देशों से पाटित न हुये आयात	मी० टन	24,755	28,666	26,647	31,611
संबद्ध देशों से पाटित हुये आयात	मी० टन	3,97,382	4,19,913	4,26,805	5,86,464
अन्य देश	मी० टन	76,073	1,15,430	1,68,398	1,91,571
कुल आयात	मी० टन	4,98,210	5,64,009	6,21,850	8,09,646

64. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों में पीओआई (ए) के दौरान पूर्णतः बढ़ोतरी हुई है। जांच की अवधि के दौरान (क) पाटित आयातों में काफी वृद्धि का प्राथमिक कारण जांच की अवधि (क) के प्रमुख भाग के लिए बी जी जी पी एल की बंदी है।

ग. सापेक्ष अवधियों में संबद्ध देशों से आयात

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	पीओआई (ए)
भारत में उत्पादन के संदर्भ में संबद्ध देशों से पाटित आयात	%	120-130	130-140	130-140	380-390
भारत में मांग के संदर्भ में संबद्ध देशों से पाटित आयात	%	40-50	40-50	40-50	50-60

65. यह देखा गया है कि आधार वर्ष और पूर्व वर्षों की तुलना में पीओआई (ए) में उत्पादन और मांग के बारे में संबद्ध पाटित आयातों में बढ़ोतरी हुई। जांच की अवधि के दौरान (क) पाटित आयातों में काफी वृद्धि का प्राथमिक कारण जांच की अवधि (क) के प्रमुख भाग के लिए बी जी जी पी एल की बंदी है।

घ. मांग में बाजार का हिस्सा:

66. विभिन्न स्रोतों से आयातों तथा घरेलू उद्योग की बिक्रियों को ध्यान में रखते हुए भारत की मांग में संबद्ध पाटित आयातों के बाजार हिस्से की जांच की गई थी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं पीओआई (ए) में संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में काफी बढ़ोतरी हुई थी। पीओआई (ए) में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में काफी बढ़ोतरी हुई है। अन्य भारतीय उत्पादकों का बाजार हिस्सा क्षति जांच अवधि के दौरान लगभग वही रहा है। तथापि, घरेलू उद्योग समेत सभी घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में पीओआई (ए) के दौरान काफी गिरावट आयी है। इसकी मुख्य वजह बीजीपीपीएल के उत्पादन/बिक्रियों में गिरावट होना है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट होने से सृजित स्थान का संबद्ध देशों से आयातों द्वारा और अन्य देशों से आयातों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है।

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	पीओआई(ए)
घरेलू उद्योग	%	30-40	20-30	20-30	10-20
अन्य भारतीय उत्पादक	%	0-10	0-10	0-10	0-10
सभी घरेलू उत्पादकों का कुल बाजार हिस्सा	%	30-40	30-40	30-40	10-20
पाटित संबद्ध आयात	%	40-50	40-50	40-50	50-60
गैर पाटित और अन्य आयात	%	10-20	10-20	20-30	20-30
कुल	%	100	100	100	100

एच.5. घरेलू बाजार पर पाटित आयातों का मूल्य प्रभाव:-

67. मूल्यों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण करना होता है कि क्या भारत में समान उत्पादों के मूल्य की तुलना में कथित पाटित आयातों से मूल्य काफी कम हो रहे हैं अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव मूल्यों को अन्यथा कम करना अथवा मूल्य में बढ़ोतरी करना है, जो सामान्य अवधि में अन्यथा हुई होगी। संबद्ध देशों से पाटित आयातों की वजह से घरेलू उद्योग के मूल्यों पर प्रभाव की मूल्य में कटौती, सस्ते मूल्य, मूल्य नियंत्रण और मूल्य दबाव, यदि को हो, के संदर्भ में जांच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग के उत्पादन, निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) और क्षतिरहित मूल्य (एनआईपी) की संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के पहुंच मूल्यों के साथ तुलना की गई है।

(क). कीमत कटौती

68. कीमत कटौती करने संबंधी विश्लेषण करने के लिए घरेलू उद्योग के निवल बिक्रय मूल्य की संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ तुलना की गई है। घरेलू उद्योग के निवल बिक्रय मूल्य की गणना करते समय सभी करों, छूट, कटौतियों और कमीशन को काट लिया गया है और कारखानागत स्तर पर बिक्रियों की वसूली का पाटित आयातों की पहुंच मूल्य के साथ तुलना करने हेतु निर्धारण किया गया है। तदनुसार, संबद्ध देशों से पाटित आयातों की कीमत कटौती करने के प्रभाव नीचे दिये अनुसार है:-

विवरण	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	पीओआई
चीन जनवादी गणराज्य					
आयातों की पहुंच कीमत	रूपये/मी० टन	50,910	50,014	50,964	49,138
निवल बिक्रय कीमत	रूपये/मी० टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	रूपये/मी० टन	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
रेंज		15 - 25	25 - 35	15 - 25	20 - 30
ईयू					

आयातों की पहुंच कीमत	रूपये/मी० टन	57,508	55,844	54,629	52,864
निवल विक्रय कीमत	रूपये/मी० टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	रूपये/मी० टन	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
रेंज		5 - 15	5 - 15	5 - 15	10 - 20
यूएसए					
आयातों का पहुंच कीमत	रूपये/मी० टन	31,765	32,106	33,948	34,966
निवल विक्रय कीमत	रूपये/मी० टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	रूपये/मी० टन	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
रेंज		85 - 95	95 - 105	75 - 85	70 - 80

पूर्वोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि क्षति अवधि और पीओआई (ए) के दौरान संबद्ध देशों से कीमत कटौती सकारात्मक है।

ख. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण :-

69. यह निर्धारित करने के लिए, क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमत पर दबाव पड़ रहा है और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी हद तक मूल्य को प्रतिबंधित करना है अथवा मूल्य में बढ़ोतरियों को रोकना है, जो सामान्य अवधि में अन्यथा हुई होगी, क्षति अवधि में लागतों और मूल्यों में परिवर्तनों की नीचे दिये अनुसार तुलना की गई थी:-

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	पीओआई(ए)
विक्री की लागत	रूपये/मी० टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	98	154
विक्री कीमत	रूपये/मी० टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	99	102
पहुंच मूल्य	रूपये/मी० टन	47,533	47,781	47,725	46,700
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	100	98

70. उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि बी जी जी पी एल की विक्री कीमत वर्ष 2015-16 तक की विक्री लागत से अधिक रही है। तथापि, पीओआई (ए) के दौरान विक्री कीमत, विक्री की लागत से कम है। विक्रियों की लागत वर्ष 2015-16 की तुलना में पीओआई (ए) के दौरान 56 सूचकांक तक बढ़ गया है।

ग. कम कीमत पर विक्री

71. घरेलू उद्योग के क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण किया गया है और सस्ते मूल्य पर बेचने के लिए संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य के साथ इसकी तुलना की गई है। नियमावली के अनुबंध III में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी की जांच अवधि की उत्पादन लागत संबंधी सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर के निर्धारण किया गया है। एनआईपी का क्षमता प्रयोग के अधिकतम स्तर पर विचार करते हुए निर्धारण किया गया है, जिसको याचिकाकर्ता संयंत्र में प्राप्त

कर सकते हैं। विश्लेषण यह दर्शाता है कि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के क्षतिरहित मूल्य से कम था, जो सस्ते मूल्य पर बेचने के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाते हुए नीचे दी गई सारणी से देखा जा सकता है:-

विवरण	यूनिट	पीओआई(रूपये/मी० टन)	पीओआई(अमेरिकी डॉलर /मी० टन)
चीन जन. गण			
पहुंच कीमत	प्रति मी० टन	49,138	728.51
क्षतिरहित कीमत (एनआईपी)	प्रति मी० टन	***	***
कम कीमत पर बिक्री	प्रति मी० टन	***	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***	***
कम कीमत पर बिक्री	% श्रेणी	20 - 30	20 - 30
ईयू			
पहुंच कीमत	प्रति मी० टन	52,864	781.62
क्षतिरहित कीमत (एनआईपी)	प्रति मी० टन	***	***
सस्ते मूल्य पर बेचना	प्रति मी० टन	***	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***	***
कम कीमत पर बिक्री	% श्रेणी	10 - 20	10 - 20
यूएसए			
पहुंच कीमत	प्रति मी० टन	34,966	516.99
क्षतिरहित कीमत (एनआईपी)	प्रति मी० टन	***	***
कम कीमत पर बिक्री	प्रति मी० टन	***	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***	***
कम कीमत पर बिक्री	% श्रेणी	70 - 80	70 - 80

72. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से कम कीमत और बिक्री सकारात्मक है। तथापि, कम कीमत पर बिक्री और कीमत कटौती की तालिका को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह देखा जा सकता है कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एनआईपी से अधिक है। इस तथ्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत जांच की अवधि के बड़े भाग के लिए बंदी के प्रभाव के कारण जांच की अवधि के दौरान अत्यधिक अधिक है। यह भी दर्शाता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान उनके उत्पाद के लिए उचित कीमत वसूलने से नहीं रोका।

एच.6. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड :-

73. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में यह अपेक्षा है कि क्षति निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच करना शामिल होगा। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादों के पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के

संबंध में पाटनरोधी नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में विक्रियों में वास्तविक और संभावित गिरावट, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता का उपयोग, घरेलू मूल्यों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन की मार्जिन की मात्रा, नगद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, माल सूचियों, रोजगार, मजदूरियां, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की सामर्थ्य सहित सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और उद्योग की स्थिति संबंधी सूचकांकों का एक वस्तुपरक और निष्पक्ष आकलन करना शामिल होना चाहिए।

74. हितवद्ध पक्षकारों के द्वारा अपने निवेदनों में दिए विभिन्न तथ्यों और दिये गये तर्कों में ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने क्षति संबंधी पैरामीटरों की वस्तुपरक जांच की है।

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

75. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया है:-

विवरण	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	पीओआई-ए
क्षमता कुल	मी० टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन-कुल	मी० टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	101	36
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	101	36
घरेलू बिक्री	मी० टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	99	42

76. उपरोक्त सारणी से यह नोट किया जाता है कि -

- क) घरेलू उद्योग की क्षमता वर्ष 2013-14 से स्थिर रही है।
- ख) घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में वर्ष 2015-16 तक सुधार हुआ है और इस तथ्य के कारण कि जांच की अवधि के दौरान बड़े भाग के लिए घरेलू उद्योग प्रचालनात्मक नहीं था, पीओआई (ए) के दौरान गिरावट हुई।
- ग) घरेलू उद्योग के उत्पादन में 2015-16 तक सुधार हुआ और पीओआई (ए) के दौरान इस वजह से गिरावट हुई है कि घरेलू उद्योग पीओआई की अधिकांश अवधि में प्रचालन में नहीं था

ख. लाभप्रदता, निवेश पर आय और नगद लाभ

77. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय, और नगद लाभ का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया है -

विवरण	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	पीओआई-ए
लाभ/ हानि	रूपये/मी० टन	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	137	102	-256
लाभ/हानि	रूपये (लाख)	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	134	101	-109
ब्याज और कर के पहले लाभ	रूपये (लाख)	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	106	6
नगद लाभ	रूपये (लाख)	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	86	-56
नियोजित पूंजी पर	%	***	***	***	***

आय					
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	75	1.4

78. उपरोक्त सारणी से यह नोट किया जाता है कि -

- क) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता वर्ष 2015-16 तक अच्छी रही है तथापि, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई और पीओआई (ए) के दौरान हानियां हुई।
- ख) इसी प्रकार घरेलू उद्योग का व्याज पूर्व लाभ और नगद, लाभ वर्ष 2015-16 तक अच्छे रहे हैं, परंतु पीओआई (ए) के दौरान इनमें गिरावट हुई, तथापि, नियोजित पूंजी पर लाभ में संपूर्ण क्षति अवधि में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई और पीओआई (ए) के दौरान अत्यधिक कमी हुई।

ग. रोजगार उत्पादकता और मजदूरी

79. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के रोजगार, उत्पादकता और मजदूरियों का ब्योरा नीचे सारणी में दिया है -

विवरण	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	पीओआई-ए
रोजगार - डीआई	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	98	93
मजदूरी	रूपये (लाख)	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	117	97
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी० टन /सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	102	39
प्रति दिन उत्पादकता	मी० टन /दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	101	36

80. यह नोट किया है कि क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की प्रति दिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता नगण्य परिवर्तन सहित स्थिर रही और इसमें पीओआई (ए) के दौरान अत्यधिक गिरावट हुई है। यह प्रमुख रूप से इस तथ्य के कारण है कि जांच की अवधि के बड़े भाग के लिए घरेलू उद्योग प्रचालनात्मक नहीं था।

घ. माल - सूचियां

81. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की माल सूची की स्थिति नीचे सारणी में दी गई है-

विवरण	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	पीओआई-ए
औसत स्टॉक	मी० टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	131	72

82. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की माल सूचियों में पीओआई (ए) के दौरान गिरावट हुई है।

ड. विकास

83. घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्रियां, लाभप्रदता 2015-16 तक स्थिर रही है और उसके बाद जांच की अवधि (क) के दौरान उसमें तेजी से गिरावट आई है। तथापि, नियोजित पूंजी पर आय में पूरी क्षति अवधि में गिरावट की प्रवृत्ति रही और जांच की अवधि (क) के दौरान अत्यधिक कमी आई।

विवरण (वर्ष दर वर्ष)	2013-14	2014-15	2015-16	पीओआई-ए
उत्पादन		-1%	2%	-64%
क्षमता उपयोग		-1%	2%	-64%
घरेलू बिक्रियां		-2%	1%	-57%

बिक्री की लागत		-1%	-1%	57%
विक्रय मूल्य		4%	-5%	3%
लाभ/हानि		37%	-25%	-350%
निवेश पर लाभ		-8%	-19%	-95%

च. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

84. घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि उनकी वर्तमान वित्तीय स्थिति नये निवेश के लिए पूंजी जुटाने हेतु उन्हें अनुमति नहीं देती है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति उसके अपने अंतरनिर्हित कारणों से बिगड़ी है और संबद्ध देशों से आने वाले आयातों से उसका कोई संबंध नहीं है।

छ. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

85. घरेलू उद्योग अपने विक्रय मूल्य को एक सीमा में कुछ हद तक बनाये रखने में समर्थ है। तथापि, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में जांच की अवधि (क) के दौरान जांच की अवधि (क) के प्रमुख भाग के लिए बंदी के प्रभाव के कारण काफी बढ़ोतरी हुई है। यह देखा जा सकता है कि जांच की अवधि (क) के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एनआईपी से अधिक है।

ज. वास्तविक क्षति का खतरा

86. नियमावली के अनुबंध-II (vii) के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मापदण्डों पर नियम में निम्नानुसार उल्लेख है: -

- (vii) वास्तविक क्षति की आशंका का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होगा और न कि आरोप, निराधार कल्पना या सुदूर संभावना पर। परिस्थितियों में परिवर्तन जिनसे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिनमें पाटन से क्षति होगी, स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए और असन्नवर्ती होने चाहिए। वास्तविक क्षति के खतरे की मौजूदगी के संबंध में निर्धारण करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे कारकों पर विचार करेंगे और;

- (क) भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की अधिक दर जिससे आयातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो।
- (ख) निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य, या आसन्नवर्ती, पर्याप्त वृद्धि जिनसे किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में पाटित निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो।
- (ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर हो रहे हैं, जिनसे घरेलू कीमतों पर काफी हासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और इनसे अधिक उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है तथा
- (घ) उस वस्तु की वस्तु सूची की जांच की जा रही हो।"

87. वास्तविक क्षति की चेतावनी एक ऐसी स्थिति होती है, जिसमें घरेलू उद्योग को क्षति अवधि के दौरान क्षति न हुई हो, अपितु, घरेलू उद्योग को क्षति उस स्थिति में सन्निकट होती है; जब यदि वर्तमान परिस्थितियां जारी रहती हों। वास्तविक क्षति की चेतावनी का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होना चाहिए और न कि आरोप, अटकल बाजियों, कल्पना अथवा दूरस्थ संभावना पर आधारित हो।

88. वास्तविक क्षति की चेतावनी के संबंध में प्राधिकारी नीचे दिए अनुसार नोट करते हैं -

- (क) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में पूर्णतः तथा भारत में उत्पादन और, खपत के संदर्भ में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट होने की वजह से संबद्ध देशों से आयातों में बढ़ोतरी करना अनिवार्य हो गया था।
- (ख) इसके अलावा, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों की क्षमता के ब्यौरे की जांच की है और यह नोट किया है कि किसी सहयोगी उत्पादक के द्वारा क्षमता में पर्याप्त वृद्धि नहीं की गई है।
- (ग) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों की माल सूची की जांच की है और यह नोट किया है कि उनमें से किसी के पास कोई पर्याप्त माल सूची नहीं है।

ज.1. क्षति और क्षति मार्जिन की मात्रा :-

89. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित मूल्य का निर्धारण किया है। जांच अवधि के लिए उत्पादन की लागत संबंधी सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपना करके विचाराधीन उत्पाद के एनआईपी का निर्धारण किया गया है। जांच अवधि के लिए उत्पादन की लागत संबंधी सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपना करके विचाराधीन उत्पाद के एनआईपी का निर्धारण किया गया है। घरेलू उद्योग का एनआईपी निर्धारित किया गया है और क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए प्रत्येक संबद्ध देश से पहुंच मूल्य की तुलना करने के लिए इस पर विचार किया गया है। एनआईपी का निर्धारण करने के लिए क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के द्वारा कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग के बारे में विचार किया गया है। यह कार्रवाई उपयोगिताओं के बारे में की गई है। क्षति अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग के बारे में विचार किया गया है। सर्वोत्तम क्षमता उपयोग पर विचार करते हुए पीओआई में उत्पादन गणना की गई है और इसी उत्पादन के बारे में प्रति यूनिट निर्धारित लागत प्राप्त करने हेतु विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन की लागत पर कोई भी असाधारण अथवा अनावर्ती व्यय नहीं लिया गया था। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III में यथा निर्धारित एनआईपी प्राप्त करने के लिए विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निबल स्थायी परिसंपत्तियों जमा औसत चल पूंजी) पर उचित लाभ (पूर्व कर 22 प्रतिशत की दर) की अनुमति थी। क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्यों के साथ ऐसे निर्धारित क्षति रहित मूल्य की तुलना की गई है, जो नीचे दिए अनुसार हैं :-

क्र. सं.	उत्पादक देश	उत्पादक	निर्यातक	एनआईपी (अमेरिकी डॉलर/मी० टन)	पहुंच मूल्य (अमेरिकी डॉलर/मी० टन)	क्षति मार्जिन (अमेरिकी डॉलर/मी० टन)	क्षति मार्जिन %	रेंज
1.	चीन जन. गण.	क. मै० शाउगुआंग मेलिन पेपर कंपनी लि० ख. मै० शानडांग केनमिंग पेपर होल्लिंग्स लि०	मै० चेनमिंग (एचके) लि०	***	***	***	***	20-30
2.	चीन जन. गण.	गोल्ड ईस्ट ट्रेडिंग (हांगकांग) कंपनी लि०	गोल्ड ईस्ट ट्रेडिंग (हांगकांग) कंपनी लि०	***	***	***	***	40-50
3.	चीन जन. गण.	अन्य सभी	अन्य सभी	***	***	***	***	40-50
4.	यूरोपियन संघ	क. सप्पी अल्फीलड जीएमबीएच ख. सप्पी एहिनगेन जीएमबीएच ग. सप्पी ग्रेटकार्न जीएमबीएच घ. सप्पी फिनलैंड ऑपरेशंस ओवाई (किरकनेमी) ड. सप्पी	क. सप्पी यूरोप एसए ख. पीजी पर कंपनी लि०	***	***	***	***	15-25

		लानाकेन एनबी च. सप्पी मास्ट्रिच बीवी छ. सप्पी स्टॉकस्टेड जीएमबीएच						
5.	यूरोपियन संघ	क. मै० यूपीएम कंम्यूनिकेशन पेपर्स ओवाई ख. मै० यूपीएम स्पेशल्टी पेपर्स ओवाई ग. यूपीएम जीएमबीएच	मै० यूपीएम सेल्स ओवाई	***	***	***	***	0-5
6.	यूरोपियन संघ	अन्य सभी	अन्य सभी	***	***	***	***	50-60
7.	यूएसए	सभी	सभी	***	***	***	***	25-35

(ट) बिना आरोप विश्लेषण

90. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ पाटन आयातों के अलावा किन्हीं ज्ञात कारणों की जांच करनी होती है, जो उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं ; ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति को पाटन आयातों के लिए उत्तरदायी न ठहराया जा सके। इस संबंध में जो कारक प्रासंगिक हो सकते हैं उनमें, अन्य बातों के साथ-साथ पाटन मूल्यों पर बेचे न गए आयातों की मात्रा और मूल्य, मांग में कमी और खपत के पैटर्न में बदलाव, व्यापार संबंधी प्रतिबंधित कार्य और विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच में प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और निर्यात निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है। इस बात की नीचे जांच की गई है कि क्या पाटन आयातों के अलावा अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हैं।

(क) अन्य देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य :-

91. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि गैर-संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का पर्याप्त आयात हुआ था।

(ख) निर्यात निष्पादन

92. प्राधिकारी ने केवल उसका क्षति विश्लेषण करने के लिए ही घरेलू प्रचालनों के आंकड़ों पर विचार किया है।

(ग) प्रौद्योगिकी का विकास

93. घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले कारक के रूप में प्रौद्योगिकी में विकास के संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई मुद्दा नहीं उठाया है।

(घ) कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन

94. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं के द्वारा उत्पादित और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों के निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने के संभावित कारक नहीं हो सकते हैं।

(ड.) व्यापार संबंधी प्रतिबंधात्मक कार्य और विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच में प्रतिस्पर्धा

95. संबद्ध वस्तुओं का आयात किसी भी तरीके से प्रतिबंधित नहीं होता है और इनका देश में स्वतंत्र रूप से आयात किया जाता है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह सुझाव देने के लिए कोई प्रमाण नहीं दिया है कि विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच में प्रतिस्पर्धा की शर्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है।

(छ) मांग में कमी और खपत की पद्धति में बदलाव

96. यह नोट किया है कि संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में समनुरूप बढ़ोतरी हुई है।
97. प्राधिकारी ने मै० जेके पेपर्स लि० के निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किए गए निवेदनों को नोट किया है। इसलिए प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से पाटन आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच में कारणात्मक संबंध के बारे में स्पष्ट निष्कर्ष हेतु मै० जेके पेपर्स लि० के प्रमुख आर्थिक पैरामीटरों की जांच करने के लिए प्रासंगिक सूचना

प्रस्तुत करने हेतु याचिकाकर्ता से अनुरोध किया था। प्राधिकारी ने मै० जेके पेपर्स लि० के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर प्रमुख क्षति पैरामीटरों का विश्लेषण किया है।

ट.1. जेके पेपर्स लि० पर पर पाटन आयातों का मूल्य प्रभाव

(क) कीमत कटौती

98. कीमत कटौती संबंधी विश्लेषण के लिए जेके पेपर्स लि० के निवल विक्रय मूल्य की संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ तुलना की गई है। जेके पेपर्स लि० के निवल विक्रय मूल्य की गणना करते समय सभी करों, छूटों, कटौतियों और कमीशन को कम कर दिया गया है और कारखानागत स्तर पर बिक्री वसूली का पाटन आयातों के पहुंच मूल्य के साथ तुलना की गई है। तदनुसार, संबद्ध देशों से पाटन आयातों के मूल्य में कमी संबंधी प्रभाव नीचे दिए अनुसार हैं :-

विवरण	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	पीओआई-ए
चीन जन. गण.					
आयातों की पहुंच कीमत	रूपये/मी० टन	50,910	50,014	50,964	49,138
निवल बिक्री कीमत	रूपये/मी० टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	रूपये/मी० टन	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
रेंज		0 – (10)	0 – 10	0 – (10)	0 – 10
ई.यू.					
आयातों की पहुंच कीमत	रूपये/मी० टन	57,508	55,844	54,629	52,864
निवल बिक्री कीमत	रूपये/मी० टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	रूपये/मी० टन	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
श्रेणी		(10) – (20)	0 – (10)	(10) – (20)	0 – (10)
यू.एस.ए.					
आयातों की पहुंच कीमत	रूपये/मी० टन	31,765	32,106	33,948	34,966
निवल बिक्री कीमत	रूपये/मी० टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	रूपये/मी० टन	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
रेंज		50 – 60	50 - 60	40 - 50	40 - 50

99. पूर्वोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि क्षति जांच अवधि और पीओआई के दौरान ईयू से मूल्य में कमी नकारात्मक है, जबकि चीन गणराज्य और यूएसए से मूल्य में कमी पीओआई (ए) के दौरान सकारात्मक है।

(ख) कीमत ह्रास और न्यूनीकरण प्रतिबंध और दबाव

100. यह निर्धारित करने के लिए, क्या पाटन आयातों से घरेलू मूल्य पर दबाव पड़ रहा है और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी हद तक मूल्य को प्रतिबंधित करना है अथवा मूल्य में बढ़ोतरीयों को रोकना है, जो सामान्य अवधि में अन्यथा हुई होगी, क्षति अवधि में लागतों और मूल्यों में परिवर्तनों की नीचे दिये अनुसार तुलना की गई थी:-

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	पीओआई(ए)
बिक्री की लागत	रूपये/मी० टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	98	154
विक्रय कीमत	रूपये/मी० टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	99	102
पहुंच मूल्य	रूपये/मी० टन	47,533	47,781	47,725	46,700
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	100	98

101. उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि (क) के दौरान बिक्री की लागत में 22 सूचकांक तक गिरावट हुई है, जबकि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि (क) के दौरान विक्रय मूल्य में एक सूचकांक तक बढ़ोतरी हुई है। आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि (क) के दौरान पहुंच मूल्य में 2 सूचकांक तक की गिरावट आई है। इस प्रकार, संबद्ध देशों से आयातों के कारण जे के पेपर लिमिटेड की बिक्री पर कोई कीमत न्यूनीकरण अथवा ह्रासमान प्रभाव नहीं पड़ा।

ट.2. मै० जेके पेपर्स लि० के आर्थिक पैरामीटर

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

102. जेके पेपर्स लि० की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियां क्षति अवधि के दौरान निम्नलिखित सारणी में दी हैं :-

विवरण	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	पीओआई=ए
क्षमता कुल	मी० टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन कुल	मी० टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	116	125
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	116	125
घरेलू बिक्रियां	मी० टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	115	122

103. उपरोक्त सारणी से यह नोट किया है कि -

- जेके पेपर्स लि० की क्षमता वर्ष 2013-14 से स्थिर रही है।
- जेके पेपर्स लि० के क्षमता उपयोग में क्षति जांच अवधि के दौरान सुधार हुआ है और पीओआई (ए) के दौरान अपनी उच्चतम सीमा (***) पर था।
- संपूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान तथा पीओआई (ए) के दौरान जेके पेपर्स लि० के उत्पादन और घरेलू बिक्रियों में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है।

ख. लाभप्रदता, निवेश पर लाभ और नगद लाभ

104. क्षति अवधि में जेके पेपर्स लि० की लाभप्रदता, निवेश पर लाभ, और नगद लाभ का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया है –

विवरण	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	पीओआई -ए
ब्याज एवं कर पूर्व लाभ	लाख रूपए	(***)	(***)	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-49	7	31
कर पूर्व लाभ	लाख रूपए	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-77	-31	-12
नकद लाभ	लाख रूपए	(***)	(***)	(***)	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-79	-11	19
नियोजित पूंजी पर आय	%	(***)	(***)	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-63	11	52

105. उपरोक्त सारणी से यह नोट किया है कि –

- क) जेके पेपर्स लि० की लाभप्रदता में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई (ए) के दौरान सुधार हुआ है।
 ख) इसी तरह, नकद लाभों और आरओसीई में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई (ए) के दौरान पर्याप्त सुधार हुआ है।

ग. रोजगार और उत्पादकता

106. क्षति अवधि में जेके पेपर्स लि० का रोजगार और उत्पादकता का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया है –

विवरण	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	पीओआई-ए
रोजगार	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	98	93
प्रति व्यक्ति उत्पादकता	मी.ट. /सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	119	134
प्रति दिन उत्पादकता	मी०/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	116	125

107. यह नोट किया है कि प्रति दिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई (ए) के दौरान काफी सुधार हुआ है।

घ. माल – सूचियां

108. क्षति अवधि में जेके पेपर्स लि० की माल सूची की स्थिति नीचे सारणी में दी है –

विवरण	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	पीओआई -ए
औसत स्टॉक	मी० टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	147	212	249

109. यह नोट किया है कि जेके पेपर्स लि० की माल सूचियों में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई (ए) के दौरान बढ़ोतरी हुई है।

ट.3 कारणात्मक संपर्क संबंधी निष्कर्ष

110. प्राधिकारी नीचे दिए अनुसार नोट करते हैं कि –

- क) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में पूर्णतः तथा भारत में उत्पादन और खपत के संदर्भ में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट होने की वजह से संबद्ध देशों से आयातों में बढ़ोतरी करना अनिवार्य हो गया था।
- ख) बीजीपीपीएल के मात्रा संबंधी मापदंडों के बारे में यह नोट किया है कि क्षमता उपयोग, उत्पादन और घरेलू बिक्रियों में क्षति अवधि के दौरान सुधार हुआ है और पीओआई के दौरान एक यथेष्ट अवधि के लिए संयंत्र के बंद हो जाने की वजह से पीओआई के दौरान इनमें गिरावट आयी। दूसरी ओर जे के पेपर लिमिटेड के क्षमता उपयोग, उत्पादन और घरेलू बिक्री में जांच की अवधि (क) के दौरान सुधार हुआ है।
- (ग) घरेलू उद्योग का ब्याज पूर्व लाभ और नकद लाभ 2015-16 तक स्थिर रहा है और जांच की अवधि (क) के दौरान उसमें गिरावट आई है। दूसरी ओर जे के पेपर लिमिटेड के ब्याज पूर्व लाभ और नकद लाभ में जांच की अवधि (क) के दौरान सुधार हुआ है।
- घ) बीजीपीपीएल का विक्रय मूल्य वर्ष 2015-16 तक बिक्रियों की लागत से अधिक रहा है। तथापि, विक्रय मूल्य पीओआई (ए) के दौरान बिक्रियों की लागत से कम है। वर्ष 2015-16 की तुलना में पीओआई (ए) के दौरान बिक्रियों की लागत में 56 सूचकांक की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी ओर जे के पेपर लिमिटेड की बिक्री लागत जांच की अवधि (क) के दौरान कम हुई है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बी जी पी पी एल की बिक्री लागत जांच की अवधि के प्रमुख भाग के लिए उसकी बंदी के कारण जांच की अवधि (क) के दौरान अत्यधिक बढ़ी है।
- ड.) संबद्ध देशों से बीजीपीपीएल के संबंध में मूल्य में कमी जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक है।
- च) क्षति जांच अवधि और पीओआई के दौरान ईयू से जेके पेपर के संबंध में मूल्य में कमी नकारात्मक है और चीन जन. गण. तथा यूएसए से मूल्य में कमी पीओआई के दौरान सकारात्मक है।
- छ) जांच की अवधि (क) के दौरान बी जी पी पी एल की बिक्री कीमत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एनआईपी से अधिक है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि संबद्ध देशों के पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान उनके उत्पाद के लिए उचित कीमत वसूलने से नहीं रोका।
- ज) बी जी पी पी एल के उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और लाभप्रदता में गिरावट स्पष्ट रूप से उसके अंतर्निहित कारकों के कारण है और संबद्ध देशों से पाटित आयातों से उसका कोई सह-संबंध नहीं है।

ट. प्रकटन के पश्चात की टिप्पणियां

111. हितबद्ध पक्षों से प्रकटन के पश्चात के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। उनमें उठाए गए अधिकांश मुद्दों का प्राधिकारी द्वारा पहले ही प्रकटन विवरण में समाधान कर दिया गया है। हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन पश्चात की टिप्पणियां जिनका पहले समाधान नहीं किया गया है, उनकी उपयुक्त सीमा तक नीचे जांच की गई है।

ट 1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

112. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन के पश्चात निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं :

- (क) 80 जीएसएम से कम की संबद्ध वस्तु को जांच के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव है। याचिकाकर्ता इस अपवर्जन से कभी भी सहमत नहीं थे। ऐसा घरेलू उद्योग को उसके हितों की रक्षा करने का अवसर दिए बिना और रिकॉर्ड में ऐसी सामग्री रखे बिना किया गया है, जो यह दर्शाती होती कि उत्पाद रेंज का उत्पादन याचिकाकर्ता नहीं करता है। याचिकाकर्ता के उत्पादन का अधिकांश हिस्सा अपवर्जन की जाने वाली प्रस्तावित उत्पाद रेंज में है।
- (ख) उत्पाद रेंज को बाहर रखने का कार्य पूर्ववर्ती जांच के आधार पर किया गया है जबकि उस जांच के तथ्य वर्तमान जांच से बिल्कुल अलग थे। अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा रिकॉर्ड में प्रद्वन्न रूप से रखी गई ऐसी भ्रामक सूचना के आधार पर प्रस्तावित अपवर्जन अवैध है और इससे इस संबंध में घरेलू उद्योग की रक्षा का अधिकार छीन लिया गया है।
- (ग) याचिकाकर्ता कंपनी ने न तो संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध वस्तु के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित हैं। याचिकाकर्ता योग्यता संबंधी अपेक्षा को पूरा करते हैं और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) और नियम (3) के अनुसार घरेलू उद्योग है।
- (घ) जे के पेपर की पूरी सूचना पर चार करने के बावजूद प्राधिकारी जेके पेपर को घरेलू उद्योग के रूप में पात्र मानने की स्थिति के संबंध में मौन रहे हैं, इसका प्रकटन किया जाना चाहिए।

- (ड.) प्रशनावली के उत्तर के सार्वजनिक अंश में सूचना उपलब्ध नहीं कराकर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है। निर्यातक, गोपनीयता का दावा करने के लिए पर्याप्त औचित्य और/या तर्क बताने में विफल रहे हैं।
- (च) चीन और यूएसए के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना उचित है। तथापि, प्राधिकारी ने संबंधित पक्षों की सूचना के अप्रकटन और गोल्ड ईस्ट ग्रुप, शेंनडोंग पेपर ग्रुप, सप्पी और यूपीएम पेपर ग्रुप्स के लिए अधूरी मूल्य श्रृंखला संबंधी अनुरोधों की अनदेखी की है। पाटन मार्जिन को पुनः निर्धारित किया जाए और इस बात पर भी विचार किया जाए कि भारत में ईयू से आयातों का अधिकांश हिस्सा पाटित कीमतों पर था।
- (छ) ई यू से पाटित और अपाटित आयातों को अलग करने के बाद भी पाटित आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से आयातों में भारी वृद्धि हुई है। उत्पादन को निलंबित करने से आयात आवश्यक हो गए परंतु किसी भी तरह से इसका अर्थ पाटित कीमतों पर या इतनी मात्रा में आयात करना नहीं था। घरेलू उद्योग के कम उत्पादन के बाद भी ऐसे आयातों के कारण कम कीमत पर बिक्री करनी पड़ी है।
- (ज) पीओआई में आयात कीमतों में भारी गिरावट आई है जबकि कच्ची सामग्री की लागत में संगत गिरावट नहीं हुई जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- (झ) संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई जबकि घरेलू उद्योग के हिस्से में गिरावट आई। प्रस्तुत की गई संशोधित सूचना से पता चलता है कि यदि पीओआई को 2015-16 में घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त क्षमता उपयोग के स्तरों के आधार पर भी समायोजित किया जाए तो भी कीमतों में गिरावट के साथ-साथ पूरी क्षति अवधि में आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। मांग आपूर्ति के अंतर से पाटन न्यायसंगत नहीं हो जाता है।
- (ट) आयातों की पहुंच कीमत में कच्ची सामग्री की लागत में कमी के बिना गिरावट आई है। यद्यपि बिक्री लागत में वृद्धि हुई, तथापि, बिक्री कीमत में गिरावट आई। क्षति अवधि के दौरान कटौती के स्तर में वृद्धि हुई है।
- (ठ) यदि बिक्री की ईष्टतम लागत पर भी विचार किया जाए तो वह घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत पर अधिक होगा। आयातों की पहुंच कीमत बिक्री की ईष्टतम लागत से भी काफी कम बनी रही है। आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनकारी और ह्रासकारी प्रभाव पड़ा है।
- (ड) आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में भी भारी मार्जिन तक कमी हुई है।
- (ढ) पीओआई में घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट आई जिसके परिणामस्वरूप बिक्री और क्षमता उपयोग में कमी आई। तब भी कम कीमत के आयातों के कारण बाजार में कीमतों में गिरावट आई जबकि घरेलू उद्योग के पास बिक्री के लिए काफी कम मात्रा थी।
- (ण) याचिकाकर्ता को उत्पादन से कम स्तर से नुकसान हुआ है। उत्पादों की बिक्री पीओआई के सभी महीनों में हुई थी। जब उत्पादन अधिक भी था तब भी आयातों के कारण सकारात्मक पाटन और क्षति मार्जिन थे और घरेलू उद्योग के उत्पादन करने या उत्पादन नहीं करने पर भी निर्यातकों के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं हुआ।
- (त) यदि घरेलू उद्योग ने इस अवधि के दौरान ऐसे उत्पाद मिश्रण जो उन्हें अधिक आय देता है, का उत्पादन नहीं किया होता, तो घाटे और अधिक होते।
- (थ) पीओआई में मालसूची में गिरावट आई परंतु वह घरेलू उद्योग के कम हुए उत्पादन को देखते हुए काफी अधिक बनी रही है।
- (द) पीओआई में घाटे अत्यधिक थे और पीबीआईटी में भारी गिरावट आई। नकद लाभ, ऋणात्मक थे और आरओआई घटकर मुश्किल से सकारात्मक स्तर पर रही। विगत में उत्पादन के ईष्टतम स्तरों को मानते हुए और उत्पाद मिश्रण को 2015-16 में बनाए रखते हुए भी घाटे ही हुए होते।
- (ध) निर्धारित पाटन मार्जिन क्षति मार्जिन से अधिक है जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित उचित कीमत विदेशी उत्पादकों की बिक्री कीमत से काफी अधिक है।
- (न) घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी वास्तविक उत्पादन के स्तर पर नहीं है बल्कि ईष्टतम उत्पादन स्तर पर है। इससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग विदेशी उत्पादकों से कम कुशल नहीं है और यद्यपि, वह वित्तीय घाटे उठा रहा है, फिर भी विदेशी उत्पादकों ने पाटन का सहारा लिया है।
- (प) जहां तक जेके पेपर के कार्य निष्पादन का संबंध है – जेके पेपर को आधार वर्ष में घाटा हो रहा था जबकि याचिकाकर्ता लाभ में था। जे के पेपर ने धीरे-धीरे अपनी खपत मांग को और कौशल में सुधार किया जिस वजह से उसकी बिक्री लागत में गिरावट आई।
- (फ) बीआईएलटी की उत्पादन लागत जेके पेपर की उत्पादन लागत की तुलना में तब भी कम थी जबकि बीआईएलटी पल्प की खरीद करता है और जेके पेपर अपनी खुद की पल्प का उत्पादन करता है। जब पल्प के कम उत्पादन के कारण जेके पेपर द्वारा उठाए

- गए घाटे के लिए जेके पेपर के कार्य निष्पादन को समायोजित किया जाता है, तो बीआईएलटी की लाभप्रदता जेके पेपर की लाभप्रदता से बेहतर बनी रहेगी।
- (ब) उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में सुधार के संबंध में जेके पेपर ने केवल अपनी पुरानी स्थिति को बहाल किया है। इस कंपनी को अपनी स्थिति का नुकसान केवल नई पल्प मिल के सामने आ रही स्थायित्व की समस्या के कारण हुआ था।
- (भ) रिलायंस को जेके पेपर की वार्षिक रिपोर्टों के उद्धरण में रखा गया है जो दर्शाता है कि नई पल्प मिल ने स्थापना की कठिनाइयों के कारण अपनी लागत को कम किया है। यह केवल एक ऐसा उदाहरण है जहां कंपनी को अपनी लागत स्थिर करने में कुछ समय लगा। इसके अलावा, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट भी आयातों से खतरे के तथ्य को स्वीकार करती है।
- (म) याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादन के निलंबन और जेके पेपर के कागज और बिक्री में सुधार के बावजूद अब भी उसे घाटा हो रहा है और पाटित आयातों के कारण उसे वांछित स्तर से काफी कम आय प्राप्त हो रही है।
- (य) जे के पेपर द्वारा प्रदत्त आंकड़ों को कंपनी से कोई स्पष्टीकरण मांगे बिना सुविधा आधार पर अपनाया/प्रयोग किया गया है। जेके पेपर की लाभप्रदता में उतनी वृद्धि नहीं हुई है जितनी प्रकटन विवरण में सिद्ध की गई है। कंपनी की आरओसीई काफी कम है और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन में कमी के बावजूद मालसूची में भारी वृद्धि हुई है।
- (र) प्राधिकारी ने ब्याज पूर्व लाभ पर विचार किया है जबकि संगत मापदंड कर पूर्व लाभ है। इस संबंध में अपनी पूर्व की परिपाटी को छोड़ना अनुचित है। जेके पेपर का कर पूर्व लाभ घाटों में गिरावट की स्थिति दर्शाता है। ऐसे घाटों में कमी पल्प मिल के स्थिर होने के कारण आई और ऐसे घाटों का प्रभाव पल्प मिल की अस्थिरता के कारण था।
- (ल) प्राधिकारी ने ई यू के लिए कीमत कटौती ऋणात्मक निर्धारित की है क्योंकि उन्होंने याचिका की तुलना में ईयू से आयातों के संबंध में काफी अधिक कीमत पर विचार किया है। ऐसा प्राधिकारी द्वारा भिन्न आंकड़े अपनाए जाने के कारण हुआ है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे अपनाए गए डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों का प्रकटन करें। इसके अलावा जेके पेपर के आंकड़ों पर विचार करते हुए औसत कीमत कटौती सकारात्मक है।
- (व) लागत सूचना पर विचार करने के बावजूद जे के पेपर के लिए एनआईपी निर्धारित नहीं की गई है। याचिकाकर्ता ने जे के पेपर की एनआईपी प्रकटन विवरण में अपनाई गई सूचना के आधार पर निर्धारित की है। यह देखा जाता है कि जे के पेपर की एनआईपी उनकी एनएसआर से काफी अधिक है। क्षति मार्जिन काफी उच्च है और जे के पेपर की एनआईपी याचिकाकर्ता की एनआईपी से तुलनीय है।
- (श) ऐसी स्थिति में जहां एक प्रमुख उत्पादक ने उत्पादन बंद कर दिया है, यह असामान्य है कि दूसरे उत्पादक की मालसूची के स्तर में वृद्धि हुई है। बीआई के आंकड़ों और विदेशी उत्पादक के आंकड़ों का सत्यापन किया गया था, परंतु जे के पेपर के लिए सत्यापन नहीं किया गया है। प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना जेके पेपर द्वारा प्रपत्रों के आधार पर दी गई थी।
- (ष) आयातों के खतरे के संबंध में आयात मात्राओं में कीमतों में गिरावट के कारण भारी वृद्धि हुई है जबकि कच्ची सामग्री की लागत में कमी नहीं आई है। ऐसे आयातों से कीमत कटौती हुई। इसके अलावा, मांग-पूर्ति के अंतर से अनुचित कीमत के आयात आवश्यक नहीं हो जाते हैं जैसा कि इस जांच में हुआ है। घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित एनआईपी उनके एनएसआर से काफी अधिक है।
- (स) यदि कंपनी बंद होने के समायोजन पर भी विचार किया जाए तब भी आयातों में वृद्धि हुई है। इसके साथ, संबद्ध देशों में मांग में गिरावट आगे और वास्तविक क्षति होने के खतरे को दर्शाती है। अकेले चीन में मांग में कमी पूरी भारतीय मांग से काफी अधिक है।
- (ह) प्राधिकारी के लिए न केवल प्रतिवादी निर्यातकों बल्कि गैर प्रतिवादी निर्यातकों की क्षमताओं का विश्लेषण और जांच करना, अतिरिक्त योजनागत क्षमताओं का विश्लेषण करना और उसके बाद निपटान योग्य क्षमताएं निर्धारित करना अपेक्षित है। चीन में मांग में गिरावट उत्पादन में गिरावट से काफी अधिक है।
- (क्ष) ईयू और यूएसए द्वारा चीन के विरुद्ध लगाए गए उपायों से उसका निर्यात बाजार और घट गया है। उसके साथ अब आधिक्य क्षमताओं का तथ्य भारत में आयातों में वृद्धि की आशंका सिद्ध करता है।
- (त्र) ईयू में भारी क्षमताएं हैं जो उनकी अपनी मांग से काफी अधिक हैं जिसके परिणामस्वरूप उच्चतर निर्यात उन्मुखीकरण होता है। अन्यथा भी ईयू, पीयूसी का निवल निर्यातक है क्योंकि वे अपने पास अप्रयुक्त क्षमताओं के बावजूद अपने कुल उत्पादन के लगभग 21 प्रतिशत का निर्यात करते हैं।
- (ज) यूएसए के लिए क्षमता उनकी अपनी मांग से काफी अधिक है जिसमें पहले ही गिरावट आ रही है। अमरीका के कागज उद्योग की लगभग 17 प्रतिशत आय निर्यात बिक्रियों के जरिए आती है जिसमें घटती हुई मांग को देखते हुए आगे और वृद्धि होना निश्चित है।

- (कक) घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट के साथ कीमत कटौती में वृद्धि से आगे और कम कीमत के आयातों के खतरे का संकेत मिलता है। वास्तव में भारतीय उत्पादन में गिरावट से आयात कीमतों में कटौती में कमी आनी चाहिए थी। ऐसी कीमतें घरेलू उद्योग के वास्तविक और मानक स्तर से कम थीं जिससे कीमत ह्रासकारी प्रभाव पड़ा है।
- (खख) चीन की सरकार ने ईसी के जांच परिणाम में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि भारत एक अधिक आकर्षक बाजार है। ईयू और यूएस के उत्पादकों के निर्यातों के लिए भी भारतीय बाजार उनके अपने देश में कम होती हुई मांग और भारत में बढ़ती हुई मांग को देखते हुए काफी आकर्षक है।
- (गग) भारी आयात मात्राओं में वृद्धि को देखते हुए यह मानना सही होगा कि ये उत्पादक अल्पावधि में अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं।
- (घघ) दायर की गई सब्सिडीरोधी याचिका से प्राप्त पीओआई के बाद के आंकड़ों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने उत्पादन में वृद्धि की है और वह बाजार में उत्पाद की बिक्री कर सकता है। परंतु, अब भी उसे कटौती स्तरों का सामना करना पड़ रहा है, उसे अब भी घाटा हो रहा है। लाभ, नकद प्रवाह और निवेश पर आय पहले की तुलना में निचले स्तर पर बने हुए हैं और उन्हें प्राधिकारी द्वारा तर्कसंगत माना गया है। इससे सिद्ध होता है कि बढ़े हुए उत्पादन के बाद उसे लाभ, नकद प्रवाह और निवेश पर आय के कारण घाटा हुआ है और प्रतिकूल कीमत प्रभाव केवल आयातों के कारण है।
- (ङ.ङ.) यदि प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचें कि पाटित आयातों से इतर कोई कारक है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है तो उन्हें ऐसे कारक की पहचान करनी चाहिए और फिर उसके प्रभाव की मात्रा निर्धारित करनी चाहिए तथा डीआई की क्षति संबंधी सूचना के विश्लेषण से पहले उनके आंकड़ों को अलग-अलग करना चाहिए। वर्तमान मामले में प्राधिकारी की सूचना में लाया गया कारक अन्य तथ्यों की वजह से याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादन में कमी किया जाना है। प्राधिकारी ने स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता का उत्पादन अन्य कारकों से प्रभावित हुआ है। उन्हें याचिकाकर्ता के संपूर्ण आंकड़ों पर विचार करना चाहिए, उसे उचित रूप से समायोजित करना चाहिए और तत्पश्चात क्षति विश्लेषण हेतु उन्हें अपनाना चाहिए। आंकड़ों को उत्पादन में हुए घाटे पर विचार करते हुए समायोजित करना अपेक्षित है।
- (चच) प्राधिकारी को ईष्टतम लागत की सूचना दी गई थी परंतु प्राधिकारी द्वारा क्षति विश्लेषण के लिए उन पर विचार नहीं किया गया। इसके अलावा, एनआईपी की गणना के समय प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की कथित अकुशलताओं पर विचार किया है और उत्पादन की मानक लागत निर्धारित की है।
- (छछ) एक बार प्राधिकारी द्वारा क्षमता उपयोग के पूर्ववर्ती स्तर पर विचार करने से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के उत्पादन पर प्रभाव डालने वाले अन्य कारकों के प्रभाव का पूर्णतः समाधान हो गया। उच्चतम प्राप्त क्षमता उपयोग पर विचार करके प्रस्तुत आंकड़ों और उसके बाद उत्पादन, बिक्री, लाभ, नकद प्रवाह और निवेश पर आय के निर्धारण को प्रकटन विवरण में पूर्णतः उपेक्षित किया गया है तथा वास्तविक सूचना पर कारणात्मक सूचना की अपेक्षाओं की अनदेखी करके विचार किया गया है।
- (जज) डब्ल्यूटीओ एडीए में प्रावधान है कि पाटन को क्षति का एकमात्र या उस हद तक प्रमुख कारक होना चाहिए। अब एकमात्र विधिक अपेक्षा यह है कि पाटन घरेलू उद्योग को हुई क्षति के कारणों में से एक होना चाहिए।
- (झझ) कम कीमतों वाले आयातों के कारण घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को कम करने पर बाध्य हुआ है। आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हुई है और वह घरेलू उद्योग की बिक्री लागत तथा बिक्री कीमत से काफी कम है।
- (ट.ट) शुल्क को अम.डा./मी.ट. के रूप में व्यक्त स्थिर राशि (शुल्क का स्थिर रूप) के रूप में ही लगाया जाना चाहिए। शुल्क को इस प्रकार लगाया जाना अम.डॉ./मी.ट. में व्यक्त किया जाना चाहिए।

ट.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

113. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात की गई टिप्पणियां निम्नानुसार हैं :-

- (क) मेकेनिकल कोटेड और क्ले कोटेड क्राफ्ट पेपर को जांच से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा इनका उत्पादन नहीं होता है।
- (ख) प्राधिकारी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्षति निर्धारण के लिए घरेलू उद्योग क भाग के रूप में किन कंपनियों पर विचार किया गया है। यह अस्पष्ट है कि क्या घरेलू उद्योग केवल बीआईएलटी है या अब इसमें जेके पेपरी और शेषस्याही पेपर भी शामिल हैं। पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) को देखते हुए बीआईएलटी इस तथ्य के कारण घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर है कि वह पीओआई के अधिकांश हिस्से में पीयूसी का उत्पादन नहीं कर रहा था, जैसा प्राधिकारी ने बताया है।
- (ग) याचिकाकर्ता द्वारा किए गए गोपनीयता के अत्यधिक दावों पर कोई प्रकटन या निर्धारण नहीं किया गया है न ही इस बात का कोई विस्तृत स्पष्टीकरण है कि कोरिया गणराज्य और इंडोनेशिया को संबद्ध देशों के दायरे से बाहर क्यों रखा गया है।

- (घ) बीआईएलटी के कम उत्पादन, जो स्व आरोपित क्षति का हिस्सा है, को देखते हुए बाजार को यह सुनिश्चित करने के लिए आयातों पर निर्भर रहना होगा कि प्रचालन इष्टतम स्तर पर जारी रहें। आयातों में वृद्धि बीआईएलटी द्वारा की गई बंदी के कारण आवश्यक हो गई जो प्राधिकारी ने माना है।
- (ङ.) याचिकाकर्ता की लागत को बीआईएलटी द्वारा किए गए बंद संयंत्र के कारण काफी बढ़ाया गया है जिसकी वजह से लागत भारत में विनिर्माण लागत को उचित रूप से नहीं दर्शाती है। चूंकि जांच अवधि में लागत एनआईपी की गणना में एक निर्णायक (और सबसे बड़ा) घटक भी होता है, इसलिए परिकल्पित एनआईपी में बाद में वृद्धि हो जाना निश्चित है और इसलिए ऐसी वास्तविक उचित कीमत सटीक या प्रतिनिधि नहीं होगी जो घरेलू उद्योग को किसी कथित क्षति को समाप्त कर सके। प्रशासन व्ययों जो बीआईएलटी द्वारा प्रचालन बंद किए जाने के बाद हुए थे, को बाहर रखने का अनुरोध किया जाता है क्योंकि वे कम उत्पादन और बिक्री मात्रा के कारण अधिक होंगे।
- (च) सहयोगी उत्पादकों के पास कोई खास मालसूची, कोई अधिक अतिरिक्त क्षमता नहीं है और यह कि आयातों की बढ़ी हुई मात्रा घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट के कारण है। इस प्रकार, निष्कर्ष रूप में सिद्ध होता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का कोई खतरा नहीं है।
- (छ) पाटनरोधी नियमावली में अनुबंध II ((V) में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि घरेलू उद्योग को कथित क्षति की मात्रा निर्धारित करते समय पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतों पर विचार करना प्राधिकारी का दायित्व है। बीआईएलटी के संबंध में ऐसा नहीं किया गया है।
- (ज) मै. जे के पेपर लि. के आर्थिक मापदंडों अर्थात् उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, लाभप्रदता, निवेश पर आय, नकद लाभ, रोजगार, उत्पादकता और मालसूचियों सभी में सकारात्मक रुझान रहे हैं। इस प्रकार पता चलता है कि कोई क्षति नहीं हुई है। अतः याचिकाकर्ता (बी आई एल टी) द्वारा उठाई गई क्षति स्व-आरोपित है और ई यू से आयातों और घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। परिणामस्वरूप क्षति मार्जिन को केवल जे के पेपर लिमिटेड के उचित बिक्री कीमत के आधार पर सही ढंग से निर्धारित किया जा सकता है।
- (झ) पाटनरोधी कानून की व्यवस्था को किसी ऐसी कंपनी के संरक्षण हेतु प्रयोग नहीं किया जा सकता है जिसने संबद्ध आयातों से पूरी तरह अलग कारणों की वजह से (संयंत्र के बंद होने के कारण) क्षति उठाई हो, जैसा कि इस तथ्य से पुष्ट होता है कि अन्य स्थानीय उत्पादक अच्छा कर रहे हैं।
- (ट) पाटित आयातों द्वारा हुई क्षति के अभाव में पाटनरोधी शुल्क को लगाया जाना भारतीय उद्योग के समग्र हित में नहीं हो सकता है।
- (ठ) घरेलू उत्पादक अर्थात् जे के पेपर का कार्य निष्पादन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बीआईएलटी क्षति अवधि के दौरान नुकसान उठाने वाला एकमात्र उत्पादक है। प्रकटन विवरण के पैरा सं. 108 में ईयू से पीयूसी के आयातों के कारण भारतीय घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है। क्षति केवल बीआईएलटी को हुई है और बी आई एल टी को हुई क्षति स्पष्ट रूप से स्वआरोपित है और ई यू से आयात उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
- (ड) यह अवश्य नोट किया जाए कि अनेक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक केवल उसी कागज का प्रयोग करते हैं जिसे फोरेस्ट स्टीवार्डशिप काउंसिल (एफ एस सी) प्रमाणन दिया गया हो। याचिकाकर्ता ने अपने बंद होने और पुनः खुलने के बाद एफ एस सी प्रमाणित कागज की आपूर्ति बंद कर दी है, इसलिए इस कागज का आयात करना जरूरी हो गया है क्योंकि ग्राहक एफएससी प्रमाणन कागज की मांग करते हैं और अपनी अपेक्षित विशिष्ट जरूरतों के लिए उसे अनिवार्य मानते हैं।
- (ढ) यह अनुरोध किया जाता है कि पीयूसी के दायरे के भीतर आने वाले सभी विभिन्न उत्पाद प्रकारों के भिन्न-भिन्न प्रयोग और भिन्न-भिन्न दरें हैं विशेष रूप से जब उनकी तुलना जीएसएम विनिर्देशनों या मैट/ग्लॉस फिनिशिंग में की जाती है। अतः सभी निर्धारण माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी की पहले की परिपाटी से संगत तुलनाओं के अनुसार समुचित अलग उत्पाद प्रसार के आधार पर ही की जानी चाहिए।
- (ण) डी डी लेबर, सुपरटेक पेपर प्रा.लि., जालक इंटरप्राइजेज, स्टीका लेबल्स, इन्फीनिटी सिक्युरिटी पेपर्स लि. सटे-ऑन पेपर्स प्रा. लि., श्री इंडस्ट्रीज, मदुरा आर्ट्स (इंडिया) प्रा. लि., चोरोमाप्रिंट इंडिया प्रा. लि., साई पैकेजिंग कंपनी और जानस इंटरनेशनल प्रा. लि. ने प्रकटन विवरण जारी होने के बाद पहली बार अनुरोध किए हैं। उन्होंने बताया है कि उनमें से कुछ सीसीके- क्ले कोटेड क्राफ्ट पेपर का प्रयोग लेखन, मुद्रण या ग्राफिक प्रयोजनों के लिए नहीं करती हैं बल्कि रिलीज बेस पेपर के रूप में करते हैं और अन्य वेट स्ट्रेंथ पेपर, जो वन वाइट कोटेड पेपर होता है, तथा जिसमें बीयर और एल्कोहल बोतलों के लिए लेबल हेतु विशेष अपेक्षित विशिष्ट गुणवत्ता होती है, का प्रयोग करते हैं। इस कागज को आम तौर पर और विशेष रूप से बीआईएलटी द्वारा घरेलू तौर पर उत्पादित नहीं किया जाता है। इसे एच एस कोडों 48101300 और 48101900 के अधीन आयात किया जाता है।

उन्होंने आगे बताया कि कोटेड कागजों के लिए एच एस कोडों के रूप में उत्पादों को इस जांच में पीयूसी माना गया है जो इस जांच में विचारित कागजों के दायरों से बाहर हैं। उन्हें पीयूसी माने जाने से उनके लिए और अन्य विनिर्माताओं के लिए काफी कठिनाइयां हो जाएंगी क्योंकि उनका भारत में उत्पादन नहीं होता है।

- (त) यू फ्लैक्स लिमिटेड ने प्रकटन विवरण के जारी होने के बाद पहली बार अनुरोध किए हैं। उन्होंने बताया है कि तरल पैकेजिंग अनुप्रयोग के लिए प्रयुक्त पैकेजिंग पेपर के दो विशेष ग्रेड होते हैं अर्थात् 70-75 जीएसएम (अन कोटेड और कोटेड) और 130-170 जीएसएम (अन कोटेड और कोटेड) इनमें से किसी का भी घरेलू रूप से उत्पादन नहीं होता है।
- (थ) एसएमआई कोटेड प्रोडक्स प्रा. लिमिटेड और दि न्यूज प्रिंट ट्रेडिंड एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉर्पोरेशन लि. ने प्रकटन विवरण के जारी होने के बाद पहली बार अनुरोध किए हैं। उन्होंने बताया है कि याचिका में उल्लिखित एचएसएम कोड उन उत्पादों को कवर करते हैं जो भारत में उत्पादित नहीं किए जाते या अपर्याप्त मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। चूंकि घरेलू विनिर्माता मुद्रण उद्योग की मांग को पूरी तरह से पूरा करने में अक्षम हैं, इसलिए उनका आयात अपेक्षित है।
- (द) आदविक इंटरप्राइजेज ने प्रकटन विवरण के जारी होने के बाद पहली बार अनुरोध किए हैं। उन्होंने बताया है कि बीआईएलटी लगभग पूरी जांच अवधि के दौरान बंद था या सीमित क्षमता के साथ प्रचालनरत था और अन्य विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाना अनुचित है इसलिए ऐसा करने से स्थानीय विनिर्माताओं को स्थानीय ग्राहकों और व्यापारियों का शोषण करने का अवसर मिल जाएगा। अतः ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी से पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं करने का अनुरोध है।
- (ध) श्री अष्ट विनायक पेपर प्रा. लि. ने प्रकटन विवरण के जारी होने के बाद पहली बार अनुरोध किए हैं। उन्होंने बताया है कि भारत में कोटेड पेपर की मासिक मांग लगभग 60000 एमटी है और उत्पादन की स्थानीय क्षमता लगभग 16000 से 20000 एमटी है। इसलिए मांग और उत्पादन के बीच के अंतर को केवल आयातों से पूरा किया जा सकता है।
- (न) गणेश पेपर एजेंसी ने प्रकटन विवरण के जारी होने के बाद पहली बार अनुरोध किए हैं। उन्होंने बताया है कि बी आई एल टी अनेक उत्पादों का उत्पादन करता है और कोटेड पेपर तथा बोर्ड उसका केवल 15-20 प्रतिशत है। अतः उसी क्षति के लिए पेपर और बोर्ड के आयातों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।
- (प) वीनस पेपर कार्प ने प्रकटन विवरण के जारी होने के बाद पहली बार अनुरोध किए हैं। उन्होंने बताया है कि भारत में कागज उद्योग कागज की कुल खपत के लगभग 30 प्रतिशत का उत्पादन करता है और शेष का आयात होता है। भारतीय मिलें जैसे बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लि. खुद अपनी जरूरतों के लिए पल्प का आयात करती हैं। यह कि शुल्क लगाने से कागज और उसके उत्पादों की लागत बढ़ जाएगी और स्थानीय तथा निर्यात व्यापार प्रभावित होगा।
- (फ) जेना एजेंसीज पेपर्स कॉर्प, राज पेपर्स ट्रेडर्स, पूर्णिमा डिस्ट्रीब्यूटर्स और कावेरी इंटरनेशनल ने प्रकटन विवरण के जारी होने के बाद पहली बार अनुरोध किए हैं। उन्होंने बताया है कि हमारे देश में कोटेड पेपर की आपूर्ति हमेशा कम रहती है। भारत में केवल बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और जे के पेपर लिमिटेड इनका विनिर्माण करते हैं। जे के पेपर स्वयं मांग को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर कोटेड पेपर का आयात करता है और बल्लारपुर भी कुछ समय पहले यही कर रहा था। घरेलू उत्पादन बाजार की कुल जरूरत का केवल 35 प्रतिशत है। यद्यपि देश में बाजार वार्षिक आधार पर बढ़ रहा है परंतु उसके साथ उत्पादन में कोई क्षमता निर्माण नहीं हुआ है। शुल्क लागू होने के परिणामस्वरूप उद्योग में बीआईएलटी का एकाधिकार हो जाएगा। इसके परिणामस्वरूप छोटे और मझौले मुद्रकों को भारी घाटा होगा जो कीमत में वृद्धि को झेल नहीं पाएंगे। उनमें से अनेक अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं। अतः पाटनरोधी शुल्क का बुरा प्रभाव पड़ेगा।
- (ब) जुनेजा ट्रेड लिंग ने प्रकटन विवरण के जारी होने के बाद पहली बार अनुरोध किए हैं। उन्होंने बताया है कि घरेलू मिलें आयातित उत्पादों की गुणवत्ता का मुकाबला नहीं कर सकती हैं।
- (भ) सुमत प्रसाद एंड संस ने प्रकटन विवरण के जारी होने के बाद पहली बार अनुरोध किए हैं। उन्होंने बताया है कि चूंकि अध्याय 48 के अधीन कागज में कागज समूह के लगभग 100 उत्पाद शामिल हैं। बीआईएलटी को विभिन्न ग्राम भार 90, 100, 15, 118, 200 130, 150 200, 220, 250 300 के दो कोटेड पेपर उत्पाद मिश्रण के अपने उत्पाद मिश्रण को विशेष रूप से बताना चाहिए जिनका वे मेट तथा ग्लास फिनिश/ रील तथा शीट के लिए अलग से उत्पादन कर रहे हैं। उन्हें उनके तथा अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा एचएसएन कोडों के अनुसार स्पष्ट रूप से उत्पादन बताना चाहिए। प्राधिकारी को याचिका से सही और स्पष्ट सूचना प्राप्त करनी चाहिए कि क्या उनके पास उत्पाद मिश्रण और विभिन्न संयंत्रों तथा विभिन्न उत्पाद मिश्रण के अधीन उत्पाद उपलब्ध हैं। यदि बीआईएलटी अपने उत्पाद एच एस एन कोड को विनिर्दिष्ट करता है तो जे के पेपर आईपीएमए का एकमात्र ऐसा सदस्य रह जाएगा जो जांच के अधीन उत्पाद का विनिर्माता है और उसका नियमित आयातक भी है। गुमराह करने के लिए बीआईएलटी ने केवल 4 अंकीय एचएसएम कोड बताया है जबकि 8 अंकीय कोड नहीं बताया है। अतः शुल्क लागू करने से अनेक लघु और स्थानीय बाजारों को नुकसान होगा जो घरेलू मांग को पूरा करने के लिए मशीन न लगाकर और एकाधिकारी नीति अपनाकर मेक इन इंडिया के सपने के विरुद्ध होगा।

- (म) फेडरेशन आफ पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने प्रकटन विवरण के जारी होने के बाद पहली बार अनुरोध किए हैं। उन्होंने बताया है कि जे के पेपर्स को कोई क्षति नहीं हुई है। यह तथ्य कि आयातों में वृद्धि के बावजूद उसके कार्य निष्पादन में निरंतर सुधार हुआ है, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आयात घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं हैं। इसके विपरीत आयातों से उसकी निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। मांग बढ़ रही है और यदि आपूर्ति केवल घरेलू विनिर्माता से होती है तो यह असमान्य स्थिति होगी। उन्होंने बताया है कि पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग के ऐसे संरक्षण हेतु नहीं लगाया जा सकता जिसकी आर्थिक स्थिति ऐसे कारणों से खराब हुई है जो आयातों से किसी प्रकार से संबंधित नहीं है। जैसा याचिकाकर्ता का स्पष्ट मामला है और लंबे समय से उत्पादन बंद रहने से स्पष्ट है। अतः एकाधिकार नीति के बजाए उचित व्यापार प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।
- (य) एनआईपी निर्धारण में खामियों के होते हुए भी यह अनुरोध किया गया है कि बीजीपीपीएल द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर निर्धारित एन आई पी अविश्वसनीय है। इंडोनेशिया, थाइलैंड और सिंगापुर से अन कोटेड पेपर के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच में बी जी पी पी एल एक आवेदक घरेलू उत्पादक रहा था, परंतु प्राधिकारी ने बी जी पी पीएल को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा था। अंतिम जांच परिणाम के पैरा 11 में प्राधिकारी ने निर्धारित किया कि :
- प्राधिकारी नोट करते हैं कि बी जी पी पी एल अपने आंतरिक कारणों की वजह से पीओआई के अधिकांश हिस्से में संबद्ध वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहा था, अतः बी जी पी पी एल को वर्तमान जांच में आंकलन के लिए घरेलू उद्योग का हिस्सा माना जाना उचित नहीं होगा।
- (र) वर्तमान जांच में पीओआई अनकोटेड पेपर संबंधी पाटनरोधी जांच की पी ओ आई के समान है। प्रतिवादियों ने प्राधिकारी से वर्तमान जांच में संगत नीति अपनाने का अनुरोध किया है तथा बी जी पी पी एल के आंकड़ों के आधार पर प्राधिकारी द्वारा बिक्री लागत और क्षति रहित कीमत पर भरोसा नहीं करने का अनुरोध किया है। कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री और कीमत ह्रास/न्यूनीकरण का परिणामी निर्धारण भी वास्तविक क्षति और कारणात्मक संबंध के निर्धारण हेतु विश्वसनीय नहीं है।
- (ल) किसी भी तरह से यह सिद्ध है कि प्राधिकारी यह निर्धारित करने के लिए कि वास्तविक क्षति हुई है, क्षति मार्जिन की मौजूदगी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। गुजरात उच्च न्यायालय ने निरमा लिमिटेड बनाक भारत संघ (विशेष सिविल आवेदन सं. 16426/2016 और 16427/2016)] में माना है कि:
- 34..... यह नोट किया जाए कि क्षति मार्जिन का निर्धारण करना अपेक्षित है जब निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह निष्कर्ष हो कि वास्तविक क्षति हुई है जिसमें पाटनरोधी शुल्क लगाना अपेक्षित है। जहां पर क्षति मार्जिन के आधार पर पाटनरोधी शुल्क की राशि लगाना निर्भर हो, अतः क्षति मार्जिन का निर्धारण केवल तभी होगा जब निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचें कि निष्कारण उपाय लागू करना अपेक्षित है।* जहां निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह निष्कर्ष हो कि किसी निष्कारण उपाय को लागू करने की जरूरत नहीं है, जैसा वर्तमान मामले में है, वहां क्षति मार्जिन के निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता है।
- (व) बीजीपीपीएल की बिक्री कीमत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति रहित कीमत के या तो बराबर है या उससे अधिक है। बीजीपीपीएल प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति रहित कीमत के स्तर पर अपनी बिक्री कीमत को बनाए रखने में सक्षम रहा है और उसे संबद्ध देशों से आयात के कारण कीमत में कमी नहीं झेलनी पड़ी है।
- (श) प्रकटन विवरण में प्रकट जे के पेपर के आर्थिक मापदंड दर्शाते हैं कि जे के पेपर लिमिटेड को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है। पी ओ आई के दौरान बी जी पी पी एल के कार्य निष्पादन में गिरावट और संबद्ध देशों से आयात के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। यदि बी जी पी पी एल के कार्य निष्पादन में गिरावट के लिए आयात जिम्मेदार होते, तो उससे जे के पेपर लिमिटेड का कार्य निष्पादन भी प्रभावित होता। प्राधिकारी ने स्वयं देखा है कि बी जी पी पी एल के उत्पादन में गिरावट के कारण संबद्ध देशों से आयात में वृद्धि करना आवश्यक हो गया। इस प्रकार प्रतिवादी प्राधिकारी से वास्तविक क्षति के आकलन हेतु पी ओ आई के दौरान बी जी पी पी एल के कार्य निष्पादन को बाहर रखने और वास्तविक क्षति के आकलन के लिए जे के पेपर के कार्य निष्पादन पर विचार करने का अनुरोध करते हैं। इस प्रकार यदि प्राधिकारी वास्तविक क्षति के आकलन के लिए बीजीपीपीएल के आर्थिक मापदंडों पर विचार करते हैं तो प्राधिकारी का यह निष्कर्ष होना चाहिए कि आयातों में वृद्धि और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
- (ष) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की योग्यता, बी जी पीपीएल की लाभप्रदता को प्रभावित करने वाले कारक, घरेलू उद्योग द्वारा उठायी जा रही क्षति और कारणात्मक विश्लेषण से संबंधित प्रतिवादियों के महत्वपूर्ण अनुरोधों को रिकॉर्ड किए बिना प्रकटन विवरण जारी कर दिया। प्रतिवादी अनुरोध करते हैं कि प्रकटन विवरण में नियम 16 के अनुसार प्रतिवादियों को प्रभावी अवसर नहीं दिया गया है। प्रतिवादी ऑयल और नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम वेस्टर्न जेको इंटरनेशनल लि., (2014)9 एस एस सी 263 पर यह कहने के लिए भरोसा करते हैं कि प्राधिकारी सभी पक्षों के तर्कों को सुने बिना कोई निर्णय नहीं दे सकते हैं क्योंकि वह एक अर्धन्यायिक निकाय है। यह निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा और विवेकशील नहीं होने के घातक दोष से भी ग्रस्त होगा।

- (स) प्रकटन विवरण में प्राधिकारी ने प्रतिवादी निर्यातकों की कारखाना द्वार निर्यात कीमत की गणना करते समय गैर वापसी योग्य वैट के लिए समायोजन किए हैं। निर्यात के प्रयोजनार्थ व्यापार प्रक्रिया के अधीन आयातित वस्तुओं पर वैट का कोई इनपुट नहीं है। अतः गैर वापसी योग्य वैट के कारण किए गए समायोजन त्रुटिपूर्ण हैं और उन्हें ठीक किया जाना चाहिए।
- (ह) प्रतिवादी पक्षों ने अनुरोध किया है कि पाटनरोधी संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 2.2 के अनुसार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना व्यापार के सामान्य स्तर पर की जानी चाहिए। तथापि, वर्तमान मामले में समायोजन एनईपी में पैकिंग प्रभारों के लिए किए गए हैं, परंतु परिकलित सामान्य मूल्य की गणना करते समय पैकिंग प्रभार को शामिल किया गया है। यह पाटनरोधी संबंधी डब्ल्यू टी ओ करार का उल्लंघन होगा। अतः प्रतिवादी प्राधिकारी से इसकी पुष्टि करने का अनुरोध करते हैं कि पैकिंग प्रभारों को परिकलित सामान्य मूल्य के निर्धारण के समय ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए।
- (क्ष) बी जी पी पी एल को कंपनी की दो कार्यनीतिक परिसंपत्तियों की बिक्री नहीं होने के कारण नुकसान उठाना पड़ा। परिणामस्वरूप तुलन पत्र की स्थिति में प्रत्याशित सुधार नहीं हो पाया और कंपनी की वित्तीय स्थिति पर और अधिक दबाव पड़ गया। बी जी पी पी एल पर दबाव के अन्य कारण यह हैं कि लकड़ी की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है जो पिछले तीन से चार वर्षों के दौरान दुगुनी से अधिक हो गई है जिसकी वजह से भारतीय कागज उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है तथा जिससे कच्ची सामग्री और ऊर्जा की लागत में वृद्धि हुई है और मुक्त व्यापार करारों (एफटीए) के अधीन पेपर और पेपर बोर्ड को अधिमानी टैरिफ व्यवहार के अधीन रखने की भारत सरकार की नीति से भी इस पर प्रभाव पड़ा है।
- (त्र) कारणात्मक संबंध के लिए संगत कारक संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि है जो घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट, पी ओ आई के दौरान अधिकांश अवधि में संयंत्र के बंद होने के कारण आवश्यक हो गया था। पीओआई के दौरान बी जी पी पी एल के बंद होने के कारण बिक्री लागतों में बिक्री कीमतों से अधिक वृद्धि हो गई। इस प्रकार क्षति और संबद्ध देशों से आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। आवेदक ने कार्य निष्पादन संकेतों को बिगाड़ने के लिए जे के पेपर को जानबूझकर घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा है। याचिकाकर्ता के संयंत्र का बंद होना घाटे की अवधि के साथ-साथ हुआ है। इस प्रकार, पूरे घरेलू उद्योग में अचानक गिरावट आई है जिसका आयातों से कोई लेना-देना नहीं है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

114. प्राधिकारी विभिन्न पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट करते हैं जिनमें से कुछ दोहराए गए हैं और जिनका समाधान प्रकटन विवरण में किया गया था। जो तर्क नए हैं और संगत माने गए हैं, उनके विशेष मुद्दों को उपर्युक्त जांच परिणामों उपयुक्त स्थानों पर लिया गया है। प्राधिकारी ने संगत माने गए और अन्य स्थानों पर हल किए गए हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की निम्नलिखित रूप में जांच की है :

- (i) जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि जांच परिणाम और निष्कर्ष का आधार बनने वाले अनिवार्य तथ्यों को प्राधिकारी को प्रकट करना चाहिए, यह पाया गया है कि प्राधिकारी ने सभी संबंधित पक्षकारों को पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार विचाराधीन सभी अनिवार्य तथ्य प्रकट किए हैं।
- (ii) घरेलू उद्योग के आधार/गठन के लिए स्पष्टता से संबंधित अनुरोधों के संबंध में प्राधिकारी मानते हैं कि याचिका घरेलू उद्योग मै. बी आई एल टी ग्राफिक पेपर प्रोडक्ट्स लि. की ओर से इंडियन पेपर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा दायर की गई थी, जो भारत में संबद्ध समानों का उत्पादक है और वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग है। याचिका में यह उल्लेख किया गया था कि विचाराधीन उत्पाद का एक और ज्ञात घरेलू उत्पादक अर्थात् जे के पेपर लिमिटेड है। जे के पेपर लिमिटेड द्वारा दिए गए आंकड़ों का क्षति और पाटन के बीच कारणात्मक संपर्क के विश्लेषण के सीमित प्रयोजन के लिए प्रयोग किया गया है।
- (iii) जहां तक कोटेड 80 जीएसएम से कम के पेपर को अलग करने के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने स्वयं ही हल्के कोटेड पेपर को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के सत्यापन के दौरान प्राधिकारी ने इस मुद्दे पर विशेष रूप से चर्चा की और यह सूचित किया गया था कि घरेलू उद्योग 75 जीएसएम से कम के दोनों ओर के कोटेड पेपर का उत्पादन नहीं करता। तदनुसार, प्राधिकारी 75 जीएसएम से कम के दोनों ओर के कोटेड पेपर और हल्के कोटेड पेपर को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग करते हैं।
- (iv) जहां तक इस अनुरोध का संबंध है, कि जे के पेपर के लिए एनआईपी निर्धारित नहीं की गई है, प्राधिकारी मानते हैं कि जे के पेपर के लिए एनआईपी का निर्धारण किए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह घरेलू उद्योग का भाग नहीं है, जैसा कि वर्तमान जांच परिणाम में उपयुक्त स्थानों पर उल्लेख किया गया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए एन आई पी का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-3 के अनुसार किया है।

- (v) जहां तक घरेलू उद्योग के इस तर्क का संबंध है, कि जे के पेपर के आंकड़ों और सूचना का प्रयोग सुविधा के आधार पर किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले के तथ्य विशिष्ट हैं क्योंकि याचिकाकर्ता अर्थात् मै. बीआईएलटी ग्राफिक पेपर प्रोडक्ट्स लि. का संयंत्र वर्तमान जांच की अवधि के दौरान एक अवधि के लिए बंद हो गया था। समुचित कारणात्मक संपर्क विश्लेषण करने के लिए जे के पेपर के आंकड़ों का विश्लेषण करना आवश्यक था जोकि विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र दूसरा प्रमुख उत्पादक है। जे के पेपर से स्वयं ही अतिरिक्त सूचना मांगते समय उन्हें यह सूचित किया गया था कि वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों के कारण (जिसमें जांच की अवधि के प्रमुख भाग के लिए याचिकाकर्ता ने बंद कर दिया था) उपयुक्त क्षति एवं कारणात्मक संपर्क विश्लेषण करने के लिए जे के पेपर से सूचना मांगी जा रही थी।
- (vi) जहां तक कई व्यापारियों/आयातकों/प्रयोक्ताओं/एसोसिएशन द्वारा पहली बार विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में प्रकटन के बाद के स्तर पर किए गए देरी से अनुरोधों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन विचाराधीन उत्पादों को अलग करने से संबंधित मुद्दे पहली बार उठाए गए हैं और वह भी प्रकटन पश्चात् टिप्पणियों के बाद के स्तर पर। प्राधिकारी के लिए यह संभव नहीं है कि वे ऐसे सभी विचाराधीन उत्पाद को हटाने से संबंधित मुद्दों की इतनी देरी के स्तर पर नए सिरे से जांच करें। तथापि, प्राधिकारी ने यथासंभव सीमा तक अधिकतर विचाराधीन उत्पादों को हटाने से संबंधित मुद्दों को प्राधिकारी को उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर हल करने का पूरा प्रयास किया है। तदनुसार, प्राधिकारी इलैक्ट्रिकल क्राफ्ट इंशुलेशन पेपर, क्राफ्ट पेपर, क्राफ्ट इंशुलेशन पेपर और इंशुलेटिंग पेपर को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग करते हैं।
- (vii) जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि बी जी पी पी एल के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित क्षति मार्जिन अविश्वसनीय है और उसे जे के पेपर लिमिटेड द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति मार्जिन घरेलू उद्योग के लिए परिकल्पित एन आई पी के आधार पर निर्धारित किया जाना होता है। जैसे कि ऊपर चर्चा की गई बी जी पी पी एल इस मामले में घरेलू उद्योग है और तदनुसार, एन आई पी का निर्धारण बी जी पी पी एल के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-3 के अनुसार किया गया है।
- (viii) जहां तक मै. जे के पेपर लिमिटेड द्वारा दी गई सूचना के सत्यापन के लिए घरेलू उद्योग के तर्क का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में जे के पेपर लिमिटेड द्वारा दिए गए आंकड़ों पर विचार किया है और उनके द्वारा दिए गए आंकड़ों में कोई परिवर्तन नहीं किए गए हैं। प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे प्रत्येक हितबद्ध पक्षकार के आंकड़ों का सत्यापन करें, जहां तक प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकार द्वारा दी गई सूचना से संतुष्ट हैं। जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि कोरिया जन.गण. और इंडोनेशिया को संबद्ध देशों की परिधि से क्यों नहीं हटाया गया, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस मुद्दे को जांच की शुरुआत की अधिसूचना में स्पष्ट कर दिया गया है जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि प्राधिकारी ने प्रथमदृष्टया जांच की अवधि के लिए इंडोनेशिया और कोरिया जन गण से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटन नहीं पाया था।
- (ix) कुछ पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि वे प्रशुल्क मद 48101300 और 48101900 के तहत कोटेड पेपर का आयात करते हैं और घरेलू उद्योग इन प्रशुल्क मदों के तहत आने वाले उत्पादों का विनिर्माण नहीं कर रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत के सीमा प्रशुल्क के तहत ऐसी कोई प्रशुल्क मद (48101300 और 48101900) नहीं है तथा इसीलिए हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों का कोई औचित्य नहीं है।
- (x) जहां तक हितबद्ध पक्षकार के इस तर्क का संबंध है कि व्यापार करने के मामले में कारखानागत निर्यात कीमत के निर्धारण में "गैर वापसी वैट" के निमित्त किया गया समायोजन गलत है, प्राधिकारी उनके द्वारा किए गए अनुरोधों से सहमत नहीं हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर वापसी योग्य वैट के लिए समायोजन व्यापार करने के मामले में भी किया जाना अपेक्षित होता है और उसके लिए फार्मूला एफओबी मूल्य* है (17 प्रतिशत - वापस की गई दर प्रतिशत)* (1- नियोजित वितरण अनुपात प्रतिशत) और इसलिए अपेक्षित ब्यौरे देना संबंधित हितबद्ध पक्षकार पर निर्भर था।
- (xi) सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत दोनों में पैकिंग प्रभारों के समायोजन से संबंधित उठाए गए मुद्दे के संबंध में यह नोट किया जाता है कि उचित तुलना के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई सतत परिपाटी के अनुसार उपयुक्त समायोजन किए गए हैं।
- (xii) घरेलू उद्योग के इस तर्क के संबंध में कि चीन जन.गण. से आयातों के विरुद्ध यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा कोटेड पेपर पर पाटनोधी/प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने से भारत में चीन जन गण से आने वाले काफी आयातों को खतरा पैदा हो गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा ये शुल्क लगाया

जाना कोई नई बात नहीं है और वास्तव में कुछ समय से (संयुक्त राज्य अमरीका में 2010 से और यूरोपीय संघ में 2011 से लागू रहा है) तदनुसार, घरेलू उद्योग के इस अनुरोध में कोई औचित्य नहीं है।

- (xiii) जहां तक जांच के लिए अपनाए गए डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों को प्रकट करने के लिए घरेलू उद्योग के अनुरोध का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि वह सार्वजनिक फाइल में रख दिया गया है और उचित प्रक्रिया अपनाने के बाद सभी हितबद्ध पक्षकार उन्हें देख सकते हैं।

ठ. सिफारिश

115. सीमा प्रशुलक अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली के अधिदेश, विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए संगत अनुरोधों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं :

- (i) संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों में पूर्ण दृष्टि से तथा भारत में उत्पादन में खपत के संबंध में काफी वृद्धि हुई है। तथापि, संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट के कारण आवश्यक हुई थी।
- (ii) जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एनआईपी से अधिक थी। यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों में घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान उनके उत्पाद के लिए उचित कीमत वसूल करने से नहीं रोका।
- (iii) घरेलू उद्योग की क्षमता 2013-14 से स्थिर रही। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग और उत्पादन में 2015-16 तक सुधार हुआ और इस तथ्य के कारण जांच की अवधि (क) के दौरान गिरावट आई है कि घरेलू उद्योग जांच की अधिक अवधि के लिए प्रचालनात्मक नहीं था। दूसरी ओर जे के पेपर लिमिटेड के क्षमता उपयोग, उत्पादन और घरेलू बिक्री में जांच की अवधि (क) के दौरान सुधार हुआ है।
- (iv) घरेलू उद्योग का व्याज पूर्व लाभ और नकद लाभ 2015-16 तक स्थिर रहा है और जांच की अवधि (क) के दौरान उसमें गिरावट आई है। दूसरी ओर जे के पेपर लिमिटेड के व्याज पूर्व लाभ और नकद लाभ में जांच की अवधि (क) के दौरान सुधार हुआ है।
- (v) वास्तविक क्षति के खतरे का मूल्यांकन करने पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयातों का घरेलू उद्योग पर कोई कीमत न्यूनीकरण/ह्रासमान प्रभाव नहीं था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि किसी भी सहयोगी उत्पादक द्वारा कोई काफी क्षमता नहीं बढ़ाई गई थी और संबद्ध देशों से किसी भी सहयोगी उत्पादक/निर्यातक की कोई काफी मालसूची नहीं है जो परिणामस्वरूप वास्तविक क्षति के खतरे को सिद्ध नहीं करती।
- (vi) बी जी पी पी एल के उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और लाभप्रदता में गिरावट स्पष्ट रूप से उनकी अपने अंतरनिहित कारकों के कारण है और उसका संबद्ध देशों से पाटित आयातों से कोई सह संबंध नहीं है।
- (vii) अतः घरेलू उद्योग के निष्पादन पर पाटित आयातों का परिणामी प्रभाव नहीं है। इस प्रकार, निष्कर्ष स्वरूप यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित आयातों के परिणामस्वरूप जांच की अवधि के दौरान क्षति हुई।

ड. सिफारिशें

116. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा तथा निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्कों के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। जांच शुरू करने और पाटनरोधी नियमावली के तहत उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क की जांच करने पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऊपर दिए गए कारणों से संबद्ध देशों से पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कोई कारणात्मक संपर्क नहीं है और इसीलिए चीन जन गण, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमरीका से संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करना उपयुक्त नहीं मानते। अतः नियम 14 (ख) और नियम 17 (1) (क) (iii), नियम 11 (2) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II के पैरा V के साथ पठित सीमा प्रशुलक अधिनियम की धारा 9 क और 9 ख के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी वर्तमान जांच को रद्द करने का निर्णय लेते हैं जो दिनांक 23 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं. 6/42/2017-डीजीएडी द्वारा शुरू की गई थी।

ढ. आगे की प्रक्रिया

117. इस अधिसूचना के विरुद्ध कोई अपील सीमा प्रशुलक अधिनियम, 1975 और मै. जिंदल पोली फिल्म लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी रिट याचिका (सिविल) सं. 8202/2017 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सीमाशुलक, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2018

FINAL FINDINGS

Sub: **Anti-dumping investigation concerning imports of “Coated Paper” originating in or exported from China PR, European Union and USA.**

A. BACKGROUND OF THE CASE

No. 6/42/2017–DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the Rules) thereof:

1. Whereas, Indian Paper Manufacturers Association on behalf of M/s BILT Graphic Paper Products Ltd., subsidiary of M/s Ballarpur Industries Limited (hereinafter also referred to as the “Petitioner” or “the Applicant”) have filed a petition before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for imposition of Anti-dumping duty on imports of “Coated Paper” originating in or exported from China PR, European Union and USA (hereinafter also referred to as the subject countries).
2. And, whereas, the Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the Petitioners, issued a public notice vide Notification No. 6/42/2017 -DGAD dated 23rd January, 2018, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Rule 5 of the AD Rules to determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:
 - a) The Authority notified the Embassies of the Subject Countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.
 - b) The Authority issued a public notice dated 23rd January, 2018 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods.
 - c) The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassies of the Subject Countries in India, known producers/exporters from the subject Countries, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the applicants and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
 - d) The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassy of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.

- e) The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
- f) The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

CHINA PR

- (i) Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd.
- (ii) Hainan Jinhai Pulp and Paper
- (iii) Chenming Group

EUROPEAN UNION

- (iv) Stora Enso Oyj
- (v) UPM Sales Oy
- (vi) Sappi Limited
- (vii) Cham Paper Group Switzerland Inc.

USA

- (viii) New Page, Miamisburg, Ohio, USA

- g) In response, the following exporters/producers from the subject countries filed exporter's questionnaire response in the prescribed format:

- (i) M/s. Gold Huasheng Paper (Sozhou) Industrial Park) Co. Ltd. (GHS)
- (ii) M/s. Hainan Jinhai Pulp & Paper Co. Ltd. (JHPP) and
- (iii) M/s. Gold East Trading (Hong Kong) Company Limited (GEHK)
- (iv) M/s. Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd. (GE)
- (v) M/s. Upm Gmbh, Germany
- (vi) M/s. Upm Paper Ena Oy, Finland
- (vii) M/s. Upm Specialty Papers Oy, Finland
- (viii) M/s. Upm Sales Oy, Finland
- (ix) M/s. Shandong Chenming Paper Holdings Limited
- (x) M/s. Shandong Chenming Paper Sales Ltd.
- (xi) M/s. Shouguang Meilun Paper Co. Ltd., China PR
- (xii) M/s. Chenming (HK) Limited, Hong Kong
- (xiii) M/s. PG Paper Company Ltd.
- (xiv) M/s. Sappi Alfeld GmbH
- (xv) M/s. Sappi Enningen GmbH
- (xvi) M/s. Sappi Gratkorn GmbH
- (xvii) M/s. Sappi Finland Operations Oy (Kirkniemi)
- (xviii) M/s. Sappi Lanaken NV
- (xix) M/s. Sappi Maastricht B.V.
- (xx) M/s. Sappi Stockstadt GmbH
- (xxi) M/s. Sappi Europe SA

- h) The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

- (i) Allied Speciality Papers (India) Pvt. Ltd.
- (ii) Bhagwati Enterprises
- (iii) Excel Enterprise
- (iv) K.C. Exim (P) Ltd.
- (v) Narsingh Dass & Co. (P) Ltd.
- (vi) Paras Papers
- (vii) Nutech Print Services
- (viii) Plus Marketing
- (ix) Shah Devji Shivji and Co.
- (x) Sheth Brothers
- (xi) Shree Balaji Udyog
- (xii) Shree Chamunda Enterprise

- (xiii) Synchem
 - (xiv) Standard Paper and Board India Pvt. Ltd.
 - (xv) Unique Sales Corporation
 - (xvi) Tenny Jose and Associates Ltd.
 - (xvii) White Arrow Group of Companies
- i) In response, the following importers/users have responded and filed importer's questionnaire response.
- (i) M/s. Avery Dennison (India) Pvt. Ltd.
 - (ii) M/s. Living Media India Ltd.
 - (iii) M/s. Malayala Manorama Company Ltd
 - (iv) M/s. Outlook Publishing (India) Pvt. Ltd
- j) Apart from the respondent exporters and importers mentioned above, some legal submissions have been received on behalf of the following parties during the course of this investigation.
- (i) European Commission
 - (ii) All India Federation of Master Printers
 - (iii) Confederation of European Paper Industries
- k) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented / submissions made by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- l) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigations, which was received by the Authority. The Authority has, relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
- m) The Non-Injurious Price (NIP) based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-Dumping Rules has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- n) Physical inspection through on-spot verification of the information provided by the applicant domestic industry, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of final findings.
- o) Verification of the information provided by the producers/exporters, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority and has been relied upon for the purpose of final findings.
- p) The Period of Investigation for the purpose of the present anti-dumping investigation is from April, 2016 to June, 2017 (15 Months). The injury investigation period has however, been considered as the period from 2013-14, 2014-15, 2015-16 and the POI.
- q) In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 5th June, 2018. All the parties who had attended the oral hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and were advised to offer their rebuttals.
- r) The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this final findings.
- s) Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- t) Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the final findings on the basis of the facts available.
- u) A Disclosure Statement was issued to interested parties on 28th November, 2018 containing essential facts under consideration of the Designated Authority, giving time up to 10th December, 2018 to furnish comments, if any, on the Disclosure Statement. The Authority has considered post disclosure comments received from interested parties appropriately in the present final findings.

- v) “***” in this final finding represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- w) The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US\$1 = ₹67.45.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration is defined as:

“Paper or Paper Board coated with kaolin (china clay) or calcium carbonate or polymer or other inorganic substance, with or without a binder; and with no other coating, either on one or both sides; whether or not surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any sizes; whether or not dull, gloss, matte or high-gloss(cast coated) finish; made generally, but not invariably or exclusively from virgin chemical pulp, properly classifiable under Chapter 4810”.

5. Product under consideration is primarily used for printing of magazines, catalogues, books & manuals, calendars, brochures, labels, flexible packaging etc. The GSM for Coated Paper ranges from 40 GSM to 350 GSM. Specifically excluded from the scope of this petition is multilayered board for packaging purpose which does not form part of the product under consideration

C.1. Submissions made by the Domestic Industry

6. The submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article and considered relevant by the Authority are as follows:
- a) The product under consideration in the present investigation is “Paper or Paper Board coated with kaolin (china clay) or calcium carbonate or polymer or other inorganic substance, with or without a binder; and with no other coating, either on one or both sides; whether or not surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any sizes; whether or not dull, gloss, matte or high-gloss (cast coated) finish; made generally, but not invariably or exclusively from virgin chemical pulp.
 - b) Coated paper and paper board are made primarily from virgin chemical pulp and falls under various heading of chapter 4810 viz. 48101430, 48101320, 48101310, 48101490, 48101910, 48101920, 48101930, 48101990, 48102200, 48102900, 48103100, 48103200, 48103990, 48109200 and 48109900 of HSN at eight digit level. The domestic industry’s products are directly competing products with imported products which are similar as far as their technical characteristics, chemical composition and other basic features are concerned. The products of all these headings find similar uses in printing industry.
 - c) PUC is primarily used for printing of magazines, catalogues, books & manuals, calendars, brochures, labels, flexible packaging etc. The grammage for coated paper ranges from 40 GSM to 350 GSM and specifically excluded multi-layered board for packaging purpose which does not form part of the product under consideration.
 - d) Other interested parties have claimed that the entire chapter 4810 at the 4 digit level has been included in the import data which has made the PUC at the 4 digit level uncertain. It is submitted in this regard that the petition clearly listed out the codes which pertain to the product under consideration.
 - e) Considering various arguments and aspects of the present case the domestic industry has revised the product scope and details thereof have been provided in the written submission. On the basis of the revised product under consideration, import methodology has also been clearly annexed with the written submissions filed earlier and the same be relied upon now.
 - f) Product under consideration is not broad and there is no ambiguity. The details of inclusions and exclusions have been brought in clearly by the petitioner.

C.2. Submissions made by the other interested parties

7. The submissions made by the exporters, importers, users and other interested parties with regard to product under consideration and like article, and considered relevant by the Authority, are as follows:
- a) Domestic Industry has defined the PUC in terms of HS Code 48.10 with some exclusions. The import data has, however, been provided for the entire HS Code 48.10 despite having full knowledge that the import data, by definition, covers more products than what is covered by the description of the PUC.
 - b) As per the petitioner's own admission, there are various exclusions in the product concerned at 4-digit level. In fact, there are products at the 6 and 8-digit level itself which are not a part of the Product under Consideration.

- c) Domestic Industry did not even present the transaction-wise imports data to the Authority for the purpose of the initiation of the present investigation particularly when the defined PUC is only a subset of the HSN Code at the four-digit level. The Hon'ble Authority may kindly note that unlike all other investigations, no transaction-wise data was procured from the DGCI&S which indeed would have given a clearer picture. Consequently, the import statement furnished by the Domestic Industry is inclusive of the excluded products and therefore could not have been relied upon even for the purpose of initiation of the investigation.
- d) In addition to the above, it is important to note that petitioner has included those varieties of papers like insulating paper, flexible packing paper etc. which are not produced and supplied by the petitioner industry during the period of investigation. As per the established jurisprudence and consistent practice of DGTR also, the goods not produced by the Domestic Industry need to be excluded from the scope of the duties for the simple reason that the same would cause imprudent hardship to the importers.
- e) In the previous final findings dated 15th December 2004 on imports of the same PUC, the Designated Authority therein had noted at para. 5 that "subject goods does not include coated paper below 80 GSM".
- f) BGPPL was the domestic industry in the previous anti-dumping investigations as well. However, it did not request for imposition of anti-dumping duty on coated paper and paper boards below 80 GSM. If BGPPL is not manufacturing coated paper below 80 GSM, it cannot be included within the scope of the PUC in the present investigation.
- g) At the time of the oral hearing in the subject investigation, the domestic industry agreed that coated paper weighing less than 80GSM can be excluded from the scope of product under consideration. In this regard, we request the Designated Authority to take the submission of domestic industry on record and exclude coated paper weighing less than 80 GSM from the scope of product under consideration.
- h) It seems that the Domestic Industry has included products falling under HS code 48102200 within the product scope. HS code 48102200 covers "Light-weight coated paper". However, in the import methodology, the Domestic Industry specifically notes that Light-weight coated paper is non-PUC and is outside the product scope.
- i) Similarly, in the updated import data provided by the domestic industry, there are a number of import transactions of 'multi layered board' which are considered as PUC. As provided in the notice of initiation, multi-layered board is specifically excluded from the scope of product under investigation. Thus, the Respondents request the Authority to discard the updated import data provided by the Domestic Industry.

C.3. Examination by the Authority

8. The Authority has noted submissions made by various interested parties with regard to scope of the product under consideration and like article offered by the domestic industry. With respect to the product under consideration, the Authority notes as follows:
- a) On the basis of submissions including post- disclosure comments made by various interested parties and the examination of records of Domestic Industry, the Authority excludes double sided coated paper below 75 GSM, light-weight coated paper, Electrical Kraft insulation paper, Kraft paper, Kraft insulation paper and insulating paper from the scope of product under consideration.
 - b) Accordingly, the product under consideration in the present investigation is "Paper or Paper Board coated with kaolin (china clay) or calcium carbonate or polymer or other inorganic substance, with or without a binder; and with no other coating, either on one or both sides; whether or not surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any sizes; whether or not dull, gloss, matte or high-gloss (cast coated) finish; made generally, but not invariably or exclusively from virgin chemical pulp. The product under consideration covers coated paper having GSM ranging between 40 GSM to 350 GSM. Specifically excluded from the scope of PUC are the following:
 - i. Multi-layered board for packing purpose.
 - ii. Double sided coated paper below 75 GSM
 - iii. Light-weight coated paper
 - iv. Electrical Kraft insulation paper
 - v. Kraft paper
 - vi. Kraft insulation paper
 - vii. Insulating paper

- c) Product under consideration is classified under chapter 48 of the Customs Tariff Act, 1975, under customs sub-heading 4810. The customs classification is indicative only and in no way binding upon the product scope.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submissions made by the Domestic Industry

9. The submissions made by the domestic industry during the course of the investigation with regard to scope of domestic industry & standing are as follows:
 - a) Application was filed by Indian Paper Manufacturers Association on behalf of domestic industry, M/s BILT Graphic Paper Products Ltd, which is a producer of the subject goods in India. There is one more known domestic producer of the product under consideration, namely, JK Paper Limited.
 - b) Applicant has not imported the product under consideration and is not related to any importer in India or exporter from subject countries and has not imported the product under consideration.
 - c) With respect to the claims of the other interested parties that the domestic industry has been incorrectly defined by the non-inclusion of other alleged producers of the subject goods in the country which has ultimately led to a skewed analysis of the injury parameters the domestic industry reiterates that the this claim is not based on any credible evidence. In fact, interested parties themselves contradicted inter-se by arguing that there are a large number of producers but there are only two major producers. In any case, interested parties have not provided any evidence to prove that the production of the petitioner does not constitute a major proportion in Indian production.
 - d) Imports made by JK Paper are quite significant in volumes, quite comparable to its own production volumes. JK Paper should not be treated as eligible domestic industry under the Rules. Notwithstanding, JK Paper has not opposed the present petition and has requested for imposition of ADD despite their imports.

D.2. Submission of other interested parties

10. The submissions made by various other interested parties with regard to the scope of domestic industry & standing are as under:
 - a) The applicants in the instant case stated that there are only two producers namely M/s. BILT Graphic Paper Products Ltd. and M/s. JK Paper Limited of the subject goods in India who are engaged in the production of Product under Consideration. However, there are other producers of the subject goods in India. This information provided by the applicant therefore appears to be factually incorrect.
 - b) It is important to note that despite the fact that JK paper is a part of IPMA (petitioner), it has not been made an applicant in the present application. It is noteworthy that the petition is completely silent on the issue as to why JK paper has not formed part of the Domestic Industry. Without prejudice, it is humbly requested that the Authority may kindly take into consideration the performance and production parameters of JK paper to ensure that the exclusion of JK paper is not done to wilfully distort the performance indices of the Domestic Industry.
 - c) As per NCV petition, it is to be noted that while calculating total demand in India, the petitioner has not considered the sale made by JK Paper and simply calculated the same by adding imports and captive consumption & sale made by domestic industry. It was submitted that apart from JK Paper, there are other producers in India namely West Coast Paper Mills Ltd., Shree Krishna Papers Mills Ltd, Century Papers, and others. The Authority is hereby requested to ask the domestic industry to provide revised and complete information.
 - d) IPMA should clarify (i) whether any of its members apart from BGPPL and JK Paper are producing coated paper & (ii) whether the information regarding production in the petition is of total production of coated paper in India or is based on information available to IPMA.
 - e) If all the producers in India are not included while calculating total production then it cannot be definitively determined if the Petitioner constitutes major proportion of total domestic production for the purposes of standing as required under Rule 2(b) of the AD Rules. The Designated Authority should request specific information from the Domestic Industry regarding the producers of subject goods in India and their respective production before proceeding any further with the investigation.
 - f) JK Paper is one of the constituents of domestic industry in the anti-dumping investigation on uncoated paper. However, it is not part of domestic industry in the present anti-dumping investigation. Petitioner has submitted during the hearing that JK paper has imported the product and therefore is excluded from the scope of domestic industry.

- g) Respondent submits that there is no automatic exclusion of domestic producer who is also an importer of the subject product. Designated Authority has the discretion to decide regarding the exclusion of the domestic industry. We request the Authority to examine the claim of domestic industry regarding exclusion of JK Paper from the scope of domestic industry. Respondent submits that JK Paper should also be included as a constituent of domestic industry to properly assess the production information of JK paper and also to arrive at a more representative determination of material injury.
- h) The Domestic Industry has ignored the claim of interested parties about existence of other coated paper producers by merely stating that no credible evidence is provided by the interested parties to substantiate the claim.

D.3. Examination by the Authority

11. Rule 2(b) of the AD Rules provides as follows:

“domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”

12. The petition was filed by Indian Paper Manufacturers Association on behalf of domestic industry, M/s. BILT Graphic Paper Products Ltd, which is a producer of the subject goods in India. In the petition it was stated that there is one more known domestic producer of the product under consideration, namely, JK Paper Limited.
13. Other interested parties have raised an issue that apart from M/s. BILT Graphic Paper Products Ltd. and M/s. JK Paper Limited there are other domestic producers of the product under consideration in India.
14. The Authority has verified the information submitted by the domestic industry regarding total production in India and total production of the domestic industry and requested other known domestic producers as pointed out by various interested parties in their submissions regarding manufacturing of subject goods. M/s. Century Pulp and Paper, M/s. Star Paper Mills Ltd., M/s. Pudumjee Paper Products Ltd, M/s. West Coast Paper Mills Ltd. and M/s. Shree Krishna Paper Mills & Industries Ltd. stated that they are not the manufacturers of the subject goods. However, one domestic producer namely M/s. Seshasayee Paper and Boards Limited has submitted that they are a domestic producer of the subject goods having capacity of *** MT during POI. Therefore, the Authority notes that based on the information available with the Authority, Domestic industry accounts for ***% share in total production of the subject goods during period of investigation.
15. The Authority notes that petitioner company has neither imported the subject goods, nor it is related to an importer or exporter of the subject goods. Therefore, the Authority holds that the Petitioner commands a major proportion of the production of the subject goods in India. Therefore, for the purpose of this investigation the Petitioner Company satisfies the standing requirement and constitutes the domestic industry in terms of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules.

E. ISSUES RELATING TO CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions by domestic industry

16. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality issues:
- a) Responding exporters/producers have claimed excessive confidentiality by not providing meaningful information in the public version of their questionnaire responses such as name of the shareholders, related party details, Indian channel of distribution etc. The respondents have not established and justified their confidentiality claims. If the Designated Authority is of the opinion that confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized form, then the Authority may elect to disregard such information.
 - b) Responding exporters/producers in their responses have claimed confidentiality on their “related parties” information. The public search reveals that apart from Shouguang Meilun Paper Co., Ltd there is one more producer of the goods that is related to Shandong Chenming Paper Holdings Ltd namely, Jiangxi Chenming Paper Co. Ltd. Further, apart from Shandong Chenming Paper Sales Company Limited and Chenming (HK) Limited there is another related company that is engaged in the trade of the subject goods, namely, Qingdao Chenming International Logistics Co., Ltd. It is submitted that these two companies have not filed response in

the present investigation. There is no clarity on the specific number of subsidiary companies and their names. The veracity of the claims with regard to related parties needs to be verified. The EQR has three subsidiary companies responding, i.e., Shougang Meilun Paper Co., Ltd, Chenming HK Ltd and Shandong Chenming Paper Sales Co. Ltd out of the five subsidiary companies involved in the business of production or sale of coated paper.

- c) Domestic industry submitted that disclosure of actual information with regard to domestic industry can jeopardize the future business in the product. As regards the volume information, petitioner information being the sole petitioner, the same have been legitimately treated as confidential. The said information is not available in public and thus they are not bound to disclose them.
- d) However, it is surprising to note that the exporters have claimed complete confidentiality on its data including information about exports, sales, production etc but are demanding the same information from the domestic industry. The yardsticks of claiming confidentiality cannot be different for domestic producers and exporters. Even the importer questionnaire response has absolutely no information disclosed.

E.2. Submissions by other interested parties

17. The following submissions have been made by other interested parties with regard to confidentiality issues:

- a) The Domestic Industry has provided a non-confidential version of the petition which involves data and information relating to five countries whereas the present investigation has been restricted only to three of those five countries. The data contained in the petition provided by the Domestic Industry is with respect to 5 countries and the cumulative analysis has also been done vis-a-vis 5 countries. Clearly, the non-confidential version of the petition provided by the Domestic Industry does not relate to the information/data contained in the initiation notification and which presumably formed the basis of the Hon'ble Authority to initiate the present investigation.
- b) In the absence of a proper non-confidential version, the rights of the responding interested parties are severely prejudiced.
- c) Further, the non-confidential version filed by the Domestic Industry is also improper on account of the arbitrary claims of confidentiality on the basic information relating to the investigation. It was incumbent upon the applicant Domestic Industry to provide a proper non-confidential version of the application in terms of Rule 6(3) and the claim of confidentiality had to be allowed or disallowed by the Designated Authority in terms of Rule 7.
- d) Domestic industry has kept several key economic parameters as confidential in the petition. Without such information, the Respondents are not able to fully undertake a meaningful examination of injury parameters of the applicant industry. This claim of excessive confidentiality has significantly impaired the ability of the Respondents to defend their interests. It is submitted that the Designated Authority must evaluate the claims for confidentiality of information and not designate information as confidential without a proper examination.
- e) The party providing the information on a confidential basis may be of the opinion that such information is not susceptible to summarization and not furnish the non-confidential summary of such information. However, in such a case, Rule 7(2) of the AD Rules requires the party to submit a statement of reasons as to why summarization is not possible. A mere statement that "the summarization of the information is not possible" cannot fulfill the legal requirement to make a statement of reasons as to why summarization is not possible.
- f) The Designated Authority is also required to evaluate the claims of confidentiality and determine whether the information in question can be kept confidential or not. In the present matter, the claim for confidentiality has been granted automatically without a thorough evaluation of the information to which the confidentiality claim pertains.
- g) Petitioner has claimed confidentiality over actual figures of (i) capacity (ii) sales (iii) capacity utilization (iv) export sale (v) market share (vi) employees & (vi) demand. Actual figures for these parameters are disclosed in all the final findings issued by the Designated Authority. In relation to net sales realization, domestic industry has not even disclosed indexed numbers. These figures are disclosed in the final findings issued by the Authority in all anti-dumping investigations. For example, in the recently concluded anti-dumping investigation on *Sodium Dichromate from Russia, Kazakhstan, Turkey & South Africa*, Designated Authority disclosed actual figures for capacity, capacity utilization, sales, demand, & market share in its final findings. In fact, the actual figures were disclosed even though domestic industry comprised of single producer even in this anti-dumping investigation.

- h) In fact, in the previous anti-dumping investigation concerning coated paper, actual figures regarding total demand, capacity, capacity utilization, total number of employees and net selling price (net sales realization) of domestic industry in indexed form was also provided:

Particulars	Unit	2000	2001	2002
Demand	MT	83,194	90,597	110,721
Market Share of BILT (domestic industry)	%	76.57	75.97	62.95

Source: Final Findings No. 14/7/2003 dt.15th December 2004, paras. 28 & 40

- i) Thus, there is no basis to claim confidentiality over these figures in the present anti-dumping investigation.

E.3. Examination by the Authority

18. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

- (2) *The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*
- (3) *Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”*

19. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection.

20. Submissions made by the domestic industry and other opposing interested parties with regard to confidentiality to the extent considered relevant were examined by the Authority and addressed accordingly. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Submissions made by domestic industry

21. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:

- a) Some of the questions in the questionnaire seek information with regard to subsidies that are provided by the Govt. of the exporting country.
- b) It would be seen that the responding exporters have claimed absence of any subsidies by their Govt. As per petitioner's understanding, many programs are being run by the Govt. of China wherein benefits are being provided to the exporters. The Indian Authority has also held that all the schemes are in operation and after detailed examination countervailed those subsidies. Under the circumstances, the statement of the exporters that there are no subsidy schemes of Government of China in operation is highly misleading and factually incorrect. The exporters are expected to report about the subsidy schemes in operation whether they have availed any benefits or not. We request the Authority to reject the questionnaire response considering the serious nature of the misleading, incomplete or otherwise deficient questionnaire response.
- c) Regarding claims of the import volumes being unreliable as they include imports from 2 non subject countries,

Korea and Indonesia, the domestic industry states that the confidential version of the application was filed considering the injury being caused from 5 countries and hence the petition contains import volumes of the 5 proposed subject countries. The investigating authority considered it appropriate to initiate and proceed with the investigation against the current set of subject countries. The requirement is that the interested parties should get a copy of the petition relied upon by the Designated Authority, i.e., the information considered by the Authority for initiation which is what the domestic industry had provided upon initiation of investigation. Moreover, the annexures and petition filed after initiation also has separate volume for each of the subject country and the interested party can analyse the share of the volume of subject imports. However, as was stated at the time of the hearing, the domestic industry has already filed the revised information along with the post hearing written submissions.

F.2. Submissions made by other interested parties

22. The following miscellaneous submissions have been made by other interested parties:

- a) Domestic industry has stated that IPMA maintains production data of paper producers but domestic industry has not disclosed source of sales data of other producers.
- b) There is no information at all in the petition regarding cash flow, productivity, wages, profit before interest and tax (PBIT), depreciation cost and interest cost. Productivity, cash flow, wages are mandatory injury parameters specified in para (iv) of Annexure II of the Anti-Dumping Rules.

F.3. Examination by the Authority

23. Various submissions made by the interested parties with regard to miscellaneous issues and considered relevant by the Authority are examined and addressed as follows:

As regards the issue of subsidies provided by the Government of China, it is noted that the present investigation is an anti-dumping investigation and therefore, the Authority is not examining the subsidies provided by the Government of China.

G. MARKET ECONOMY TREATMENT (MET), NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

24. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

- (i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- (ii) *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*
 - (a) *Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - (b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

G.I. Submissions by the Domestic Industry

25. The following submissions have been made by the domestic industry:

- a) It is submitted that the respondents from China PR should not be granted market economy treatment unless the responding exporters satisfy each & every of the following conditions.
- i. Market economy status cannot be given in a situation where one of the major shareholders is a State owned/controlled entity –It needs to be ascertained whether there is any shareholder which is a state owned entity. The Designated Authority and the EC has consistently held that possibilities of State interference cannot be ruled out in such cases. It is being held that it is not only the question of past interferences alone, but also

- possibilities of potential State interference in the future after the imposition of anti-dumping duties that is relevant for market economy treatment.
- ii. Market economy status cannot be given unless the responding Chinese exporters establish that the prices of major inputs substantially reflect market values – “substantially reflect market values” has been widely interpreted to mean that the price of these inputs must be comparable to the prices prevailing in the international market.
 - iii. Market economy status cannot be given unless the responding exporter establish that their books are audited in line with international accounting standards – market economy treatment must be rejected in such situations where Chinese exporters are unable to establish that their books are consistent with International Accounting Standards (IAS). The requirement on insisting compliance with International Accounting Standards is to ensure accuracy and adequacy of revenues and expenses, assets and liabilities expressed in the annual report.
 - iv. Market economy status cannot be granted even if one of the parameters is not satisfied – market economy status cannot be granted unless the responding Chinese exporters pass the test in respect of each and every parameter laid down under the rules. This situation is just the opposite of the test required for material injury. It is well acknowledged position that a positive finding of injury can be recorded even if one single parameter establishes injury. Thus, while one parameter is sufficient to establish existence of injury, failure to pass one single parameter is sufficient to reject the claim of market economy status.
 - v. Onus/obligations – it is not for the Authority to establish that the responding companies are indeed operating under market economy environment and is entitled for market economy treatment. On the contrary, it is for the responding Chinese exporters to establish that they are operating under market economy conditions.
 - vi. Response from group as a whole – Market economy status cannot be granted unless the responding company and its group as a whole make the claim. If one or more companies forming part of the group have not filed the response, market economy status must be rejected.
 - vii. Transformation – In a situation where the current shareholders have not set up their production facilities themselves but have acquired the same from some other party, market economy status cannot be granted unless process of transformation has been completely established through documentary evidence
 - b) The authority should investigate and ascertain all the changes in the ownership since setting up the initial plant in China, if any, that can have an impact. The history of development forms the basis of giving/denying market economy treatment. The exporter is required to establish that prices of inputs substantially reflect the market values. Further, the Designated Authority has earlier held that “substantially reflect market value” is not with reference to Chinese market price. The same is with reference to international prices. The exporter has provided no evidence to establish that prices of inputs substantially reflected market value. The possibility of material being supplied to some other related/unrelated company and exported to India by such related/unrelated entity cannot be ruled out from the present response. There are past determination of Designated Authority where the Designated Authority refused individual dumping margins and duties whenever the Designated Authority found that the value chain was incomplete.
 - c) Normal value in case of the European Union and the USA has been determined on the basis of the import prices in the respective countries. The other interested parties have contended that there is no legal basis to determine normal value on the basis of the prices of worldwide imports into the European Union. On the contrary, when information with regard to consumption price in the domestic market of the exporting country is available, it is that information that needs to be correlated. Imports of subject goods into EU and USA are significant. The import price into these countries shows the price prevailing in the domestic market of these subject countries. Thus the petitioner has determined normal value at the stage of initiation in accordance with law.
 - d) The petitioner had relied upon DGCI&S published data, to assess the volume and value of subject imports into India, at the stage of initiation of investigations. The export price was calculated at the CIF level, while the normal values were at ex-factory level. The export prices were adjusted for expenses on Ocean Freight, Marine insurance, Commission, Inland Freight, Port expenses, Bank charges and VAT adjustment (for China PR). Since the petitioner has provided transaction wise import data, the petitioner has provided revised calculations of normal value, export price and dumping margin.

G.2. Submissions by the other interested parties

26. The following submissions have been made by other interested parties:
 - a) Determination of normal value and dumping margin should be based on the information provided by the exporters/producers from subject countries.

- b) It must be noted that in the present case, the Hon'ble Designated Authority has deemed it appropriate to exclude Korea RP and Indonesia from the scope of this investigation on the grounds that the import prices evidenced an absence of dumping. It is submitted that this approach of the Designated Authority is discriminatory by initiating the investigation against China PR, EU and USA while excluding Korea RP and Indonesia. It is submitted that this exclusion is inconsistent with regards to Rule 14(d), Rule 5(2) and Rule 5(3)(b) of the AD Rules.
- c) If the Hon'ble Designated Authority does discriminate between the countries for the purposes of imposing an anti-dumping duty, it would be in violation to the Most Favoured Nation (MFN) treatment as enshrined under Article I of the GATT 1947.
- d) It is further submitted that the volume of the imports from Korea RP and Indonesia is above the 3% de minimis threshold as laid out under Rule 14(d) of the AD rules. The exclusion of Korea RP and Indonesia even when their import volumes are above the threshold is unjustified. This exclusion is even more erroneous as the calculation of dumping to justify this exclusion has not been made available to the interested parties.
- e) Indian Investigating Authority has issued a separate questionnaire to exporters from China PR seeking voluminous information from exporters from China PR with regard to claims of Market Economy status. China PR had been treated as a Non-Market Economy country by India in the past. It is hereby submitted that in accordance with relevant provisions of the Protocol on China's accession to the WTO, the "surrogate country" practice in Anti-Dumping actions should be lacking in multilateral legal basis since 11th Dec, 2016. Such practice is bound to expire from then on. It is requested to the Authority not to use "surrogate country" methodology in calculating the normal value for this case, regardless of whether treating China as a market economy country or not.
- f) Domestic Industry has incorrectly stressed the relevance of import price of PUC in EU and USA for the purpose of determination of normal value. EU is a market economy territory. The normal value in case of market economy countries is determined in accordance with Section 9A (c) of the Customs Tariff Act. Section 9A (c) provides that normal value shall be based on (i) domestic sales of like article in such country or when such information is not available or reliable (ii) comparable price of like article when exported from such exporting country to an appropriate third country or (iii) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs and for profits.
- g) There is no legal requirement to further correlate the normal value determined in this manner with the import price of the PUC in the concerned market economy country.
- h) Respondents have filed the questionnaire response and have furnished all the relevant information. The Domestic Industry has wrongly claimed that information is not provided regarding the complete value chain. Related entities of the Respondents noted by the Domestic Industry are not involved in the production or exports of the PUC to India. Thus, there is no requirement to file response for related entities.

In the petition filed by the Domestic Industry, CIF price/export price per unit from the EU was much higher. However, in the updated data, for reasons best known to the Domestic Industry, the CIF price/export price from the EU has reduced drastically.

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI (A)	POI
CIF Price as per petition	MT	52,476	52,391	51,338	49,796	49,796
CIF Price as per updated data	Rs/MT	44,714	42,571	42,205	41,286	41,286

- (j) There are substantial variations in the import price (CIF) without any further explanation. This adds to the already highlighted inaccuracies, contradictions and unreliability of import data provided by the Domestic Industry.
- (k) In any case, determination of normal value & dumping margin is required to be made based on the information provided by the Respondents in the questionnaire response. Thus, claim regarding increased dumping margin and lower export price is inconsequential.

G.3. Examination by the Authority

27. Under section 9A (1) (c) normal value in relation to an article means:

- a) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or
- b) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:
 - (i) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - (ii) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*
- c) The Authority sent questionnaires to the known exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed. However, barring the following producers and exporters, none of the other producers/ exporters from subject countries co-operated in this investigation by filing the prescribed questionnaire responses:
 - (i) M/s. Gold Huasheng Paper (Sozhou) Industrial Park) Co. Ltd. (GHS)
 - (ii) M/s. Hainan Jinhai Pulp & Paper Co. Ltd. (JHPP) and
 - (iii) M/s. Gold East Trading (Hong Kong) Company Limited (GEHK)
 - (iv) M/s. Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd. (GE)
 - (v) M/s. Upm Gmbh, Germany
 - (vi) M/s. Upm Paper Ena Oy, Finland
 - (vii) M/s. Upm Specialty Papers Oy, Finland
 - (viii) M/s. Upm Sales Oy, Finland
 - (ix) M/s. Shandong Chenming Paper Holdings Limited
 - (x) M/s. Shandong Chenming Paper Sales Ltd.
 - (xi) M/s. Shouguang Meilun Paper Co. Ltd., China PR
 - (xii) M/s. Chenming (HK) Limited, Hong Kong
 - (xiii) M/s. PG Paper Company Ltd.
 - (xiv) M/s. Sappi Alfeld GmbH,
 - (xv) M/s. Sappi Enningen GmbH,
 - (xvi) M/s. Sappi Gratkorn GmbH,
 - (xvii) M/s. Sappi Finland Operations Oy (Kirkniemi),
 - (xviii) M/s. Sappi Lanaken NV,
 - (xix) M/s. Sappi Maastricht B.V.,
 - (xx) M/s. Sappi Stockstadt GmbH
 - (xxi) M/s. Sappi Europe SA

28. Article 15 of China's Accession Protocol provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

29. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption that there are significant distortions prevailing in the industry producing the subject goods in China PR. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide relevant information to demonstrate prevalence of market conditions related to manufacture, production and sales of the subject goods in the domestic market and in exports to India and other countries. The Authority sent copies of supplementary questionnaire to all the known producers/ exporters for providing information in regard to the criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules. The Authority also requested the Government of China PR to advise the producers/ exporters in China PR to provide the relevant information.
30. Article 15 implies that provisions of one of the subparagraph shall expire 15 years from date of China's Accession. The provisions of this paragraph expired on 11th December, 2016. Since the factum of dumping causing injury to the domestic industry is established based on investigation period, the conditions prevalent during the investigation period is relevant, appropriate and necessary for the purpose of present investigation. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present investigation is April, 2016 to June, 2017. Since the subparagraph of Article 15 was in existence during the major part of the period of investigation, the Authority shall use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.
31. The Authority notes that in the past three years, China PR has been treated as non-market economy country in anti-dumping investigations by India and other WTO Members. China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the Rules.

Examination of Market economy claims

32. As per Paragraph 8 of Annexure I of the Anti-Dumping Rules, the presumption of a non-market economy can be rebutted, if the exporter(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) of Paragraph 8 and establish the facts to the contrary. The cooperating exporters/producers of the subject goods from People's Republic of China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether:
 - i. The decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
 - ii. The production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;

- iii. Such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and
- iv. The exchange rate conversions are carried out at the market rate.

G.4. Determination of Normal Value and Export Price for cooperating producers and exporters in China PR

G.4.1. Determination of Normal Value for producers and exporters in China PR

33. It is noted that one Chinese group consisting of Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd. Gold Hua Sheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd., Hainan Jinhai Pulp & Paper Co. Ltd and Gold East Trading (Hong Kong) Co. Ltd claimed market-economy treatment. However, they withdrew their claim during the course of the investigation. No other Chinese producer/exporter has claimed market economy treatment. Therefore, the Authority has determined the normal value on the basis of best facts available and the same is shown in the Dumping Margin Table at para 52.

G.4.2. Export Price for China PR

A. Export price for case of M/s Shouguang Meilun Paper Co., Ltd. & M/s Shandong Chenming Paper Holdings Ltd., (Producers) along with its trader M/s Chenming (HK) Limited (Exporter) Hong Kong

34. From the response filed by producers/exporters, Authority notes that M/s Shouguang Meilun Paper Co., Ltd. and M/s Shandong Chenming Paper Holdings Ltd., China PR are related and have exported the subject goods to India during the POI through related trader namely M/s Chenming (HK) Limited (Exporter), Hong Kong. The producers have claimed adjustments on account of inland freight, handling charges, overseas freight, credit cost, bank charges, etc. and the same have been allowed by the Authority for computation of the export price at ex-factory. It is also noted by the authority that trader has exported the subject goods at loss and therefore appropriate adjustment has been made for loss incurred by the trader. Further, Authority has made appropriate adjustment on account of Non-Refundable VAT. Accordingly, ex-factory export price for the participating producers has been determined as USD *** per MT.

B. Export Price for Gold East Trading (Hong Kong) Company Limited (“GEHK”)

35. From the response filed by Gold East Trading (Hong Kong) Co. Ltd (“GEHK”), Authority notes that GEHK gets the goods manufactured by its three related producers namely Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd. (GE), Gold Hua Sheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd. (GHS) and Hainan Jinhai Pulp & Paper Co. Ltd. (JHPP). GEHK supplies the raw materials (pulp and some chemicals), which are imported into China under the Processing Trade procedure, for toll manufacturing by above three producers. The subject goods manufactured by these producers are exported by GEHK to India and other countries. GEHK retains the ownership of the raw materials as well as that of the final products manufactured by these producers. Accordingly, GEHK is the exporter of the subject goods to India.
36. It is noted that GEHK has claimed adjustment on account of ocean freight, clearance & handling charges, overseas insurance, inland freight, commission, bank charges and credit cost. Further, Authority has made appropriate adjustment on account of Non Refundable VAT. Accordingly, ex-factory export price for GEHK has been determined as USD *** per MT.

C. Export Price for non-cooperating producers and exporters from China PR

37. The Authority notes that no other producer/exporter from China PR has responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative producers/exporters in China PR, the Authority has determined the export price on the basis of facts available and the same is shown in the Dumping Margin Table at para 52.

G.5. Determination of Normal Value and Export Price for cooperating producers and exporters in European Union

G.5.1. Determination of Normal Value for producers and exporters in European Union

A. Normal Value for M/s. UPM Communication Papers Oy (formerly known as UPM Paper ENA Oy), (b) M/s. UPM Specialty Papers Oy, (c) M/s. UPM GmbH and exporter/trader M/s. UPM Sales Oy (“UPM Group”)

38. From the response filed by producers in UPM Group i.e. M/s. UPM Communication Papers Oy, M/s. UPM Specialty Papers Oy and M/s. UPM GmbH, authority notes that all companies have made sales of product under consideration in domestic market during the POI through their related company M/s. UPM Sales Oy. It is noted that all the producer companies in UPM Group sell the entire production to M/s. UPM Sales Oy and M/s. UPM Sales Oy carries out domestic sales as well as exports to India and other countries. It was also noted that domestic

sales were made to related as well unrelated customers in EU. However, the prices to related customers were higher than the prices to unrelated customers.

39. To determine the normal value, the authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production and SGA expenses of product under consideration. If profit making transactions are more than 80% then the Authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value and in case, profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value.
40. In this case, based on the ordinary course of trade test, all domestic sales have been taken for determination of normal value, since the profitable sales were more than 80%. M/s. UPM Sales Oy has claimed adjustments for inland transportation, ocean freight, insurance, handling and other expenses, credit cost, commission & rebate/discount and the same have been allowed by the authority. While arriving at ex-factory normal value, Authority has also deducted the SGA expenses incurred by M/s. UPM Sales Oy. Accordingly, normal value at ex-factory level for the participating producers has been determined as USD *** per MT for UPM Group.

B. Normal Value for M/s. Sappi Alfeld GmbH, M/s. Sappi Enningen GmbH, M/s. Sappi Gratkorn GmbH, M/s. Sappi Finland Operations Oy (Kirkniemi), M/s. Sappi Lanaken NV, M/s. Sappi Maastricht B.V., M/s. Sappi Stockstadt GmbH and M/s. Sappi Europe SA ("SAPPI Group")

41. From the response filed by the above-mentioned producers in SAPPI Group, the Authority notes that all companies have made sales of subject goods in domestic market during the POI. The Authority examined the domestic sales made by the SAPPI Group and noted that the sales in the domestic market are representative when compared to exports of the product under consideration to India.
42. The Authority has, therefore, decided to determine the normal value based on domestic sales of the SAPPI Group. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit-making domestic sales transactions with reference to cost of production of product under consideration for each company in the group. If profit making transactions are more than 80% then the Authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value and in case, profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value.
43. The companies in SAPPI Group have claimed adjustments for commission, claims, inland freight, delivery charges and inland insurance and the same have been allowed by the Authority. Accordingly, normal value at ex-factory level for the participating producers has been determined as USD *** per MT.

C. Normal Value for non-cooperating producers and exporters from European Union

44. The Authority notes that no other producer/exporter from EU has responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative producers/exporters in EU, the Authority has determined the normal value at ex-factory level on the basis of best available information and the same is shown in the Dumping Margin Table at para 52.

G.5.2. Export Price for European Union

A. Export Price for M/s. UPM Communication Papers Oy (formerly known as UPM Paper ENA Oy), (b) M/s. UPM Specialty Papers Oy, (c) M/s. UPM GmbH and exporter/trader M/s. UPM Sales Oy ("UPM Group")

45. From the response filed by producers in UPM Group i.e. M/s. UPM Communication Papers Oy, M/s. UPM Specialty Papers Oy and M/s. UPM GmbH, authority notes that all companies have exported the product under consideration to India during the POI through their related company M/s. UPM Sales Oy. All exports to India have been made to unrelated customers.
46. Accordingly, the Authority has worked out the ex-factory export price taking the export price to unrelated Indian customers and making adjustments on account of inland transportation, ocean freight, insurance, handling and other expenses, credit cost, sales commission & rebate/discount. While arriving at ex-factory export price, Authority has also deducted the SGA expenses incurred by UPM Sales Oy. Accordingly, ex-factory export price for the participating producers has been determined as USD *** per MT for UPM Group.

B. Export price for M/s. Sappi Alfeld GmbH, M/s. Sappi Enningen GmbH, M/s. Sappi Gratkorn GmbH, M/s. Sappi Finland Operations Oy (Kirkniemi), M/s. Sappi Lanaken NV, M/s. Sappi Maastricht B.V., M/s. Sappi Stockstadt GmbH and M/s. Sappi Europe SA ("SAPPI Group") and M/s. PG Paper Company Ltd ("PGCPL")

47. From the response filed by producers and exporters involved in the sales to India, the authority notes that during the POI sales to India were made by the producers in the SAPPI Group, through a related trader i.e. Sappi Europe SA as well as the unrelated trader PGCPL. The Authority notes that both traders have filed their questionnaire responses, and their respective responses have been duly verified. All exports to India have been made to unrelated customers.
48. Accordingly, the Authority has worked out the ex-factory export price taking price to unrelated Indian customers and making adjustments on account of commission, claims, shipping cost, insurance and bank charges, along with SG&A expenses of the traders involved. It is also noted by the authority that PGCPL has exported the subject goods at loss, therefore, appropriate adjustment has been made for loss incurred by PGCPL and the ex-factory export price has been determined as USD *** per MT for SAPPI Group.

C. Export Price for non-cooperating producers and exporters from EU

49. The Authority notes that no other producer/exporter from EU has responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative producers/exporters in EU, the Authority has determined the export price on the basis of best available information and the same is shown in the Dumping Margin Table at para 52.

G.6. Determination of Normal Value and Export Price for cooperating producers and exporters in USA

G.6.1. Determination of Normal Value for producers and exporters in USA

50. The Authority notes that no producer/exporter from USA has responded to and cooperated with the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative producers/exporters in USA, the Authority has determined normal value at ex-factory level for the subject goods on the basis of best available information and the same is shown in the Dumping Margin Table at para 52.

G.6.2. Export Price for other producers and exporters in USA

51. The Authority notes that no other producer/exporter from USA has responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative producers/exporters in USA, the Authority has determined the export price for the subject goods on the basis of best available information and the same is shown in the Dumping Margin Table at para 52.

G.7. Dumping Margin Table

52. The dumping margin during the POI for all exporters/producers from the respective subject countries have been determined as provided in the table below:

S.No.	Country	Producer	Exporter	Constructed Normal Value/ Normal Value	Net Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin
				(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	(%)	(Range)
1	China PR	a. M/s Shouguan g Meilun Paper Co., Ltd. b. M/s Shandong Chenming Paper Holdings Ltd.,	M/s Chenming (HK) Limited	***	***	***	***	60-70
2	China PR	Gold East Trading (Hong Kong) Company Limited	Gold East Trading (Hong Kong) Company Limited	***	***	***	***	60-70

S.No.	Country	Producer	Exporter	Constructed Normal Value/ Normal Value	Net Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin
3	China PR	All Others	All Others	***	***	***	***	90-100
4	European Union	a. Sappi Alfeld GmbH b. Sappi Enningen GmbH c. Sappi Gratkorn GmbH d. Sappi Finland Operations Oy (Kirkniemi) e. Sappi Lanaken NV f. Sappi Maastricht B.V g. Sappi Stockstadt GmbH	a. Sappi Europe SA b. PG per Company Ltd	***	***	***	***	25-35
5	European Union	a. M/s. UPM Communication Papers Oy b. M/s. UPM Specialty Papers Oy, c. UPM GmbH	M/s. UPM Sales Oy	***	***	***	***	(5)-0
6	European Union	All Others	All Others	***	***	***	***	70-80
7	USA	All	All	***	***	***	***	140- 150

H. INJURY ASSESSMENT AND CAUSAL LINK

H.1. Submission made by the Domestic Industry

53. The submissions made by domestic industry are as follows:

- It has been contended by some interested parties that the period of investigation does not end as close to the initiation. It is submitted that April 2016-June 2017 was a recent period, as the notice of initiation was issued in January, 2018. There have been several past cases wherein the POI was marginally more than 6 months old. In any case, the performance of the domestic industry for post POI can also be evaluated, if considered relevant by the Authority. The performance of the domestic industry will continue to be adverse on account of dumped imports.
- It has been argued that prices of import from EU is higher than that from China and US. The domestic industry states that, the imports from EU are competing with goods exported from China and USA as well as goods produced and sold by the domestic industry and thus cumulative assessment is justified.

- c) The assessment of demand can be seen as the sum of domestic industry sales, other Indian producers' sales and imports from all sources. The demand for the product under consideration, as can be seen from the petition, has increased throughout the injury period and shows a positive trend.
- d) It has been argued that the demand in the country has increased and considering the shutdown of the domestic industry operations for a major period in the POI, the lack of availability of the PUC resulted in increase in import volumes. The domestic industry agrees that the domestic industry went through shut down for a major period of the POI. However, the domestic industry states that despite making adjustments for the shutdown suffered by the domestic industry by same considering the maximum capacity utilization achieved by the domestic industry in 2015-16, imports would still show increase in absolute as well as relative terms.
- e) Import price from subject countries declined significantly in the POI without corresponding decline in the raw material costs. This has been the primary reason for the injury caused to the domestic industry.
- f) The landed price of imports from subject countries as a whole as well as individually from each subject country has been below the net sales realization of the domestic industry over the injury period. Thus, the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market. The extent of undercutting has increased in the POI.
- g) If adjusted data at optimum level is considered, it would be seen that whereas the optimized cost of sales increased, selling price increased over the injury period however the increase in selling price is much less than the increase in costs. The landed prices of the subject imports remained much below the optimized cost of sales too throughout the injury investigation period. Thus, it can be seen that the imports have had a suppressing and depressing effect on the prices of the domestic industry.
- h) The petitioner has also compared the landed price of the subject goods with the optimized non-injurious price of the domestic industry. A comparison of the two clearly shows that the landed price of the subject goods is much below the non-injurious price, resulting in positive underselling and/or injury margin from all the subject countries.
- i) There has been significant increase in imports in absolute terms as well as in relative terms. Further, imports are undercutting the domestic price and the price undercutting led to depressing effect on the prices of domestic industry in the market and the effect of such dumped imports is likely to further suppress and depress the prices to a significant degree.
- j) The production and sales of the domestic industry has declined over the injury period. While it is accepted that the decrease in production and sales is also attributed to the shutdown that the domestic industry had to undertake, petitioner submits that significant low priced imports from subject countries have led to the decline in the prices in the market even when the domestic industry was having much lower volumes to sell.
- k) The market share of the domestic industry has declined over the injury period, even after adjusting the production for the effect of shutdown suffered and appropriately adjusting the sales. However, despite such low volumes and market share with the domestic industry, the foreign producers reduced their prices significantly.
- l) The profits of the petitioner company increased in 2014-15 after which they show a decline in 2015-16 and turned negative in the period of investigation. The cash profits also show the same trend as that of profits and turned negative in the period of investigation. The ROCE of the petitioner company shows a continual decline throughout the injury investigation period. While petitioner considers that their operations were impacted both by low priced imports and consequent financial constraints faced by industry; in order to clearly establish that the domestic industry would have suffered injury in this period even if they would have produced to the extent of optimum production in the past, the petitioner has determined the profitability of domestic industry considering the production achieved in the past. Further, in view of the fact that the number of different product types were sold during the relevant period, the product mix of the industry as maintained in 2015-16 was considered in order to determine the profitability of the domestic industry as would have been prevalent during the POI. The relevant profitability statement is enclosed on confidential basis. Accordingly, petitioner has updated the injury statement showing the position as would have prevailed, had the domestic industry produced at the level of optimum production. It would be seen that the domestic industry would have still suffered financial losses. Evidently, the domestic industry has suffered because of low price dumped imports of the PUC from subject countries. The landed price of imports is below the level of selling price and cost of sales of the domestic industry. The significant increase in low priced imports are likely to lead to losses to the domestic industry.
- m) The inventories of the domestic industry increased till 2015-16 but declined in the period of investigation. It is also to be noted that despite undertaking shut down and having to produce and sell reduced quantities, the level of inventory remained significant. The employment levels of the domestic industry and wages paid too show a continuous decline throughout the investigation period.
- n) The existing capacity with the petitioner is largely unutilized. With current capacity being unutilized and losses being incurred by the domestic industry, the ability of the petitioner to raise capital has weakened.

- o) The impact of dumping of the subject goods from the subject countries has been adverse on the domestic industry. The petitioner has calculated dumping margin which is positive and significant.
- p) The imports of the subject goods from the subject countries have increased throughout the injury investigation period. There was a continuous increase in the volumes of the subject imports. Imports even after adjustment for the shutdown that the domestic industry had to undertake, shows an increasing trend, which clearly shows that the increase in imports was not solely because of suspension of production by the petitioner. This clearly shows threat of further increase in imports to the already existing high volumes of the dumped imports. Such rise in the import volumes coupled with unfair prices will decimate the domestic industry.
- q) There has been a decline in the production as well as the demand of the PUC in China. However, the decline in demand is much more than the decline in capacity and production. It can be seen that the demand is almost half of the total capacity in China in the year 2017. This alone signifies the extent of unused capacities and inventory levels in China.
- r) The development of Coated Paper in China was done in two phases, from 2009 to 2011 and from 2011 to 2015. During 2009-2011, the main objective of the Chinese producers was to go into an expansion mode and set up huge capacities for the product concerned. This led to a rise in the capacity levels from 5.79 million tons in 2009 to 7.99 million tons in 2011. This eventually led to an increase in the production levels of the product concerned. The same increased from 5 million tons in 2009 to 6.71 million tons in 2011.
- s) The second phase of the Coated Paper industry in China PR was from 2011 to 2015. The Chinese producers faced the problem of over capacities in this phase that emerged from the massive expansion steps taken in the first phase. It was more so impacted because of the rise in the usage of electronic media and the reduction in the print media advertising along with the decline in demand and idle capacities because of the first phase expansion.
- t) The level of inventories available with the producers in subject countries could not be ascertained by the domestic industry. However, in view of the fact of significant capacity available with the producers in the subject countries and the decline in demand of the PUC in the subject countries, it can be fairly assumed that the foreign producers can scale up production in a short period and still do hold significant inventory levels.
- u) Petitioner has presented an elaborate non-attribution analysis in the petition and established that (a) the listed known factors have not caused claimed injury to the domestic industry, (b) there are no factors other than dumped imports that are causing injury to the domestic industry. At the same time, it is not a legal mandate that the dumping of the product under consideration should be the sole cause of injury to the domestic industry. So long as dumping is one of the causes of injury to the domestic industry, it must be concluded that causal link requirements are met.
- v) The imports of product under consideration from other countries are either negligible in volume or are at higher prices; the claimed injury is on account of domestic operations and not on account of export sales as is evident from costing and injury information provided for domestic sales separately; the technology as also the production process for producing subject goods has not undergone any significant development/change; performance of other products being produced and sold by the petitioner is not a possible cause of injury to the domestic industry as the information provided is only for the subject goods; there is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the domestic industry.
- w) Petitioner Company is a part of an established responsible corporate Ballarpur Industries Limited (BILT) which is India's largest manufacturer of writing and printing (W&P) paper and has a good investor relationship. All the information is regularly published on the website of the companies. The fact of shut down has been specifically mentioned in the annual report which is a part of the petition filed. Thus, it was not the intention of the domestic industry to mislead or hide facts from the Authority.
- x) Petitioner has two plants, at some time one plant was shut and for some time the other plant. Thus, there was reduction in the production level of the petitioner; however there was production for most of the months. Further, petitioner sold the subject goods during all the months covered in the POI as would be seen from the Q-15 filed by the petitioner along with the petition filed earlier. Further, even for those months when the domestic industry had significant production, imports show positive dumping and injury margin. The level of margins is also similar. Thus, there is no change in the behaviour of the exporters irrespective of the fact of the quantity of domestic industry's production. Thus, even if the domestic industry had been producing continuously the fact of dumping and injury would have remained true.
- y) Domestic industry has also supplied the information relating to the shutdown. The information still shows increase in imports causing injury to the Domestic Industry at the optimum costs of the domestic industry which were based on the capacity utilization levels as were achieved in 2015-16 and the same would evidence that despite considering those costs, the domestic industry has been a victim of the injury caused by unfairly priced imports from the subject countries. The data clearly shows even at those optimum levels the domestic industry would and is suffering injury and the imports by the subject countries are being dumped.

- z) Production by the domestic industry declined during the POI because of the shutdown faced by the domestic industry. But despite that shutdown, it can be seen that the landed prices of the subject imports declined significantly during the POI. The revised information attached with the written submission would show that even if the production during POI was adjusted on the basis of the capacity utilization levels achieved by the Domestic Industry in 2015-16, there was an increase in import volumes throughout the injury investigation period, the imports increased significantly in the POI with a decline in prices. Even at those adjusted levels, the imports are being dumped into the country leading to an increase in the already existing injury to the domestic industry. In any case, demand supply gap does not justify dumping.
- aa) The contention of various interested parties that the injury is due to other factors and not because of the imports is incorrect. As stated earlier, while petitioner considers that their operations were impacted both by low priced imports and consequent financial constraints faced by industry; in order to clearly establish that the domestic industry would have suffered injury in this period even if they had produced to the extent of optimum production in the past, petitioner has determined the profitability of domestic industry considering the production achieved in the past. Further, in view of the fact that the number of different product types were sold during the relevant period, the product mix of the industry as maintained in 2015-16 was considered in order to determine the profitability of the domestic industry as would have prevailed during the POI. It would be seen that the domestic industry would have still suffered financial losses. Evidently, the domestic industry has suffered because of low price dumped imports of the PUC from subject countries.
- bb) All the conditions for cumulative assessment are fulfilled in the present case. In particular, the imports from EU is competing with goods exported from China and USA as well as goods produced and sold by the domestic industry and thus cumulative assessment is justified. Further, if the prices are higher from EU then it will get a lower injury margin and thereby lower quantum of duty.

H.2. Submission by other interested parties

54. The submissions made by the exporters, importers, users and other interested parties with regard to injury and causal link, considered relevant by the Authority, are as follows:
 - a) The performance of BILT deteriorated due the phenomenal increase in their cost which is mainly on account of sudden increase in their finance cost and selling expenses. Therefore, it is submitted that the Domestic Industry has not suffered any injury on account of the allegedly dumped imports but the injury to them is on account of factors other than the imports.
 - b) The petitioner company is suffering injury because of bad investment decisions and other liquidity issues. There is no relationship between the imports from subject countries and performance of the Domestic Industry.
 - c) Anti-dumping duties on the raw material (Sodium Chlorate) has impacted the business relating to the Product under Consideration.
 - d) Other player in the market namely J K Paper is doing exceedingly well. They achieved the highest production of paper in their history - 4.70 lakh MT in 2016-17 against 4.50 lakh MT in the previous year. Their output during the year under review corresponded to a capacity utilization of 103 per cent as against 99 per cent in 2015-16. The company also produced 2.82 Lakh MT of pulp.
 - e) There is no causal link between the allegedly dumped imports and the injury to the Domestic Industry. Therefore, the Authority is requested to terminate the present investigation in view of the fact that any injury suffered by the Domestic Industry is caused by factors other than imports and the same is not at all linked to the allegedly dumped imports. It may be noted that it is for the first time that the petitioner has provided revised injury information taking into consideration the three subject countries in its written submissions and the evidence relating to the threat of material injury to the Domestic Industry. It may kindly be noted that neither the petition filed by the Domestic Industry nor the initiation notification even remotely indicates that the investigation proposes to examine the "threat of material injury" also. Clearly, the "threat of material injury" being inherently different from material injury in terms of rule 11, such a claim cannot be entertained at this stage of the investigation. In this regard, the responding parties submit that such new information cannot be taken into consideration at this stage of the investigation. Effectively, the petitioner, by way of the said additional information has revised the entire application which is not only against the express provisions of law but are also grossly violative of the basic principles of natural justice. Acceptance of additional information from the Domestic Industry, which de facto amounts to a new application, is not envisaged in law and completely undermines the very purpose of the oral hearing.
 - f) Further, it has been the consistent practice of the Authority to reject the data and evidence filed after the public hearing. The Authority has been consistently rejecting the data and information filed at the belated stage of the investigation for the reason that other parties do not get an opportunity to present their view on such data. Therefore, it is requested that the Authority may kindly reject the new information submitted by the petitioner after the hearing and disregard such information while making the determination in the present case.

- g) The Domestic Industry has suffered injury on account of its prolonged shut down, inefficient management, financial turmoil and unviable investment decisions. It is a matter of record that the Domestic Industry has been facing financial constraints for past few years and their costs have skyrocketed.
- h) The conditions of competition between EU products, imports from the US and China and the domestic products do not support a cumulative assessment. Imports from EU have not caused any injury to the domestic industry and therefore no measures should be imposed against imports from the EU.
- i) There is a lack of causality, as the injury allegedly suffered by the domestic industry is not related to the increase in imports but is in fact self-inflicted.
- j) The facts on the record reveal that, the petitioner has exaggerated the increased imports of the subject product, and deliberately invented material injury to the domestic industry. If the investigating authority continues the investigation, it shall be determined that there is no increase in imports of the subject product which has caused injury to the petitioner.
- k) Initially, the application for initiation of present anti-dumping investigation was filed against five subject countries namely China PR, EU, Indonesia, South Korea and USA. However, the Designated Authority vide its initiation notification excluded Indonesia and Korea RP from the scope of present investigation. With the exclusion of Indonesia and Korea RP, import volumes as represented in the petition have changed, however, the petitioner has not provided the revised information to the interested parties.
- l) The capacity remains unchanged during the injury period and POI. The production and capacity utilization have declined during the POI substantially. The reasons for such decline are working capital and raw material constraints faced by M/s. BILT Graphic Paper Products Limited. Annual report of Ballarpur Industries Limited (holding company of BILT) for the financial year 2016-17 states that BILT has a large debt position, which is causing injury to the Domestic Industry and certainly not the imports from subject countries. It was also submitted by the petitioner that the production in their plant was suspended for 12 months i.e. from July 2016 to June 2017. Out of the total 15 months of period of investigation, the production in the plant was suspended for 12 months.
- m) As shown in Proforma IVA, enclosed with the petition, inventories have reduced during the POI as compared to the base year 2013-14. Due to working capital constraints and shortage of raw material, Domestic Industry is not able to produce enough quantity to satisfy the demand of Indian users. In such a situation, imports tend to increase to fill the demand and supply gap in India, and surely not cause injury to the Domestic Industry. Thus, imports are nowhere causing injury to the Domestic Industry.
- n) The cost of sale of Domestic Industry has increased substantially during the POI, from 100 during the base year 2013-14 to 154 during the POI. However, there was no such increase in the cost of raw material in the prevailing market. Price undercutting has remained unchanged during the entire injury period and POI.
- o) The profitability of the Domestic Industry has improved from 100 during the base year 2013-14 to 102 in 2015-16, net fixed assets and working capital of the petitioner have increased significantly during the POI as compared to the base year 2013-14. Net Fixed Assets have increased from 100 to 130 during the POI as compared to base year, 2013-14. Working Capital has increased from 100 to 163 during the POI as compared to the base year 2013-14. The Director General Trade Remedies is requested to critically examine the same.
- p) The Petition claims that the volume and price injury suffered by the Petitioner is due to the increase in imports from the subject countries. However, this claim is simply the Petitioner characterizing the effect as the cause. The Petition clearly shows that any injury allegedly suffered by the Petitioner was self-inflicted and the Petitioner itself admitted this at the Public Hearing. This is also confirmed by the fact that no other Indian producer has been loss-making. Petitioner's low production created a supply shortage and there was inevitable import substitution due to the local shortage as the demand for the Product under Consideration remained at the same level throughout the injury period.
- q) The Petitioner claims price undercutting of 15-25% for subject imports throughout the POI and injury period. If the price undercutting was causing injury, the Petitioner should have observed losses throughout the period.
- r) The Petition shows an abrupt increase in cost during the POI which was not experienced by the rest of the industry. The Authority is requested to analyse the cost of other co-operating producers which would not reflect the abovementioned increase in cost.
- s) The Petitioner has also been suffering considerable injury due to its production of uncoated paper where in a separate investigation the Petitioner has claimed volume injury. This has led to substantial decline in the Petitioner's production of uncoated paper as well.
- t) The Petitioner has claimed that profitability and cash profits have declined drastically and that there were heavy losses during the POI. Respondent refers to the Annual Reports of the Petitioner which show sharp rises in finance

costs which would directly affect their profitability. The Annual reports also show healthy PBIT and Return on Capital Employed.

- u) The Petitioner itself admitted at the Public Hearing that their plant had been shut down for 12 out of 15 months of the POI. It is obvious after such an admission that any injury would be self-inflicted and the entire case for anti-dumping duties is a sham. Dumped imports may cause injury to volume and price parameters but they certainly cannot cause the plant shutdown.
- v) The data available in the Petition only reflects the performance data of one entity in India and is not reflective of the status of the Indian domestic market. Other producers such as JK Paper and ITC Ltd have been performing at adequate levels and it is only the Petitioner that has been suffering adverse economic effects which are self-inflicted.
- w) The Domestic Industry submitted that JK Paper has imported the PUC and has not opposed the investigation in the Public Hearing. It is submitted that regardless of JK Paper's imports it becomes important to consider their performance data as they are one of the largest domestic producers.
- x) The Petitioner acquired a subsidiary in Malaysia that it failed to make profitable in 2007 and had thus tried to sell in 2015. It was only able to divest itself of the failed investment in 2018. This caused delays in the Petitioner's deleveraging and refinancing attempts. Sources close to the Petitioner also confirm that there were overarching financial problems within the Petitioner's group. In view of the non-attribution factors faced by the Petitioner, it is submitted that the Hon'ble Designated Authority should consider that there is no causal link between the imports and alleged injury and that the, the alleged injury is self-inflicted. The calculation of injury would be illogical due to the fact that it is calculated in context of the plant being shut down for 12 out of 15 months of the POI and that if the injury is still determined then the Hon'ble Designated Authority would have to consider the reworking of the cost to make and sell as well as NIP calculations after segregating the extraordinary expenses incurred during the shutdown period especially during the POI as it was a self-inflicted phenomenon.
- y) It is submitted that in light of the present investigation being an original matter and not a SSR investigation there is no need for the consideration of the Post – POI data. Consideration of the Post – POI data would be inconsistent with the past practice of the Hon'ble Designated Authority.
- z) The volume injury analysis has been conducted in a cumulated manner which would not be equitable considering the EU has not been excluded even though Korea RP and Indonesia have very similar data.
- aa) It is submitted that considering that landed prices have not declined as averred earlier, the alleged injury was caused by self-inflicted adverse business conditions. The Petitioner has not given any reasons as to how the alleged low prices of imports have led to the plant shutdown.
- bb) Domestic industry did not provide any information regarding the shutdown of the production of the domestic industry during the POI in the Petition. Domestic industry also did not provide for any known factors other than alleged dumped imports to be causing injury to the domestic industry. During the public hearing i.e. nearly six months after the initiation of investigation, domestic industry for the first time specifically submitted that there was shutdown of production from July 2016 to June 2017 and admitted that injury is also caused due to working capital constraints which is required to be adjusted.
- cc) Period of investigation in the present anti-dumping investigation is from April 2016 to June 2017. Out of this 15 months period, domestic industry was not operational between June 2016 to July 2017 i.e. for total 12 months. Moreover, as admitted by the domestic industry and as also elaborated in the submission subsequently, it is clear that the shut-down of domestic industry was due to working capital constraints faced by the domestic industry. Respondent submits that no proper assessment of dumping, injury or causal link can be made based on the three months operation period. Injury determination based on such short period will not be representative and would present a distorted picture. For a correct assessment of injury, the Designated Authority should select the POI in which the domestic industry was operational for majority of the period.
- dd) Respondent understands that there is no great variance in the manufacturing process of uncoated paper and coated paper. Uncoated paper is coated by a compound or polymer to impart certain qualities to the paper, such as weight, surface gloss, smoothness or reduced ink absorbency. Accordingly, there should be parity between cost of production or cost of sales for uncoated paper and coated paper.
- ee) There is significant variance in trend in the cost of sales of coated paper as compared to the cost of sales of uncoated paper provided by the domestic industry in the ongoing anti-dumping investigation on import of "Uncoated Copier Paper" from Indonesia, Thailand and Singapore.

Cost of Sales	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI (A)
Uncoated paper*	Rs/MT - Index	100	101	100	99
Coated paper**	Index	100	99	98	154

* Petition of domestic industry in anti-dumping investigation on uncoated paper

** Current Petition

- ff) Annexure II, para (iv) of the Anti-dumping Rules and Article 3.4 of the Anti-dumping Agreement provides for list of mandatory economic parameters, which are required to be examined by the Designated Authority. Productivity, return on investments, cash flow, wages, growth are mandatory parameters prescribed under para (iv), Annexure II of the Anti-dumping Rules. Domestic industry has not provided any information regarding some of these parameters. No claim regarding existence of material injury can be made if no information is provided at all regarding these mandatory injury parameters.
- gg) The raw materials that can be used for manufacture of paper are wood, pulp, agricultural residue (bagasse, wheat straw, rice husk, etc) and waste paper. It is an admitted fact by the paper industry in India that there is a shortfall in the availability of wood-pulp in India which leads to high raw material prices. The paper industry in India has to import most of its raw material requirements from the international market. It is also admitted that due to higher raw material cost, existing capacity of Petitioner has remained underutilized. Therefore, the Respondent submits that it is on account of the shortage of the aforementioned raw materials that the domestic industry is suffering injury.
- hh) The Domestic Industry has provided revised figures of import volume and value from subject countries for the entire injury investigation period without providing any explanation for such change in figures. It has merely stated that updated import data is provided along with detailed import methodology for segregation of product under consideration (PUC) and non-PUC.

H.3. Examination of the Authority

55. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties and has examined various parameters in accordance with the Anti-Dumping Rules after duly considering the submissions made by the interested parties.

Cumulative Assessment

56. Para (iii) of Annexure II of the Anti-Dumping Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
- Margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article; and
 - Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in the light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
57. The Authority notes that:
- The subject goods are being dumped into India from subject countries. The margin of dumping from each of the subject countries is more than the de minimis limits prescribed under the Rules.
 - The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of total volume of imports.
 - Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete inter se but also with the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.
58. In view of the above, the Authority considers that it is appropriate to assess injury to the domestic industry cumulatively from exports of the subject goods from the subject countries.
59. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as

compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.

60. The Authority notes that BGPPL was not producing the subject goods for a major part of the POI due to its own intrinsic reasons. The Authority in order to arrive at a fair conclusion requested the information from M/s. JK Paper Ltd., a major producer of the subject goods for injury analysis. Accordingly, the Authority considered the data of M/s. JK Paper Ltd. also separately apart from BGPPL data for the injury and causal link assessment in the later part of the final findings.
61. The submissions made by the domestic industry and other interested parties during the course of investigations with regard to injury and causal link, which have been considered relevant by the Authority are examined and addressed as under:

H.4. Volume Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

(a) Assessment of Demand/Apparent Consumption

62. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources. The demand so assessed has increased consistently during the injury investigation period and the POI (A).

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI(A)
Domestic Industry sales	MT	***	***	***	***
Sales – JK Paper Ltd.	MT	***	***	***	***
Sales – Sehasayee Paper	MT	***	***	***	***
Imports from subject countries	MT	4,22,136	4,48,579	4,53,452	6,18,075
Other imports	MT	76,073	1,15,430	1,68,398	1,91,571
Demand/consumption	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	108	116	123

(b) Import Volumes from subject countries

63. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports from subject countries, either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI (A)
Undumped imports from EU	MT	24,755	28,666	26,647	31,611
Dumped imports from EU	MT	88,692	1,05,312	1,24,424	1,41,405
China PR	MT	1,95,124	2,15,054	1,83,540	2,93,269
USA	MT	1,13,566	99,547	1,18,841	1,51,790
Undumped imports from subject countries	MT	24,755	28,666	26,647	31,611
Dumped imports from subject countries	MT	3,97,382	4,19,913	4,26,805	5,86,464
Other Countries	MT	76,073	1,15,430	1,68,398	1,91,571
Total Imports	MT	4,98,210	5,64,009	6,21,850	8,09,646

64. It is seen that dumped imports of the subject goods from the subject countries have increased in absolute terms during the POI (A). The primary reason for significant increase in dumped imports during POI (A) is the shutdown of BGGPL for major part of the POI(A).

(c) Subject Country Imports in relative terms

Particular	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI (A)
Dumped imports from subject Countries in relation to Production in India	%	120-130	130-140	130-140	380-390
Dumped imports from subject Countries in relation to Demand in India	%	40-50	40-50	40-50	50-60

65. It is seen that the subject dumped imports in relation to production and demand increased in the POI (A) as compared to the base year and previous years. The primary reason for significant increase in dumped imports during POI (A) is the shutdown of BGPPL for major part of the POI (A).

(d) Market Share in Demand

66. Considering imports from various sources and sales of the domestic industry, market share of subject dumped imports in demand in India was examined. The Authority notes that the market share of the subject imports increased significantly in the POI (A). Market share of the domestic industry has declined significantly during the POI (A). The market share of other Indian producers has more or less remained the same during injury investigation period. However, the market share of all domestic producers including domestic industry has fallen significantly during the POI (A). This is mainly due to fall in production/ sales of BGPPL. The space created by decline in the market share of the domestic industry has been occupied by the imports from subject countries and also imports from other countries.

Particular	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI (A)
Domestic Industry	%	30-40	20-30	20-30	10-20
Other Indian Producers	%	0-10	0-10	0-10	0-10
Total market share of all domestic producers	%	30-40	30-40	30-40	10-20
Dumped subject imports	%	40-50	40-50	40-50	50-60
Undumped & Other imports	%	10-20	10-20	20-30	20-30
Total	%	100	100	100	100

H.5. Price Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

67. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from subject countries has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject countries.

(a) Price Undercutting

68. For the purpose of price undercutting analysis, the net selling price of the domestic industry has been compared with the landed value of imports from the subject countries. While computing the net selling price of the domestic industry all taxes, rebates, discounts and commissions have been deducted and sales realization at ex works level has been determined for comparison with the landed value of the dumped imports. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject countries work out as follows:

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI
<u>China PR</u>					
Landed price of imports	Rs/MT	50,910	50,014	50,964	49,138
Net Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
Range		15 - 25	25 - 35	15 - 25	20 - 30
<u>EU</u>					
Landed price of imports	Rs/MT	57,508	55,844	54,629	52,864
Net Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
Range		5 - 15	5 - 15	5 - 15	10 - 20
<u>USA</u>					
Landed price of imports	Rs/MT	31,765	32,106	33,948	34,966
Net Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
Range		85 - 95	95 - 105	75 - 85	70 - 80

From the aforesaid table, it can be seen that the price undercutting from the subject countries during the injury period as well as in POI (A) is positive.

(b) Price Suppression and Depression

69. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, were compared as below:

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI (A)
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	99	98	154
Selling price	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	104	99	102
Landed Value	Rs./MT	47,533	47,781	47,725	46,700
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	101	100	98

70. From the above table, it can be seen that the selling price of BGGPL has been higher than cost of sales till 2015-16. However, the selling price is lower than the cost of sales during the POI (A). The cost of sales has increased by 56 indexed points during POI (A) as compared to 2015 - 16.

(c) Price Underselling

71. The non-injurious price (NIP) of the domestic industry has been determined and compared with the landed value of the subject goods to arrive at the extent of price underselling. The NIP of the product under consideration has been

determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation on the basis of principles mentioned in Annexure III of the Rules. The NIP has been determined considering optimum level of capacity utilisation that the Petitioners can achieve in the plant. The analysis shows that during the period of investigation, the landed value of subject imports was below the non-injurious price of the domestic industry, as can be seen from the table below, demonstrating positive price underselling effect:

Particulars	Unit	POI (Rs/MT)	POI (USD/MT)
<u>China PR</u>			
Landed Price	Per MT	49,138	728.51
Non-Injurious Price (NIP)	Per MT	***	***
Price underselling	Per MT	***	***
Price underselling	%	***	***
Price underselling	% Range	20 - 30	20 - 30
<u>EU</u>			
Landed Price	Per MT	52,864	781.62
Non-Injurious Price (NIP)	Per MT	***	***
Price underselling	Per MT	***	***
Price underselling	%	***	***
Price underselling	% Range	10 - 20	10 - 20
<u>USA</u>			
Landed Price	Per MT	34,966	516.99
Non-Injurious Price (NIP)	Per MT	***	***
Price underselling	Per MT	***	***
Price underselling	%	***	***
Price underselling	% Range	70 - 80	70 - 80

72. From the aforesaid table, it can be seen that the price underselling from the subject countries during the POI is positive. However, from a combined reading of the table for price undercutting and price underselling, it can be seen that the selling price of the domestic industry during POI is higher than the NIP determined by the Authority. This fact leads to the conclusion that the cost of sales of the domestic industry is exorbitantly high during the POI due to the effect of shutdown for a major part of the POI. It also demonstrates that the dumped imports from the subject countries did not stop the domestic industry from realising a fair price for their product during the POI.

H.6. Economic Parameters of the Domestic Industry

73. Annexure II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Anti-dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.
74. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.
- (a) Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales

75. Capacity, production, capacity utilization and sales of the domestic industry over the injury period is given in the following table: -

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI-A
Capacity Total	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	100	100	100
Production- Total	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	99	101	36
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	99	101	36
Sales Domestic	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	98	99	42

76. From the above table, it is noted that:

- Capacity of the domestic industry has remained constant since 2013-14.
- Capacity utilisation of domestic industry has improved till 2015 - 16 and declined during the POI (A) due to the fact that the Domestic Industry was not operational for major part of POI.
- Production of the domestic industry improved till 2015-16 and has declined during the POI (A) due to the fact that the Domestic Industry was not operational for major part of POI.

(b) Profitability, return on investment and cash profits

77. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is given in the table below: -

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI-A
Profit/ Loss	Rs/MT	***	***	***	(***)
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	137	102	-256
Profit/ Loss	Rs.Lacs	***	***	***	(***)
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	134	101	-109
Profit before Interest and Tax	Rs.Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	125	106	6
Cash Profit	Rs.Lacs	***	***	***	(***)
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	112	86	-56
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	92	75	1.4

78. From the above table, it is noted that:

- Profitability of domestic industry has been good till 2015 - 16. However, profitability of domestic industry declined and turned into losses during the POI (A).
- Similarly, profit before interest and cash profits of domestic industry have been good till 2015 – 16 but declined during POI (A). However, return on capital employed witnessed declining trend during entire injury period and reduced drastically during POI (A).

(c) Employment, productivity and wages

79. Employment, productivity and wages of Domestic Industry over the injury period is given in the table below.

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI-A
Employment - DI	Nos	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	99	98	93
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	123	117	97
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	100	102	39
Productivity per day	Mt/Day	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	99	101	36

80. It is noted that the Productivity per day and productivity per employee of the domestic industry remained constant with negligible change through out the injury investigation period and has declined drastically during the POI (A). This is primarily due to the fact that the Domestic Industry was not operational for a major part of POI.

(d) Inventories

81. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI-A
Average stock	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	104	131	72

82. It is noted that the inventories with the domestic industry have declined during the POI (A).

(e) Growth

83. The production, capacity utilisation, domestic sales and profitability of the domestic industry have been stable till 2015-16 and thereafter sharply deteriorated during the POI (A). However, return on capital employed witnessed declining trend during entire injury period and reduced drastically during POI (A).

Particulars (Year on Year)	2013-14	2014-15	2015-16	POI-A
Production		-1%	2%	-64%
Capacity Utilization		-1%	2%	-64%
Domestic Sales		-2%	1%	-57%
Cost of Sales		-1%	-1%	57%
Selling Price		4%	-5%	3%
Profit/ Loss		37%	-25%	-350%
Return on investment		-8%	-19%	-95%

(f) Ability to Raise Capital Investments

84. Domestic Industry claimed that the current state of its financial position does not allow them to raise capital for fresh investment. It is noted that the financial position of the domestic industry has deteriorated due to its own intrinsic reasons and has no relation with the imports coming from subject countries

(g) Factors affecting domestic prices

85. The domestic industry is able to more or less maintain its selling price within a range. However, the cost of production of domestic industry has significantly increased during the POI (A) due to the effect of shutdown for a major part of the POI (A). It can be seen that the selling price of the domestic industry during POI (A) is higher than the NIP determined by the Authority.

I. Threat of Material Injury

86. The provisions relating to threat of material injury are provided in para vii of Annexure II of AD Rules and provide as follows:

(vii) *A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances which would create a situation in which the dumping would cause injury must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the designated Authority shall consider, inter alia, such factors as:*

(a) *a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;*

(b) *sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;*

(c) *whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and*

(d) *inventories of the article being investigated.*

87. A threat of material injury is a situation where the domestic industry has not suffered during the injury period but injury to the domestic industry is imminent if the present circumstances continue. A 'threat of material injury' means clear and imminent danger of injury. The determination of threat of material injury should be based on facts, and not merely on allegation, conjectures, imagination, or remote possibilities.

88. With respect to threat of material injury, the Authority notes as under:

a) There is substantial increase in imports of subject goods from subject countries in absolute terms as well as in relation to production & consumption in India. However, the increase in imports from subject countries was necessitated due to decline in production of the domestic industry.

b) Further, Authority has examined the capacity details of the co-operative producers/exporters from the subject countries and it is noted that no significant capacity has been added by any of the co-operative producers.

c) Authority has examined the inventory of the co-operative producers/exporters from subject countries and it is noted that none of them hold any significant inventory.

I.1. Magnitude of Injury and Injury Margin

89. The Authority has determined Non-Injurious Price for the domestic industry on the basis of principles laid down in Anti-Dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The NIP of the domestic industry has been worked out and it has been considered for comparing the landed price from each of the subject countries for calculating injury margin. For determining NIP, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been done with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. The production in POI has been calculated considering the best capacity utilisation and the same production has been considered for arriving per unit fixed cost. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. Average Net Fixed Assets plus Average Working Capital) for the product under consideration was allowed to arrive at the NIP as prescribed in Annexure-III of AD Rules. The non-injurious price so determined has been compared with the landed prices of imports from the subject countries to determine the injury margin as follows;

S. No.	Producer Country	Producer	Exporter	NIP (USD/MT)	Landed Value (USD/MT)	Injury Margin (USD/MT)	Injury Margin %	Range
1	China PR	a. M/s Shouguan g Meilun Paper Co., Ltd. b. M/s Shandong Chenming Paper Holdings	M/s Chenming (HK) Limited	***	***	***	***	20-30

		Ltd.,						
2	China PR	Gold East Trading (Hong Kong) Company Limited	Gold East Trading (Hong Kong) Company Limited	***	***	***	***	40-50
3	China PR	All Others	All Others	***	***	***	***	40-50
4.	European Union	a. Sappi Alfeld GmbH b. Sappi Enningen GmbH c. Sappi Gratkorn GmbH d. Sappi Finland Operations Oy (Kirkniemi) e. Sappi Lanaken NV f. Sappi Maastricht B.V g. Sappi Stockstadt GmbH	a. Sappi Europe SA b. PG per Company Ltd	***	***	***	***	15-25
5.	European Union	a. M/s. UPM Communication Papers Oy b. M/s. UPM Specialty Papers Oy, c. UPM GmbH	M/s. UPM Sales Oy	***	***	***	***	0-5
6.	European Union	All Others	All Others	***	***	***	***	50-60
7.	USA	All	All	***	***	***	***	25-35

J. Non-Attribution Analysis

90. As per the AD Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry.

(a) Volume and price of imports from third countries

91. The Authority notes that there were significant imports of the product under consideration from non-subject countries.

(b) Export Performance

92. The Authority has considered the data for domestic operations only for its injury analysis.

(c) Development of Technology

93. None of the interested parties have raised any issue with regard to developments in technology as being the cause of injury to the domestic industry.

(d) Performance of other products of the company

94. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the Petitioners does not appear to be a possible cause of injury to the domestic industry.

(e) Trade Restrictive Practices and Competition between the Foreign and Domestic producers

95. The import of the subject goods is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. No evidence has been submitted by any interested party to suggest that the conditions of competition between the foreign and the domestic producers have undergone any change.

(f) Contraction in Demand and Changes in pattern of consumption

96. It is noted that the demand of the subject goods has increased consistently over the entire injury period.

97. The Authority has taken note of the submissions made by various interested parties to analyse the performance of M/s JK Paper Ltd. The Authority therefore requested petitioner to submit relevant information to examine key economic parameters of M/s JK Paper Ltd. to arrive at a fair conclusion regarding the causal link between the dumped imports from the subject countries and injury suffered by the domestic industry. The Authority has analysed key injury parameters based on the information submitted by M/s. JK Paper Ltd. as under:

J.1. Price Effect of Dumped Imports on JK Paper Ltd.**(a) Price Undercutting**

98. For the purpose of price undercutting analysis, the net selling price of the JK Paper Ltd. has been compared with the landed value of imports from the subject countries. While computing the net selling price of the JK Paper Ltd. all taxes, rebates, discounts and commissions have been deducted and sales realization at ex works level has been determined for comparison with the landed value of the dumped imports. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject countries work out as follows:

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI-A
China PR					
Landed price of imports	Rs/MT	50,910	50,014	50,964	49,138
Net Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
Range		0 – (10)	0 – 10	0 – (10)	0 – 10
EU					
Landed price of imports	Rs/MT	57,508	55,844	54,629	52,864
Net Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
Range		(10) – (20)	0 – (10)	(10) – (20)	0 – (10)
USA					
Landed price of imports	Rs/MT	31,765	32,106	33,948	34,966
Net Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
Range		50 - 60	50 - 60	40 - 50	40 - 50

99. From the aforesaid tables, it can be seen that the price undercutting from EU during the injury investigation period as well as in POI (A) is negative whereas price undercutting from China PR and USA is positive during POI (A).

(b) Price Suppression and Depression

100. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, were compared as below:

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI (A)
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	95	80	78
Selling price	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	102	98	101
Landed Value	Rs./MT	47,533	47,781	47,725	46,700
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	101	100	98

101. From the above table, it can be seen that the cost of sales has decreased during POI (A) by 22 indexed points as compared to the base year whereas selling price has increased by 1 indexed point during POI (A) as compared to the base year. The landed value has decreased by 2 indexed points during POI (A) as compared to the base year. Thus, the imports from subject countries did not have any price suppressing or depressing effect on the sales of JK Paper Ltd.

J.2. Economic Parameters of M/s. JK Paper Ltd.

a) Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales

102. Capacity, production, capacity utilization and sales of the JK Paper Ltd. over the injury period is given in the following table: -

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI-A
Capacity Total	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	100	100	100
Production- Total	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	110	116	125
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	110	116	125
Sales Domestic	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	107	115	122

103. From the above table, it is noted that:

- Capacity of the JK Paper Ltd. has remained constant since 2013-14.
- Capacity utilisation of JK Paper Ltd. has improved throughout the injury investigation period and was at its peak (***) during the POI (A).
- Production & domestic sales of the JK Paper Ltd. significantly increased during the entire injury investigation period and during the POI (A).

b) Profitability, return on investment and cash profits

104. Profitability, return on investment and cash profits of the JK Paper Ltd. over the injury period is given in the table below: -

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI-A
Profit before Interest and Tax	Rs.Lacs	(***)	(***)	***	***

<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	-100	-49	7	31
Profit Before Tax	Rs.Lacs	(***)	(***)	(***)	(***)
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	-100	-77	-31	-12
Cash Profit	Rs.Lacs	(***)	(***)	(***)	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	-100	-79	-11	19
Return on Capital Employed	%	(***)	(***)	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	-100	-63	11	52

105. From the above table, it is noted that:

- a) Profitability of JK Paper Ltd. has improved during the POI (A) as compared to the base year.
- b) Similarly, cash profits and ROCE have significantly improved during POI (A) as compared to the base year.
- c) **Employment and productivity**

106. Employment and productivity of JK Paper Ltd. over the injury period is given in the table below.

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI-A
Employment	Nos	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	99	98	93
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	112	119	134
Productivity per day	Mt/Day	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	110	116	125

107. It is noted that the Productivity per day and productivity per employee has significantly improved during the POI (A) as compared to the base year.

d) Inventories

108. Inventory position with the JK Paper Ltd. over the injury period is given in the table below:

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI-A
Average stock	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	147	212	249

109. It is noted that the inventories with the JK Paper Ltd. has increased during the POI (A) as compared to the base year.

J.3. Conclusion on causal link:

110. The Authority notes as under:

- a) There is substantial increase in imports of subject goods from subject countries in absolute terms as well as in relation to production & consumption in India. However, the increase in imports from subject countries was necessitated due to decline in production of the domestic industry.
- b) With regard to BGPPL's volume parameters it is noted that capacity utilisation, production and domestic sales have improved throughout the injury investigation period and declined during the POI (A) due to shutdown of the plant for a significant period during the POI. On the other hand, capacity utilisation, production and domestic sales of JK Paper Ltd. have improved during the POI (A).

- c) Profit before interest and cash profits of domestic industry have been stable till 2015 – 16 and have declined during the POI (A). On the other hand, profit before interest and cash profits of JK Paper Ltd. have improved during POI (A).
- d) Selling price of BGPPL has been higher than cost of sales till 2015 – 16. However, the selling price is lower than cost of sales during the POI (A). The cost of sales of BGPPL has increased by 56 indexed points during POI (A) as compared to 2015 – 16. On the other hand, the cost of sales of JK paper Ltd. has decreased during the POI (A). This clearly shows that the cost of sales of BGPPL increased exorbitantly during POI (A) due to its shutdown for a major part of the period of investigation.
- e) The price undercutting with regard to BGPPL from the subject countries is positive during period of investigation.
- f) Price undercutting with regard to JK Paper from EU during the injury investigation period as well as in POI is negative and price undercutting from China PR and USA is positive during POI.
- g) The selling price of BGPPL during POI (A) is higher than the NIP determined by the Authority. This clearly demonstrates that the dumped imports from the subject countries did not stop the domestic industry from realising a fair price for their product during the POI.
- h) The fall in production, sales, capacity utilisation and profitability of BGPPL is clearly attributable to its own intrinsic factors and has no co-relation with the dumped imports from the subject countries.

K. POST DISCLOSURE COMMENTS

111. The post disclosure submissions have been received from the interested parties. Most of the issues raised therein have already been addressed by the Authority in the disclosure statement. The post disclosure comments from interested parties which have not been addressed earlier to the extent deemed fit are being examined below:

K.1. Submissions by Domestic Industry

112. Following are the post-disclosure comments made by the domestic industry:

- a) Subject goods below 80 GSM are proposed to be excluded from the scope of the investigation. Petitioner never agreed for such exclusion. This has been done without providing an opportunity to the domestic industry to defend its interests and without having material on record to show that the product range is not produced by the petitioner. A significant proportion of the production of petitioner is in the product range proposed to be excluded.
- b) The exclusion of the product range has been done on the basis of the previous investigation when the facts of that investigation were entirely different from the present investigation. Such proposed exclusion on the basis of ill-conceived information discreetly placed on record by other interested parties is illegal and has taken away the right of defence of the domestic industry in this regard.
- c) Petitioner company has neither imported the subject goods, nor is it related to an importer or exporter of the subject goods. Petitioner satisfies the standing requirement and constitutes the domestic industry in terms of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules.
- d) Despite considering complete information of JK Paper, authority remains silent on the status of JK paper as regard to eligibility of being domestic producer. The same may be disclosed.
- e) Excessive confidentiality has been claimed by other interested parties by not providing information in public version of the questionnaire responses. Exporters have even failed to show sufficient justification and/or reasoning for claiming confidentiality.
- f) Normal value for China and USA has been rightly determined on the basis of best available information. However, the authority has ignored submissions made with respect to the non-disclosure of information on related parties and incomplete value chains for Gold East Group, Shandong Paper Group, Sappi and UPM Paper groups. Dumping margins should be re-determined and it should also be considered that a significant part of imports from EU into India are at dumped prices.
- g) Even after segregation of dumped and undumped imports from EU, the volume of dumped imports has risen significantly. Imports from subject countries have risen significantly. Suspension of production necessitated imports but by no chance it meant imports at dumped prices and to the extent done. Because of such imports even after low production DI had to sell at sub-optimal prices.
- h) Import prices declined significantly in the POI without corresponding decline in raw material costs which resulted in injury to the domestic industry.

- i) Market share of subject imports increased while that of domestic industry declined. Revised information submitted shows that even if POI was adjusted on basis of capacity utilization levels achieved by the Domestic Industry in 2015-16, there are an increase in import volumes throughout the injury period with a decline in prices. Demand supply gap does not justify dumping.
- j) Landed prices of the imports declined without decline in raw material costs. While the cost of sales increased, selling prices declined. Level of undercutting has increased over the injury period.
- k) Even if optimized cost of sales is considered, it would be above the selling price of domestic industry. Landed prices of the imports remained much below the optimized cost of sales too. The imports have had a suppressing and depressing effect on the prices of the domestic industry.
- l) The imports are also underselling the prices of the domestic industry by a significant margin.
- m) Production of the domestic industry declined in the POI which resulted in decline in sales and capacity utilization. Even then low priced imports led to decline in prices in the market even when the domestic industry was having much lower volumes to sell.
- n) The petitioner suffered from reduced production level. Products were sold during all months of the POI. Even when production was significant, imports resulted in positive dumping and injury margins and there was no change in behaviour of exporters even if there was production or no production by domestic industry.
- o) Had the domestic industry not produced the product mix which gives higher return during the period, the losses would have been worse.
- p) Inventories declined in the POI but still remained significantly high considering the reduced production by the domestic industry.
- q) Losses were immense in the POI and PBIT declined significantly. Cash profits were negative and the ROI declined to barely positive levels. Even if optimum production levels achieved in the past and the product mix maintained in 2015-16 were considered, there would have still been losses.
- r) Dumping margins determined are more than injury margins, which shows that fair price determined for domestic industry is far higher than selling price of foreign producers.
- s) NIP for domestic industry is not at level of actual production but at level of optimum production. This shows that domestic industry is not less efficient than foreign producers and even then, it is suffering financial losses while foreign producers resort to dumping.
- t) As regards JK Paper performance – JK Paper was making losses in the base year whereas the petitioner was in profits. JK Paper gradually improved its consumption norms and efficiency which is the reason that its cost of sales showed decline.
- u) Cost of production of BILT was lower as compared to the cost of production of JK Paper even when BILT purchases pulp while JK Paper produces its own pulp. When performance of JK Paper is adjusted for losses suffered by JK Paper on account of lower production of pulp, profitability of BILT would remain better than profitability of JK Paper.
- v) With regard to improvement in production, sales and capacity utilization JK Paper has only regained its old position. The company only lost its position because of stabilization issues faced by new pulp mill.
- w) Reliance is placed on the extracts of the annual reports of JK paper which show that new Pulp Mill reduced their costs, difficulties in establishment of such mill. It is only an instance where company took some time to stabilize its costs. Further, annual reports of the company also acknowledge the fact of threat from imports.
- x) Despite suspension of production by petitioner and improvement in paper and sales of JK Paper, it is still incurring losses and earning a return much below the desired level because of dumped imports.
- y) Data provided by JK Paper has been adopted/used on “convenience” basis without seeking any clarifications from the company. Profitability of JK Paper has not increased as much as has been established in the disclosure statement. The ROCE of the company is significantly low and the inventories have increased significantly despite reduction in production by domestic industry.
- z) Authority has considered profit before interest while the relevant parameter is profit before tax. Deviating from its past practice in this regard is inappropriate. Profit before tax of JK Paper shows a declining situation of losses. Such losses reduced as the pulp mill stabilized and effect of such losses due to non-stabilization of pulp mill.
- aa) Authority determined price undercutting for EU negative because it considered much higher price in respect of imports from EU as compared to the petition. This is on account of differently adopted data by the authority.

- Authority is requested to disclose the DGCI&S data adopted. Further, average price undercutting considering JK Paper data is positive.
- bb) Despite considering costing information, NIP has not been determined for JK Paper. Petitioner determined NIP of JK Paper on basis of information adopted in the disclosure statement. It is seen that NIP of JK Paper is far higher than their NSR; Injury margin is quite high and NIP of JK Paper is comparable to NIP of petitioner.
 - cc) In a situation where a major producer suspended production, it is unusual that other producer faced increased inventory levels. Verification of DI data and foreign producer data was done but has not been done for JK paper. The information sought by the authority was provided by JK paper on the basis of the formats.
 - dd) As regards to threat of imports, the import volumes increased significantly with a decline in prices which came in without a decline in raw material costs. Such imports led to price undercutting. Further, demand-supply gap does not warrant unfairly priced imports as is the case in this investigation. NIP of the domestic industry determined is higher than their NSR.
 - ee) Even if the adjustment for shutdown is factored in the imports show an increase. This coupled with the decline in demand in the subject countries shows imminent threat of further material injury. Loss of demand in china alone is much more than entire Indian demand.
 - ff) The authority is required to analyse and examine the capacities of not only the responding exporters but also the non-responding exporters, analyse the additional planned capacities and then make a determination of disposable capacities. The decline in demand in china is much more than the decline in production.
 - gg) Measures imposed by EU and USA against china have further reduced their export market. This coupled with the fact of surplus capacities is likely to increase imports into India.
 - hh) There are significant capacities in EU which is much more than their own demand which results in higher export orientation. Even otherwise EU is a net exporter of the PUC as they export about 21% of their total production even after which they have unutilized capacities.
 - ii) For USA, the capacity is much more than their own demand which has already been facing a decline. About 17% of American paper industry's revenue is generated through export sales which are set to further rise in view of the declining demand.
 - jj) The increasing price undercutting with the decline in domestic industry's production indicates the looming threat of further low-priced imports. In fact, on decline of Indian production, the import prices should have shown declining undercutting. Such prices were below the actual and normated levels of the domestic industry resulting in depressing price effects.
 - kk) Government of China had specifically admitted in the EC finding that India was a more attractive market. The exports of EU and US producers also find the Indian market highly attractive in view of the declining demand in their home country and increasing demand in India.
 - ll) In view of the increased as well as significant import volumes, it would be right to assume that these producers can scale up their production in a short period.
 - mm) Post POI data derived from the anti-subsidy petition filed shows that the petitioner has enhanced production and is able to sell the product in the market but is still facing undercutting levels; it is still suffering from losses; profits, cash flow and the ROI continue to remain below levels achieved in the past and those considered reasonable by the authority. This evidences that despite increased production it suffers on account of profits, cash flow and ROI and the adverse price effect is only because of imports.
 - nn) If authority comes to a conclusion that there is a factor other than dumped import which also caused injury to the domestic industry, it is required to identify such factor and then quantify its impact and segregate the same from the data before analyzing injury information of DI. In the present case, factor brought to notice of the authority is reduction in production by petitioner due to other factors. The Authority has admitted that production of petitioner suffered because of other factors. It is required to consider entire data of petitioner, appropriately adjust the same and thereafter adopt it for injury analysis. Data is required to be adjusted considering loss of production suffered.
 - oo) Optimized costs were reported to the authority but the same have not been considered by the authority or injury analysis. Further while computation of NIP Authority has considered alleged inefficiencies of domestic industry and determined normated cost of production.
 - pp) Once authority considered the past level of capacity utilization, it is evident that the effects of other factors impacting production of the petitioner get fully addressed. The data presented by considering highest achieved capacity utilization and thereafter determining production, sales, profits, cash flow and ROI has been completely

ignored in the disclosure statement and actual information has been considered ignoring the requirements of causal link.

- qq) The WTO ADA provides that that dumping need not be the sole or to that extent even the principle cause of injury. The only legal requirement now is that dumping should be one of the causes of injury to the domestic industry.
- rr) Low priced imports forced the domestic industry to reduce its prices; the imports have been undercutting the prices of the domestic industry and are much below the cost of sales and selling prices of the domestic industry.
- ss) Duties should be imposed only as fixed quantum (fixed form of duty), expressed in US\$/MT. Such imposition of duties should be expressed in USD/MT.

K.2. Submissions by other interested parties

113. Following are the post-disclosure comments made by the other interested parties:

- a) There should be exclusion of Mechanical Coated and Clay Coated Kraft Paper as they are not produced by the Petitioner.
- b) Authority has not clarified as to which companies have been considered for injury determination as part of the “domestic industry”. It is unclear whether the “domestic industry” is only BILT, or now includes JK Paper and Seshasayee Paper also. By virtue of rule 2(b) of the AD rules, BILT does not fall under the purview of domestic industry due to the fact that it did not produce any of the PUC for a significant portion of the POI as stated by the Authority itself.
- c) There is no disclosure or determination made on the excessive claims of confidentiality made by the Petitioner nor is there any detailed explanation as to why Korea RP and Indonesia were excluded from the ambit of Subject Countries.
- d) In light of BILT’s low production, which is a part of their self-inflicted injury, the market must rely on imports to ensure that operations continue at optimum levels. The increase in imports is necessitated by the shutdown experienced by BILT as acknowledged by the Authority.
- e) The cost of the Petitioner has inflated substantially due to the plant shutdown experienced by BILT, whereby the cost is not appropriately reflective of the manufacturing cost in India. Since cost in the period of investigation is also a crucial (and biggest) component in the calculation of the NIP, the NIP calculated is in turn bound to be inflated egregiously and therefore would not be accurate or representative of the actual fair price that would remove any alleged injury to the Domestic Industry. It is requested to exclude the administration expenses which have been incurred after the shutdown of operations suffered by BILT as the same is inflated on account of low production and sales volume in the POI.
- f) The co-operating producers do not hold any significant inventory, no significant added capacities and that the increased import volumes are due to decline in production of the Domestic Industry. Thereby conclusively proving that there is no threat of material injury to the Domestic Industry.
- g) The AD rules at Annexure II (v) clearly state that there is an explicit onus on the Authority to consider the effect of “the volume and prices of imports not sold at dumping prices” while determining the extent of alleged injury to the Domestic Industry. This has not been done with regard to BILT.
- h) Economic Parameters of M/s. JK Paper Ltd. viz. Production, Capacity, Capacity utilization, Profitability, ROI, cash profits, Employment, Productivity and Inventories have all shown positive trends thereby showing that there is no existence of injury. Therefore, the injury suffered by the Petitioner (BILT) is self-inflicted and there is no causal link between imports from the EU and the performance of the Domestic Industry. Consequently, the injury margin can only be appropriately determined on the basis of fare selling price of JK Paper Ltd.
- i) The aegis of anti-dumping law cannot be used to protect a company, which suffered injury (on account of a plant shutdown) for reasons entirely unrelated to the subject imports, as confirmed by the fact that other local producers are seen to be doing well.
- j) In the absence of injury caused by dumped imports the imposition of anti-dumping measures cannot be in the overall interest of the Indian industry.
- k) The performance of the other domestic producer i.e. JK Paper clearly indicates that BILT is the only producer injured during the injury period; At Paragraph No. 108 of the Disclosure Statement, the imports of the PUC from the EU did not cause injury to the Indian domestic industry. The injury is only observed for BILT, and any injury of BILT was clearly self-inflicted and not attributable to imports from the EU.
- l) It must be noted that many prominent international publishers only use paper which has been given a Forest Stewardship Council (‘FSC’) certification. The Petitioner has stopped supplying FSC certified paper post their

shutdown and reopening. Hence, there is a need to import this paper when customers request FSC certified paper and make it a mandatory requirement in their requirement specifications.

- m) It is submitted that different product types, all falling within the scope of the PUC, have different uses and different rates especially when comparing GSM specifications or matt/gloss finishing therefore all determinations must be based on appropriate individual product type comparisons consistent with the past practice of the Hon'ble Designated Authority.
- n) Dee Dee Label, Supertech Papers Pvt. Ltd., Zalak Enterprise, Stiga Labels, Infinity Security Papers Ltd, Stay-On Papers Pvt. Ltd, Sri Industries, Mudra Arts (India) Pvt. Ltd. Chromaprint India Pvt. Ltd, Sai Packaging Company and Janus International Pvt. Ltd. made submissions for the first time after the issuance of the disclosure statement. They have submitted that few of them use CCK-Clay Coated Craft Paper, not for writing, printing or graphic purposes, but as a release base paper and others use wet strength paper, which is a one side coated paper, with special qualities that are specially required for labels for the beer and alcohol bottles. This paper is not domestically produced generally and by BILT in particular. It is imported by them under the HS Codes 48101300 and 48101900. They further submit that the HS codes for the coated papers being considered as PUC under this investigation are products that are beyond the ambit of the papers being considered in this investigation. Considering them as PUC will lead to a lot of difficulties for them and other manufacturers, since they are not produced in India.
- o) UFLEX Limited made submissions for the first time after the issuance of the disclosure statement. They have submitted that there are two specific grade of packaging paper used for Liquid Packaging application viz. 70-75 GSM (uncoated & coated) and 130-170 GSM (uncoated & coated), neither of which is domestically produced.
- p) SMI Coated Products Private Limited and the Newsprint Trading & Distributing Corporation Ltd. made submissions for the first time after the issuance of the disclosure statement. They have submitted that the HSN Codes mentioned in the petition cover products that are not produced or produced in insufficient quantities in India. Since, the domestic manufacturers are incapable of sufficiently meeting the demands of the print industry, imports of the same are required.
- q) Advik enterprises made submissions for the first time after the issuance of the disclosure statement. They have submitted that BILT was shutdown or operational with limited capacity during almost the entire duration of the investigation and it is unjustified to impose anti-dumping duty on other foreign suppliers. As such, doing so would give local manufacturers an opportunity to exploit the local customers and traders. Therefore, keeping the interests of the customers, the authority is requested not to impose the anti-dumping duty.
- r) Shree Ashtavinayak Papers Pvt. Ltd. made submissions for the first time after the issuance of the disclosure statement. They have submitted that the monthly demand of Coated Paper in India is appx. 60,000 MT and that the local capacity of production amounts to around 16,000 to 20,000 MT. As such, the gap in demand and production can be fulfilled by imports only.
- s) Ganesh Paper Agencies made submissions for the first time after the issuance of the disclosure statement. They have submitted that BILT produced a wide range of products and coated paper and board may have constituted only 15-20% of it. Therefore, its injury cannot be blamed on the imports of paper and board.
- t) Venus Paper Corp. made submissions for the first time after the issuance of the disclosure statement. They have submitted that paper industry in India only produces about 30% of the total paper consumption and the rest is imported. Indian mills, like Ballarpur Industries Ltd, themselves import pulp for their needs. That introduction of the duties will result in the increase in the cost of the paper and its products and will affect local and export businesses.
- u) Jana Agencies Paper Corp., Raj Paper Traders, Purnima Distributors and Kaveri International made submissions for the first time after the issuance of the disclosure statement. They have submitted that there is always a short supply of coated paper in our country. Only Ballarpur Industries Ltd. and JK Paper Ltd. manufacture them in India. JK Paper itself imports coated paper on a large scale to satisfy the demand and Ballarpur also had been doing so till a while ago. The domestic production accounts for only 35% of the total market requirement. Though, the market in the country is expanding on a yearly basis and simultaneously no capacity building in production has taken place. That imposition of the duty will result in the monopoly of BILT in the industry. This might result in great loss to the small and medium printers who will not be able to bear the price increase. Many of them depend on this for their livelihood. Therefore, anti-dumping duties will have an adverse effect.
- v) Juneja Trade Links made submissions for the first time after the issuance of the disclosure statement. They have submitted that the domestic mills are not able to match the quality of the imported products.
- w) Sumat Pershad & Sons made submissions for the first time after the issuance of the disclosure statement. They have submitted that since paper under chapter 48 covers about 100s of paper family products, BILT has to specifically declare its product mix of 2/s coated paper product mix of 90, 100, 15, 118, 200 130, 150 200, 220,

250 300 various grammage they are producing, separately for Matt and Gloss finish/Reel & Sheets. They have to clearly state production according to HSN codes by them & other domestic producers. Authority should get the exact and clear information from the petition as to what they are having product mix and under different plants and under different HSN code. If BILT specifies their product HSN Code, then JK Paper will be the only member of IPMA left who manufacture the product in question who is the regular importer also? In order to mislead, BILT has only mentioned the 4-digit HSN code as against the 8-digit code. Therefore, imposing the duty will harm a lot of small and local businesses which is against the dream of “Make in India” by not putting machines to meet the domestic demands and adopting a monopolistic approach.

- x) Federation of Paper Traders’ Association of India made submissions for the first time after the issuance of the disclosure statement. They have submitted that JK Paper has not suffered any injury. The fact that its performance improved consistently despite the increase in imports, clearly indicates that imports are not the cause of the injury to the domestic industry. On the contrary, imports ensured continuous supply of the same. The demand is growing, and the lead time would be abnormal if supplies are to be taken only from the domestic manufacturers. They further submit that Anti-dumping duty cannot be imposed to protect a domestic industry whose economic situation has deteriorated for reasons that are in no way connected to imports, as is clearly the case of the petitioner and its long production shutdown. Therefore, fair-trade practice should be adopted rather than a monopolistic approach.

- y) Notwithstanding the infirmities with the NIP determination, it is submitted that NIP determined based on information provided by BGPPL is unreliable. In the anti-dumping investigation concerning import of Uncoated Paper from Indonesia, Thailand & Singapore, BGPPL was one of the applicant domestic producer but the Authority excluded BGPPL from the scope of domestic industry. The Authority in paragraph 11 of the final findings determined that:

The Authority notes that BGPPL was not producing the subject goods for a major part of the POI due to its own internal reasons. Therefore, it would not be appropriate to consider BGPPL as a part of the DI for assessment in the present investigation.

- z) The POI in the present investigation is same as the POI in the anti-dumping investigation on uncoated paper. Respondents request the Authority to follow its consistent approach in the present investigation as well and not rely on the cost of sales & non-injurious price determined by the Authority based on the data of BGPPL. Consequent determination of price undercutting, price underselling and price suppression/depression is also not reliable for determining material injury and causal link.

- aa) In any case, it is settled that the Authority cannot rely on existence of injury margin to determine that there is material injury. The Gujarat High Court in the matter of Nirma Ltd. v. Union of India [Special Civil Applications No.16426/2016 & 16427/2016] held that:

34. It may be noted that injury margin is required to be determined when the designated authority comes to the conclusion that there is material injury requiring imposition of anti-dumping duty, whereupon the quantum of anti-dumping duty to be levied is based upon the injury margin. Therefore, determination of injury margin would come into play only in case the designated authority comes to the conclusion that determinative measures are required to be applied. Where the designated authority comes to the conclusion that no determinative measures are required to be imposed, as in the present case, the question of determining the injury margin would not arise.

- bb) The selling price of BGPPL is either equal to or higher than the non-injurious price determined by the Authority. BGPPL is able to maintain its selling price at the level of non-injurious price determined by the Authority and is not suffering any price suppression due to imports from subject countries.

- cc) The economic parameters of JK Paper disclosed in the disclosure statement demonstrate that there is no material injury to JK Paper Ltd. There is no causal link between the decline in performance of BGPPL during the POI and the imports from subject countries. If imports were responsible for decline in performance of the BGPPL, then it would have also affected performance of JK Paper Ltd. The Authority has itself observed that increase in imports from subject countries was necessitated due to decline in production of BGPPL. Thus, Respondents request the Authority to exclude the performance of BGPPL during the POI for assessment of material injury and consider performance of JK Paper for assessment of material injury. In any case, even if the Authority considers the economic parameters of BGPPL for assessment of material injury then the Authority should conclude that there is no causal link between increase in imports and material injury to the domestic industry.

- dd) The authority has issued the disclosure statement without recording the respondents’ critical submissions pertaining to domestic industry standing, factors affecting profitability of BGPPL, injury being suffered by the domestic industry and causal link analysis. The respondents submit that the disclosure statement has not given an effective opportunity granted to the respondents in terms of Rule 16. The respondents rely on Oil and Natural Gas Corporation Ltd. vs. Western Geco International Ltd., (2014) 9 SCC 263, to state that a decision cannot be

passed by the authority without hearing all the arguments as it is a quasi-judicial body. This decision would be against the principles of natural justice and would also suffer from the fatal defect of non-application of mind.

- ee) In the disclosure statement, the Authority has made adjustments on account of “Non-Refundable VAT” while calculating the ex- factory exports price of the responding exporter. There is no input VAT on the goods imported under processing trade for the purpose of exports. Therefore, the adjustment made on account of “Non-Refundable VAT” is erroneous and should be corrected.
- ff) The responding parties submit that as per Article 2.2 of the WTO agreement on anti-dumping the normal value and export price are to be compared at the equal level of trade. However, in the present case while adjustments have been made towards “Packing Charges” in NEP “Packing Charges” have been included while calculating the Constructed Normal Value. This would be in violation of the WTO agreement on anti-dumping. Thus, the respondents request the authority to confirm that “Packing Charges” should not be taken in consideration while determining the Constructed Normal Value.
- gg) BGPPL suffered as two strategic asset sales of the Company did not materialize. Consequently, the expected improvements in the balance sheet position did not happen and the financial condition of the Company was put under further stress. Other reasons for stress on BGPPL are that wood prices have gone up steeply, more than doubling in the last three to four years which, in turn, has seriously affected competitiveness of the Indian paper industry, increasing cost of raw material and energy, Government of India’s policy of extending preferential tariff treatment to paper and paperboard under the free trade agreements (FTAs).
- hh) Factors relevant for causal link are, increase in imports from subject countries, which was necessitated due to decline in production of the domestic industry, shutdown of the plant for a significant period during the POI. Due to shut down of BGPPL during the POI, cost of sales increased more than selling price. Thus, there is no causal link between injury and imports from subject countries. The applicant purposefully excluded JK Paper from the purview of domestic industry to distort performance indices. The shutdown of petitioner’s plant coincided with the period of loss. Thus, the entire domestic industry experienced a sudden decline, which had nothing to do with imports.

K.3. Examination by the Authority

- 114. The Authority notes the submissions made by various parties some of which are repetitive in nature and were addressed in the disclosure statement. To the extent fresh arguments have been made and considered relevant, the specific issues have been dealt at appropriate places in the findings above. The Authority has examined submissions of interested parties herein below to the extent relevant and not addressed elsewhere.
 - (i) As regards the submission that the Authority should disclose essential facts that form the basis of its findings and conclusion, it is observed that the Authority had disclosed all essential facts under consideration in terms of Rule 16 of the AD Rules to all the parties concerned.
 - (ii) With regard to the submissions concerning clarity for the standing/constitution of the domestic industry, the Authority holds that the petition was filed by Indian Paper Manufacturers Association on behalf of domestic industry, M/s. BILT Graphic Paper Products Ltd, which is a producer of the subject goods in India and constitutes the domestic industry for the purpose of the present investigation. In the petition, it was stated that there is one more known domestic producer of the product under consideration, namely, JK Paper Limited. The data provided by JK Paper Ltd. has been used for the limited purpose of causal link analysis between injury and dumping.
 - (iii) As regards the submissions of the domestic industry regarding exclusion of coated paper below 80 GSM the Authority notes that the domestic industry itself excluded lightweight coated paper from the scope of product under consideration. In addition, during the verification of the domestic industry, the Authority had specifically discussed this issue and it was informed that Domestic Industry does not produce double side coated paper below 75 GSM. Accordingly, the Authority excludes double sided coated paper below 75 GSM and lightweight coated paper from the scope of product under consideration.
 - (iv) As regards the submission that NIP for the JK Paper has not been determined, the Authority holds that determination of NIP for JK paper is not required as it is not a part of the domestic industry as mentioned at appropriate places in the present findings. The Authority has determined NIP for the domestic industry as per Annexure-III to the AD Rules.
 - (v) As regards the contention of the Domestic Industry that JK paper data/information has been used on convenience basis, the Authority notes that the facts of the present case are unique as plant of the Petitioner i.e. M/s. BILT Graphic Paper Products Ltd. was shutdown for a significant period during the period of investigation. In order to conduct a proper causal link analysis, it was necessary to analyse data of JK paper, which is the only other major producer of PUC. At the time of seeking additional information itself from JK Paper, it was informed to them that because of the peculiar facts of the present case (wherein the petitioner was

shutdown for a major part of the POI) information was being sought from JK Paper in order to conduct an appropriate injury and causal link analysis.

- (vi) As regards the belated submissions made by several traders/importers/users/association for the first time at post disclosure stage with respect to the scope of product under consideration, the Authority notes that these PUC exclusion related issues have been raised for the first time and that too at this belated stage of post disclosure comments. It is not possible for the Authority to examine all such PUC exclusion related issues afresh at such a belated stage. However, the authority has tried its best to address most of the PUC exclusion issues, to the extent possible, based on the records available with the authority. Accordingly, the authority excludes Electrical Kraft insulation paper, Kraft paper, Kraft insulation paper and insulating paper from the scope of PUC.
- (vii) As regards the contention of the interested parties that injury margin determined on the basis of data of BGPPL is unreliable and the same should be done on the basis of the data provided by JK Paper Ltd., the Authority notes that the injury margin is to be determined based on the NIP calculated for the domestic industry. As discussed above, BGPPL is the domestic industry in the present case and accordingly NIP has been determined in terms of Annexure III to the AD Rules for BGPPL.
- (viii) As regards the contention of the domestic industry for the verification of information provided by M/s. JK Paper Ltd., the Authority notes that it has considered the data provided by JK Paper Ltd. in the present final findings as such and no changes have been made in the data provided by them. It is not necessary for the Authority to verify the data of each and every interested party so long as the Authority is satisfied with the information provided by an interested party. As regards the contention of the interested parties as to why Korea RP and Indonesia were excluded from the ambit of subject countries, the Authority notes that this issue had been clarified in the initiation notification itself wherein it was clearly mentioned that Authority prima facie found absence of dumping on imports of subject goods from Indonesia and Korea RP for the period of investigation.
- (ix) Some parties have submitted that they import coated paper under tariff items 48101300 and 48101900 and that the domestic industry is not manufacturing the products falling under these tariff items. The Authority notes that under the customs tariff of India no such tariff items (48101300 and 48101900) exists and therefore submissions of the interested parties is devoid of any merits.
- (x) As regards the contention of the interested party that the adjustment made on account of “Non-Refundable VAT” in determining ex-factory export price in case of processing trade is incorrect, the Authority does not agree with the submission made by them. The Authority notes that adjustment for non-refundable VAT is required to be done even in case of processing trade and the formula for the same is $\text{FOB value} \times (17\% - \text{refunded rate}\%) \times (1 - \text{planned distribution ratio}\%)$ and it was therefore incumbent upon the concerned interested party to provide the requisite details.
- (xi) With regard to the issue raised relating to the adjustment of the packing charges in both normal value and the export price, it is noted that appropriate adjustment has been made for fair comparison as per the consistent practice followed by the authority.
- (xii) With regard to the domestic industry’s contention that imposition of AD/ CV duty on coated paper by EU and USA against imports from China PR has created a threat of significant imports coming from China PR to India, the Authority notes that the imposition of impugned duties by EU and USA is not a recent development and has actually been in force for quite some time (in US since 2010 and in EU since 2011). Accordingly, the submission of the Domestic Industry is devoid of any merit.
- (xiii) As regards the request of the domestic industry for disclosure of DGCI&S data adopted for the investigation, it is noted that the same has been placed in the public file and can be accessed by all the interested parties after following the due procedure.

L. CONCLUSION

- 115. Keeping in view the mandate of the Customs Tariff Act and AD rules, relevant submissions made by various interested parties and facts available before the Authority; the authority concludes as under:
 - i) There is substantial increase in imports of subject goods from subject counties in absolute terms as well as in relation to production & consumption in India. However, the increase in imports from subject countries was necessitated due to decline in production of the domestic industry.
 - ii) The selling price of the domestic industry during POI was higher than the NIP determined by the Authority. It demonstrates that the dumped imports from the subject countries did not stop the domestic industry from realising a fair price for their product during the POI.
 - iii) Capacity of the domestic industry remained constant since 2013 – 14. Capacity utilisation and production of the domestic industry improved till 2015-16 and have declined during the POI (A) due to the fact that the Domestic

Industry was not operational for a major part of POI. On the other hand, capacity utilisation, production and domestic sales of JK Paper Ltd. have improved during the POI (A).

- iv) Profit before interest and cash profits of domestic industry have been stable till 2015 – 16 and have declined during the POI (A). On the other hand, profit before interest and cash profits of JK Paper Ltd. have improved during POI (A).
- v) Having evaluated the threat of material injury, the Authority notes that imports from the subject countries had no price depression/suppression effect on the domestic country. The Authority further notes that no significant capacity has been added by any of the co-operative producers and none of the co-operative producers/exporters from subject countries hold any significant inventory, which consequently does not establish the threat of material injury.
- vi) The fall in production, sales, capacity utilisation and profitability of BGPPL is clearly attributable to its own intrinsic factors and has no co-relation with the dumped imports from the subject countries.
- vii) The consequent impact of dumped imports on the domestic industry performance is therefore absent. It cannot thus be conclusively established that the domestic industry suffered injury during POI as a result of dumped imports from the subject countries.

M. RECOMMENDATIONS

- 116. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal links. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the authority notes that there is no causal link between the dumped imports from the subject countries and injury to the domestic industry due to the reasons given above and therefore does not consider it appropriate to recommend levy of Anti-Dumping Duty on the subject goods from China PR, European Union and USA. Therefore, in terms of Section 9A and 9B of the Customs Tariff Act read with Rule 14 (b) and Rule 17(1)(a)(iii), Rule 11(2) and para v of Annexure II of the Anti-Dumping Rules, the Designated Authority decides to terminate the present investigation which was initiated vide Notification No. 6/42/2017 -DGAD dated 23rd January, 2018.

N. FURTHER PROCEDURE

- 117. An appeal against this notification shall lie before the Customs, Excise, and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 and the decision of the Hon'ble High Court of Delhi in M/s Jindal Poly Film Ltd. v. Designated Authority W.P. (Civil) No. 8202/2017.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. and Director General